RNI NO. DELHI/2012/48369
वर्ष 8 अंक 319
नई दिल्ली, शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

एली गोल्डिंग में थी आत्मविश्वास की कमी
विविध-12

www.dailypioneer.com

आज बंद, एक तारीख से रेल का चक्का जाम

● पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के किसान संगठन विरोध प्रदर्शन को देंगे धार

● रेलवे ने ऐहतियातन 24 से 26 तक स्थगित कीं 26 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही

कृषि बिलों के खिलाफ भड़का किसान आंदोलन

पटियाला में गुरुवार को रेल ट्रैक पर जमे किसान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

पंजाब में किसान संगठनों ने तीन कृषि सुधार विधेयकों के विरोध में गुरुवार से तीन दिवसीय रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है, जबकि अन्य ने 25 सितंबर को राष्ट्रव्यापी बंद तथा अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन 1 अक्टूबर से शुरू करने का आह्वान किया है।

किसान नेताओं के मुताबिक इस दौरान सड़कों, राजमार्गों और रेल ट्रैक को रोक दिया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के किसानों ने किसान आंदोलन में शिरकत करने का फैसला किया है। कांग्रेस, जिसकी चार राज्यों में सरकार है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, केरल में वाम, दिल्ली में आप, तेलंगाना में टीआरएस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी समेत 18 राजनीतिक दलों का भी समर्थन किसानों को हासिल है।

आल इंडिया ट्रेन यूनियन कांग्रेस, नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस, सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन्स, हिंद मजदूर सभा, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर और ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का समर्थन किया है। ओला कैब ड्राइवर्स एसोसिएशन और लॉरी डाइवर्स एसोसिएशन ने किसानों का समर्थन करने का फैसला किया है तथा शुक्रवार को वे वाहन नहीं चलाएंगे। इस बीच, कई सोशल मीडिया यूजर्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि एनसीबी ने ड्रग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को 25 सितंबर को बुलाया है और उसी दिन किसान देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। सोशल मीडिया में ये अटकलें जोरों पर हैं कि यह कदम लोगों को ध्यान भटकाने का एक तरीका हो सकता है।

बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे ने 26 जोड़ी विशेष ट्रेनों और नौ पार्सल ट्रेनों का संचालन 24 से 26 सितंबर तक के लिए रोक दिया है जबकि 20 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया और पांच की गंतव्य से पहले ही यात्रा समाप्त कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि जो ट्रेनें नहीं चलेंगी उनमें गोल्डन टेंपल मेल (अमृतसर-मुंबई सेंट्रल), जनशताब्दी एक्सप्रेस (हरिद्वार-अमृतसर), नई दिल्ली-जम्मू तवी, कर्मभूमि (अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी), सचखंड एक्सप्रेस (शेष पेज 9)

बिल छोटे किसानों के हक में बदल जाएगी जिंदगी : तोमर

● कांग्रेस पर दोमुंही राजनीति और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि कृषि विधेयक 'छोटे किसानों के हित' के साथ निवेशकों के पक्ष में भी है और ये पूरी तरह से उनके जीवन को बदल देंगे। तोमर ने कहा संसद द्वारा पारित विधेयक किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे क्योंकि वे अपने उत्पादों को किसी भी खरीदार को बेच सकेंगे और अपनी फसल के लिए उन्हें गारंटीशुदा मूल्य मिलेगा, विविध फसल उपजा सकेंगे, नई तकनीक का इस्तेमाल तथा लागत को कम कर सकेंगे। भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों से मंडी में 8.5 फीसदी कर वसूला जाता है और वे कम कीमत पर अपनी उपज को बेचने पर मजबूर हैं। उन्हें अपनी उपज को मंडी तक ले जाने के लिए परिवहन का भाड़ा भी वहन करना पड़ता है। मंत्री ने कहा कि हमने उन्हें इस बात की आजादी दी है कि वे अपने उत्पादों को मंडी के बाहर बेच सकते हैं, जहां पर उनसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा टैक्स नहीं वसूला जाएगा। सिंह ने कहा, 'किसान अपनी उपज को लेकर मंडी जाते हैं। इन मंडियों में 25-30 लाइसेंस वाले लोग होते हैं। वे उपज की बोली लगाते हैं। कीमत बोली के (शेष पेज 9)

भारत में रोज पूरे एशिया से दो गुना ज्यादा केस

● महाद्वीप के अन्य देशों में स्थिति संभली, पर यहां हफ्ता दर हफ्ता हालात हो रहे बदतर

● यूरोप से डेढ़ गुना और अफ्रीका से दस गुना अधिक मरीज

नवीन उपाध्याय। नई दिल्ली

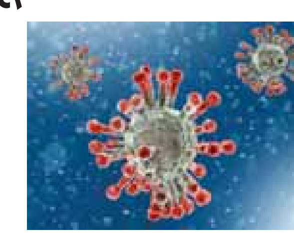

लॉकडाउन लागू होने के छह महीने बाद भारत कोरोना का सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। स्थिति कितनी खराब हो चुकी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में रोज पूरे एशिया की तुलना में दोगुने और यूरोप के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक केस आ रहे हैं। इन दोनों महाद्वीपों में 100 से अधिक राष्ट्र हैं।

यही नहीं, भारत में रोजाना कोरोना केसों में बढ़ोतरी भी 57 अफ्रीकी देशों की तुलना में दस गुना अधिक है। जब पहली बार 25 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया था, उस समय देश में 500 से कम कोविड-19 मामले थे और इसका नंबर दुनिया भर में सबसे नीचे था। छह महीने बाद कोरोना के मामले लगभग 60 लाख हो चुके हैं और संक्रमण प्रभावित देशों की सूची में इसका नंबर दूसरा है। पहले स्थान पर अमेरिका है। इसी अवधि के दौरान भारत को छोड़कर अन्य सभी एशियाई देशों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की है। गुरुवार को जब भारत में लगभग 87,000 मामले दर्ज किए गए, 48 एशियाई देशों में मिलाकर सिर्फ 40,000 कोरोना मरीज ही आए। भारत के करीबी पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल को ही लें तो यहां क्रमशः 1666, 533, 11 और 1,172 मामले दर्ज किए गए। भारत के बाद एशिया में सबसे ज्यादा करीब 43 लाख केस ईरान में हैं। इसके बाद बांग्लादेश, इराक, सऊदी अरब और तुर्की का नंबर आता है जहां तीन लाख से अधिक केस हैं।

पाकिस्तान में इस समय कोरोना के 3,07418 मरीज हैं। ताजा रुझान देखने से पता चलता है कि कम से कम दस एशियाई देशों में गुरुवार को एक भी नया मरीज सामने नहीं आया और 15 देशों में नए रोगी दोहरे अंक में ही आए हैं। यूरोप की बात करें तो यहां कोरोना की दूसरी लहर जोर मार रही है और इसी को देखते हुए नए सिरे से लॉकडाउन की चर्चा शुरू हो गई है। भारत की स्थिति इसलिए ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि यहा हफ्ता दर हफ्ता केस में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। सप्ताहंत या अन्य कारणों से कम टेस्ट होने पर ही यहां कोरोना मामलों की संख्या कम दर्ज की जाती (शेष पेज 9)

कोविड-19 से कर्नाटक के कांग्रेसी विधायक की मौत

पायनियर समाचार सेवा। बेंगलुरु

कोरोना वायरस की चपेट में आने से यहां कांग्रेस विधायक बी नारायण राव (65) का गुरुवार को निधन हो गया। मणिपाल अस्पताल के निदेशक डॉ. मनीष राय ने अपने बयान में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद उत्तरी कर्नाटक के बीदर जिले की बसावा कल्याण सीट से विधायक राव को एक सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मुताबिक अपराह्न 3 बजकर 55 मिनट पर राव ने अंतिम सांस ली। राय ने कहा कि राव के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी हालत नाजुक थी। विधायक वेंटिलेंटर पर थे और विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रहा था। उल्लेखनीय है कि बुधवार को रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का भी कोरोना वायरस के संक्रमण से निधन हो गया था। उनकी उम्र 65 वर्ष की थी और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था।

दीपिका और सारा पहुंचीं मुंबई कल होगा एनसीबी से सामना

● अभी जेल में ही रहेंगी रिया चक्रवर्ती, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 29 सितंबर तक टाली सुनवाई

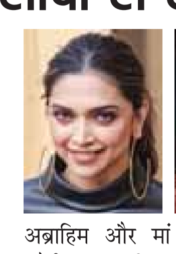

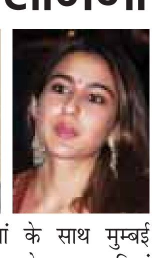

पायनियर समाचार सेवा। मुंबई

बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और सारा अली खान गुरुवार शाम गोवा से मुम्बई लौट आई हैं। दीपिका गोवा में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं जबकि सारा छुट्टियां मनाने वहां गई थीं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में एनसीबी ने दीपिका और सारा को शनिवार को पेश होने का नोटिस दिया है। इसी मामले में रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर का भी एजेंसी के अधिकारियों से आमना-सामना होगा। दीपिका अपने पति रणवीर सिंह, मैनेजर करिश्मा प्रकाश समेत लीगल टीम में शामिल तीन लोगों के साथ चार्टर प्लेन से मुंबई पहुंचीं। मषहूर एक्टर सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी नवोदित अभिनेत्री सारा अली खान अपने भाई अब्राहिम और मां के साथ मुम्बई लौटी। वह परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गोवा गई थीं। एनसीबी दोनों अभिनेत्रियों से 26 सितंबर को पूछताछ करेगी। दूसरी ओर, बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को अभी 29 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। रिया को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत से जुड़े ड्रग मामले में ही 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से वह मुम्बई की भायखला जेल में बंद हैं। उन्हीं से पूछताछ के बाद फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग के फैले जाल का खुलासा हुआ था। उन्होंने ड्रग लेने या इस धंधे से जुड़ी 25 बड़ी बॉलीवुड हस्तियों के नाम एनसीबी को बताएं हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, नम्रता शिरोडकर आदि इसी कड़ी का हिस्सा हैं।

उप्र में छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के आरोपियों के लगेंगे पोस्टर

● बढ़ते महिला अपराध पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला

● महिलाओं के साथ आपराधिक घटना होने पर संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ होंगे जिम्मेदार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यूपी में महिला अपराधों को बढ़ते मामलों को देखते हुये योगी सरकार फिर सख्त हो गई है। आपरेशन मजनू की तर्ज पर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की शामत आएगी। दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफसरकार ऑपरेशन दुराचारी चलाने जा रही है। सीएम ने ऐसे अपराधियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाने का आदेश दिया है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले अपराधियों को महिला पुलिस कर्मियों से ही दंडित कराओ। ऐसे अपराधियों और दुराचारियों के मददगारों के भी नाम उजागर करने का आदेश दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वालों को समाज जाने, इसलिए चौराहों पर ऐसे अपराधियों के पोस्टर लगवाएं। योगी ने महिलाओं, बच्चियों से छेड़खानी, दुर्व्यहार, अपराध और यौन अपराध में लिप्त अपराधियों के पोस्टर शहर के सार्वजनिक स्थानों पर लगाने का आदेश दिया है, ताकि ऐसे लोगों को समाज के सामने लाकर शर्मिंदा किया जा सके। उन्होंने सख्ती से कहा कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेदार होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब नागरिक संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले उपद्रवियों के पोस्टर की तरह ही मनचलों, शोहदों और दुराचारियों के पोस्टर पूरे शहर में लगेंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन दुराचारी के तहत होने वाले इस कार्रवाई की जिम्मेदारी महिला पुलिसकर्मियों को दी गई है। ये महिला पुलिसकर्मी ऐसे शोहदों और मनचलों की पहचान कर उनके पोस्टर को शहर के चौराहों और सार्वजनकि स्थलों पर लगवाएंगी।

कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर की आशंका से सेंसेक्स धड़ाम

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण का दूसरा दौर शुरू होने की आशंका, वैश्विक बाजारों में भारी बिकवाली और विदेशी फंड में जबर्दस्त निकासी से शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। केंद्रीय बैंकों की ओर से अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने के लिए प्रोत्साहन की कोई नई घोषणा नहीं होने से बाजारों की धारणा प्रभावित हुई और, गुरुवार को सेंसेक्स औंधे मुंह गिर गया।

इसमें 1,115 अंक की जोरदार गिरावट दर्ज की गई वहीं निफ्टी 326 अंक लुढ़क गया। घरेलू मोर्चे पर रुपए में भारी गिरावट तथा शेयर बाजार में वायदा एवं विकल्प खंड में निपटान कारोबार की वजह से भी बाजार में जोरदार गिरावट आई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स कमजोर रुख के साथ खुलने के बाद और नीचे गया। अंत में यह।,114.82 अंक या 2.96 प्रतिशत के नुकसान से 36,553.60 अंक पर बंद हुआ। चार मई के बाद यह सेंसेक्स में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट (शेष पेज 9)

दिल्ली में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पीक पर: मुख्यमंत्री

● विशेषज्ञों ने दिए संकेत, आने वाले दिनों में कम होंगे संक्रमण के मामले : केजरीवाल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कोविड-19 संक्रमण में तेजी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर चल रही है और, यह अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में संक्रमण के मामले घटेंगे।

उनकी सरकार को भी पूरा भरोसा है कि उसके द्वारा उठाए गए कदमों से कोरोना केस धीरे-धीरे कम होते जाएंगे। केजरीवाल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के एक एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली पहले से ही कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही है। इस महीने यहां अचानक कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने लगे और रोजाना सामने आने वाले मामलों की संख्या चार हजार को पार कर गई। दरअसल यह इसकी दूसरी लहर थी और विशेषज्ञों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि इसका पीक गुजर चुका है। गौरतलब है कि इस लिहाज से दिल्ली ऐसा पहला राज्य है जहां कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई है।

केजरीवाल के मुताबिक, पिछली एक जुलाई से 17 अगस्त के बीच राजधानी में रोजाना औसतन 1,100 से 1,200 नए कोरोना मामले सामने आ रहे थे यानी, कुल मिलाकर संक्रमण नियंत्रण में था। 17 अगस्त से मामलों में थोड़ी बढ़त दर्ज की गई और यह प्रतिदिन 1,100 से बढ़कर 1,500 हो (शेष पेज 9)

बाजार

सेंसेक्स	36,553	↓	1114	
निफ्टी	10,805	↓	326	
सोना	50,418	↓	485	/10g
चांदी	58,099	↓	2081	/kg

क्विक न्यूज

बेंगलुरु हिंसा का मुख्य षड्यंत्रकर्ता गिरफ्तार

बेंगलुरु, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 11 अगस्त को बेंगलुरू में एक पुलिस थाने पर हुए हमले के एक कथित षड्यंत्रकर्ता सैयद सादिक अली को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियो ने यह जानकारी दी। बेंगलुरु निवासी अली (44) फरार चल रहा था। वह केजी हल्ली पुलिस थाने पर हमले में कथित तौर पर संलिप्त था, जिसके चलते पुलिस थाना परिसर में और आसपास के इलाके में खड़े वाहनों सहित सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। जांच एजेंसी ने बताया कि 11 अगस्त को 3,000 से अधिक लोगों ने हिंसक तरीका अपनाते हुए कांग्रेस विधायक आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनकी बहन जयंती और देवारा जीवनहल्ली के आवासों तथा कडुगोंडनहल्ली(केजी) पुलिस थाने को आग लगा दी थी।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स का मुंबई में निधन

पायनियर समाचार सेवा। मुंबई

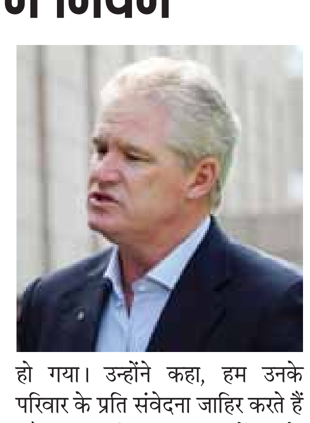

एकदिवसीय क्रिकेट के शानदार बल्लेबाजों में शामिल रहे आस्ट्रेलिया के डीन जोन्स का गुरुवार को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जोन्स इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के लिए स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम का हिस्सा थे और मुंबई में थे। वह 59 बरस के थे। जोन्स शहर के एक होटल में जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में थे।

उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटियां हैं। जोन्स ने आस्ट्रेलिया की ओर से 52 टेस्ट और 164 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। वह 1987 विश्व कप जीतने वाली आस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे। स्टार स्पोर्ट्स ने विज्ञप्ति में कहा, बेहद दुख के साथ हम डीन मर्विन जोन्स एएम के निधन की खबर साझा कर रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्होंने कहा, हम उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करते हैं और इस मुश्किल समय में उनके सहयोग के लिए तैयार हैं।

जरूरी इंतजाम करने के लिए हम आस्ट्रेलियाई उच्चायोग के संपर्क में हैं। आईपीएल सूत्रों के अनुसार यह सब कुछ सेकेंडों में घटित हो गया। सूत्र ने कहा, डीनो होटल की लॉबी में खड़ा था और अचानक गिर पड़े। ब्रेट ली उनके साथ खड़े थे। ब्रेट ने सीपीआर देकर (शेष पेज 9)

मोदी ने दिया-'फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज' का मंत्र

फिट इंडिया अभियान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

फिटनेस को लेकर क्रिकेटर विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन से संवाद करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ तन बेहद जरूरी है। इस बारे देश को संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है, जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम व परिश्रम से हमेशा स्वस्थ रहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 'फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज', मंत्र में सभी का स्वास्थ्य और सभी का सुख छिपा हुआ है। 'फिट इंडिया अभियान' की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस को लेकर जागरूकता का प्रसार करने वाले लोगों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। संवाद करने वाले लोगों में भारतीय क्रिक्रेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन और मशहूर डायटीशियन रुजुता दिवेकर के अलावा फिटनेस के प्रति उत्साही आम नागरिक शामिल थे। मोदी ने आज के संवाद को हर आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी करार देते हुए कहा कि एक साल के भीतर 'फिट इंडिया अभियान' आमजन का अभियान बन चुका है तथा देश में स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर निरंतर जागरूकता में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। उन्होंने कहा, 'फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है कि वाकई में फिट रहना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। 'फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज', इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य और सभी का सुख छिपा हुआ है।' उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबाल, कराटे हो या कबड्डी, उन्हें जो पसंद आए कम से कम 30 मिनट रोज करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसार में श्रम, सफलता, भाग्य, सब कुछ स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। उन्होंने कहा, 'स्वास्थ्य है, तभी भाग्य है, तभी सफलता है। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, खुद को फिट और मजबूत रखते हैं।

एक भावना जागती है कि हां, हम स्वयं के निर्माता हैं। एक आत्मविश्वास आता है और व्यक्ति का यही आत्मविश्वास उसको जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में भी सफलता दिलाता है। यही बात परिवार समाज देश पर भी लागू है।' कोहली, सोमन और दिवेकर के अलावा इस सत्र में पैरालम्पिक भालाफेंक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झझारिया और जम्मू कश्मीर की महिला फुटबॉलर अफशां आशिक ने भी भाग लिया। श्रीनगर में 2017 में पत्थरबाज के तौर पर सुर्खियों में आई अफशां से भी प्रधानमंत्री ने बात की।

जम्मू-कश्मीर फुटबॉल टीम में गोलकीपर अफशां बाद में एफसी कोल्हापुर सिटी के लिये भारतीय महिला लीग 2019 में खेली। वह श्रीनगर में युवाओं को प्रशिक्षण भी देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर निरंतर जागरूकता भी बढ़ रही है और सक्रियता भी। उन्होंने बेहद खुशी जताई कि योग, आसन, व्यायाम, पैदल चलना, दौड़ना, तैराकी, स्वस्थ खाने की आदत और एक स्वस्थ जीवन शैली लोगों के जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। फिट इंडिया अभियान से ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुड़ने का आग्रह करते हुए (शेष पेज 9)

ई-पीटीएम में 70 हजार विद्यार्थियों व अभिभावकों ने लिया हिस्सा

जिले के करीब 700 स्कूलों में आयोजित की गई ई-पीटीएम

पंकज शर्मा। करनाल

महामारी के बीच जिले में मेगा ई पीटीएम आयोजित की गई। पीटीएम में जिले के करीब 700 स्कूलों के 70 हजार विद्यार्थी व अभिभावकों ने हिस्सा लिया। ई-पीटीएम के माध्यम से विद्यार्थियों व अभिभावकों ने उपायुक्त के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि महामारी के काल में भी ई-पीटीएम एक अच्छा प्लेटफार्म है।

उपायुक्त ने सभी अभिभावकों व बच्चों को आश्वासन दिलाया कि आगे भी यह कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं, विद्यार्थी घर पर ही टीवी, स्मार्टफोन व अन्य माध्यमों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लॉकडाऊन में विद्यार्थियों ने क्या किया और अभिभावकों का क्या रुझान है, इसकी जानकारी के लिए गुरुवार को मेगा ई-पीटीएम आयोजित की गई। पीटीएम में अभिभावकों व विद्यार्थियों से बातचीत की। विद्यार्थियों व अभिभावकों ने भी उपायुक्त व जिला शिक्षा अधिकारी रविन्द्र चौधरी के साथ अपने अनुभव साझा किए।

उपायुक्त ने बताया कि जिले के करीब सभी 700 स्कूलों में ई पीटीएम आयोजित की गई है। पीटीएम में करीब 70 हजार विद्यार्थियों व अभिभावकों ने हिस्सा लिया। यह शिक्षा विभाग की एक अच्छी पहल है, जिससे कोरोना काल में हर विद्यार्थी व अभिभावक के पास पहुंच सुनिश्चित की जा सकी। उन्होंने कहा कि उपमंडल स्तर पर भी संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में ई पीटीएम के माध्यम से वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को चाहिए कि वह अपने बच्चों के साथ बैठें, ताकि इस लॉकडाउन में उनके बैठने का अभ्यास हो सके। माता-पिता को भी जानकारी हो सके कि उनके बच्चे क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभिभावकों का बच्चों के साथ बैठने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें पड़ोस के व्यक्ति का सहयोग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि 11वीं व 12वीं की कक्षा बच्चे के भविष्य का लक्ष्य निर्धारित करती है, इसलिए सभी को सजग रहकर कार्य करने की जरूरत है। लॉकडाउन में विद्यार्थियों को किसी विषय की जानकारी लेनी है तो वह स्कूल में जा सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा भी 9वीं से 12वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को अपने शंका हल करने के लिए स्कूल में जाने की अनुमति दी है, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और अपने आपको सैनिटाईज करना हर अभिभावक व विद्यार्थी की पहली जिम्मेदारी होगी। उपायुक्त ने सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिए कि वे विद्यार्थियों के साथ सम्पर्क में रहें। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी रविन्द्र चौधरी, मुख्यमंत्री की सुशासन सहयोगी अमृता दाटला उपस्थित रहीं।

अभिभावकों ने डीसी के साथ सांझा किए अनुभव

ई-पीटीएम में अभिभावक सुरेन्द्र ने उपायुक्त से बातचीत की और लॉकडाऊन में ई लर्निंग को एक अच्छा माध्यम बताया उसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन के साथ-साथ स्कूल के शिक्षकों को आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि पड़ोस के बच्चों का भी सहयोग करते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है।

ई-पीटीएम से जोड़ा जाएगा सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को : सीएमजीजीए

ई-पीटीएम में उपायुक्त निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की सुशासन सहयोगी अमृता दाटला ने बताया कि जिले में सभी बच्चों को ईपीटीएम से जोड़ा जा रहा है। इसके माध्यम से सभी विद्यार्थियों की सेहत व पढ़ाई की स्थिति के बारे में जानकारी रखी जाएगी। इसके लिए एक प्रोफोर्मा तैयार किया गया है जिसमें 12 प्रश्न रखे गए हैं जोकि बच्चे के व्यक्तिगत और शिक्षा से संबंधित होंगे। सभी शिक्षक अपने-अपने विद्यार्थियों तक इन फार्मों को पहुंचाएंगे और इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे।

छात्रा कृति ने उपायुक्त के साथ साझा किए अनुभव, उपायुक्त ने छात्रा के उज्ज्वल भविष्य की कामना की

ई-पीटीएम में गढ़ीबीरबल के राजकीय स्कूल की छात्रा कृति ने उपायुक्त से बातचीत की और कहा कि वह लॉकडाऊन का भरपूर फायदा उठा रही है। वह सुबह 4 बजे पढ़ाई के लिए उठ जाती है। उन्होंने कहा कि वह अपने लक्ष्य को पार करेगी, जब भी उन्हें कोई प्रश्नों को हल करने में दिक्कत आती है तो उनके शिक्षक फोन के माध्यम से उन्हें सहायता करते हैं। उपायुक्त ने छात्रा के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

संक्षिप्त-समाचार

मानदेय बढ़ाने पर कुविवि शिक्षकों ने जताया दुष्यंत का आभार

कुरुक्षेत्र। मानदेय बढ़ाए जाने पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त किया है। गुरुवार को जननायक जनता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष जसविंद्र सिंह खेहरा से कुविवि के शिक्षक डॉ.अभिनव कटारिया, डॉ. अहमद, डॉ. श्वेता कश्यप, डॉ. तपेश, डॉ. संगीता, डॉ. सचिन वर्मा, कर्मदीप सैनी व डॉ. मनजीत शिक्षक मिले और दुष्यंत चौटाला व खैहरा का उनके संघर्ष में साथ देने पर आभार प्रकट किया। बता दें कि कुछ माह पूर्व ही कुविवि शिक्षकों ने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को मानदेय बढ़ाने को लेकर ज्ञापन सौंपा था और दुष्यंत चौटाला ने जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कुविवि कुलपति डॉ. नीता खन्ना का धन्यवाद किया।

स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने रक्तदाताओं को किया प्रोत्साहित

कुरुक्षेत्र। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के महानिदेशक डॉ. सूरजभान कंबोज ने लोक नायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ विभाग के निदेशक डॉ. प्रवीण सेठी मौजूद रहे। अस्पताल पहुंचने पर सिविल सर्जन डॉ. सुखबीर सिंह और चिकित्सा अधीक्षक एवं हृदय एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉ. शैलेंद्र शैली ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अस्पताल के ब्लड बैंक में सामाजिक संस्था शुभकर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट और सर्वसमाज सेवा कल्याण समिति द्वारा पंडित राजू ममगाईं की याद में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और रक्तदाताओं को बेज लगाकर उनकी हौसला अफजाई की। डॉ. सूरजभान कंबोज ने कहा कि ममगाईं परिवार रक्तदान शिविर के लगाने के लिए धन्यवाद का पात्र है। वास्तव में रक्तदान शिविर के माध्यम से ममगाईं परिवार और सामाजिक संस्थाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता पंडित राजू ममगाईं को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। निदेशक प्रवीण सेठी ने उम्मीद जताई कि उनका परिवार भविष्य में भी समाज सेवा के कामों में अपना योगदान देता रहेगा। महानिदेशक डॉ. कंबोज ने स्वतंत्रता सेनानी सुशीला देवी, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र शैली, शुभकर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा रजवंत कौर, सर्व समाज सेवा कल्याण समिति के अध्यक्ष रामेश्वर सैनी, शिव शक्ति सेवा मंडल के प्रधान एमके मौदगिल, समाज सामाजिक कार्यकर्ता ध्रुव और श्रुति को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया एवं रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. सूरजभान कंबोज ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की व्यवस्था में जुटा है। सभी जिलों में इस समय टेस्टिंग सुविधा अच्छी है और बेहतर सुविधाएं प्रदान कराने के उद्देश्य से पूरा खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने और कोरोना के संक्रमण से बचाए रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों से अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं दी जा रही गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। इस मौके पर आवासीय चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्याम सुंदर अरोड़ा, स्वतंत्रता सेनानी सुशीला देवी, मुख्य तकनीकी अधिकारी नरेश सैनी, शोभा, समृद्धि, सुनिधि, आउटसोर्सिंग सुपरवाइजर पवन शर्मा, श्यामलाल, पंकज, लिपिक धीरज, अतुल शर्मा, वीरेंद्र, विकास और रेखा आदि मौजूद रहे।

पिहोवा हल्के की सड़कों पर खर्च किए 2.97 करोड़ रुपये

कुरुक्षेत्र। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सड़कें, शिक्षा व संचार किसी भी क्षेत्र के विकास का मूल आधार है। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण का कार्य जल्दी पूरा करके गांवों को शहरों के समान सुविधाएं दी जाएं, ताकि ग्रामीण अंचल में बसे लोगों खासकर किसानों को मंडियों और शहरों से सीधा जुड़ने की सुविधा मिल सके। इसके लिए पिहोवा हल्के की सड़कों के नवीनीकरण कार्य पर दो करोड़ 97 लाख का बजट खर्च किया है। निरंतर किए जा रहे विकास कार्यों से पिहोवा हल्के की विकास की एक नई तस्वीर सामने आ रही है। इन सड़कों के नवीनीकरण कार्य से दर्जनों गांवों के हजारों लोगों को फायदा मिला है। खेलमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पिहोवा हल्के में लगभग दो करोड 97 लाख रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्र की 11 से अधिक सड़कों का नवीनीकरण कार्य पूरा किया जा चुका है। सड़कों पर दोनों तरफ सफेद रंग की पट्टी लगाई जा रही है। ताकि कोहरे के समय में विजिबिलिटी कम होने पर सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके और ये सड़कें सुंदर व आकर्षक नजर आएं। उन्होंने बताया कि गांव गुमथला भागल से रामगढ़ रोड, अंबाला हिसार रोड से गांव गुमथला, मोहनपुर कलसा से डेरा कागां वाली, अरुणाय से संगमेश्वर महादेव मंदिर, कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड से निकटपुरा, कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड से मुकीमपुरा, पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड से जीएस फार्म, बीबीपुर कलां से नन्दूखेड़ा, पिहोवा ढांड रोड से असमानपुर आदि कार्य का पूरा किया जा चुका है।

अपने कानूनों से पंजाब का नाम हटाएगा हरियाणा

विस अध्यक्ष ने मुख्य सचिव और विधि विभाग के अफसरों के साथ की बैठक

ज्ञान चंद गुप्ता बोले प्रदेशवासियों के स्वाभिमान के लिए हरियाणा के नाम पर होंगे कानून

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

आधी सदी बाद हरियाणा अपने अधिनियमों से पंजाब का नाम हटाने जा रहा है। इसके लिए हरियाणा की विधान पालिका और कार्यपालिका मिल कर योजना बना रही है।

वीरवार को विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने प्रदेश की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, कानून एवं विधि निर्माण विभाग में कानून सचिव बिमलेश तंवर और विधान सभा के अवर सचिव विष्णु देव के साथ बैठक की। बैठक में विधान सभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी अधिनियम पंजाब की बजाय हरियाणा के नाम करने की योजना तैयार करें। इसके लिए जल्द ही कानून एवं विधि निर्माण विभाग की कानून सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। फिलहाल हरियाणा में करीब 237 ऐसे अधिनियम हैं जो पंजाब के नाम से ही चल रहे हैं।

विधान सभा अध्यक्ष इन सभी अधिनियमों से पंजाब शब्द हटाना चाहते हैं। बता दें कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तब पंजाब में जिन अधिनियमों का अस्तित्व था, वे ही हरियाणा में लागू रहे थे। व्यवस्था यह बनी थी कि अगले दो वर्ष में हरियाणा अपनी जरूरतों के मुताबिक इनमें आवश्यक संशोधन कर सकेगा। अनावश्यक अधिनियमों को हटाने का अधिकार भी प्रदेश की विधान सभा को मिला है। हरियाणा को विरासत में जो अधिनियम मिले थे, वे सभी पंजाब के नाम पर थे और गत 54 वर्षों से हरियाणा की शासन व्यवस्था इन्हीं कानूनों के आधार पर चल रही है। इसके चलते प्रदेश की जनता और जनप्रतिनिधि इन कानूनों को हरियाणा के नाम पर करने की मांग करते रहे हैं।

विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा प्रदेश का गौरवशाली इतिहास रहा है। 1966 में स्थापना के बाद इस प्रदेश ने शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी विशिष्ट पहचान बनाई है। आर्थिक विकास की तीव्र रफ्तार से प्रदेश ने बुलंदियों को छुआ है। इसके बावजूद इसके सभी पुराने अधिनियम पंजाब के नाम पर ही है। उन्होंने कहा कि प्रमुख अधिनियमों में हरियाणा शब्द जुड़ने से यहां नागरिकों और जनप्रतिनिधियों में स्वाभिमान की भावना जागृत होगी, जो किसी भी आगे बढ़ते प्रदेश के लिए जरूरी है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 व सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट की बेहतरी को कार्यशाला

कुरुक्षेत्र। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों में राष्ट्रीय स्तर विशेषकर उत्तर भारत में उत्कृष्टता की उपलब्धि से उत्साहित कुरुक्षेत्र ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर अपनी तैयारियां प्रारम्भ कर दी हैं। वीरवार को स्थानीय पंचायत भवन में जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 व सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें नगर परिषद सहित जिला की सभी नगर पालिकाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्कशॉप में गुरूग्राम स्थित फीडबैक फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजय सिन्हा ने दो सत्रों में तैयारियों को लेकर क्या-क्या किया जाना है, इस बात की जानकारी दी। पहला सत्र सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट को सैधांतिक बनाने तथा दूसरे सत्र में इसकी व्यवहारिकता पर 32 इंडीकेटर्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। वर्कशॉप में उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़, एडीसी वीना हुड्डा, एसडीएम थानेसर अखिल पिलानी, पिहोवा एसडीएम सोनू राम, लाडवा एसडीएम अनिल यादव, डीएमसी नरेन्द्र पाल मलिक, चेयरमैन उमा सुधा, लाडवा नगरपालिका की चेयरमैन साक्षी मलिक शामिल हुए।

प्रदेश में कोरोना के नाम पर हुआ करोड़ों का घोटाला : किरण चौधरी

कोरोना के नाम पर घोटाले की आशंका, इस दौरान हुए खर्च की जांच करवाए सरकार

पायनियर समाचार सेवा। भिवानी

कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने आरटीआई द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कोरोना पर 345 करोड़ के खर्च पर सवाल उठाते हुए इसमें बड़ा घोटाला होने की आशंका जताई है, किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 345 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही है जो प्रति मरीज 26355 रुपये होता है। किरण चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हुए मरीजों से बात करने पर पता चला कि उन्हें दवाई के नाम पर 100 -200 रुपये की दवा देकर आइसोलेशन में रखा था इसके साथ 4500 रुपये कोरोना टेस्ट को जोड़ दिया जाए तो 5000 रुपये भी खर्च नहीं होता तो फिर 26355 रुपये किस आधार पर एक मरीज के ऊपर खर्च कर दिया, उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर खर्च पर आशंका का कारण यह भी है कि कोरोना से संक्रमित हुए ज्यादातर मरीजों को उनके घर पर ही आइसोलेट किया है। किरण चौधरी ने सरकार से मांग की है कि इसकी जांच कराई जाए ताकि सच्चाई लोगों के सामने आए और कोरोना के नाम पर घोटाला करने वाले बेनकाब किए जाएं। किरण चौधरी ने कहा कि गठबंधन सरकार घोटालों की पर्याय बन चुकी है, कोरोना की आड़ में घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं और पूरी तरह लूट मचा रखी है, उन्होंने कहा की कोरोना की आड़ में शराब घोटाला, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला करने वाली भाजपा- जजपा सरकार के नाम कोरोना घोटाला ओर जुड़ने जा रहा है और घोटालों की पर्याय बन चुकी गठबंधन सरकार में कोरोना के नाम पर घोटाले के लिए मना नहीं किया जा सकता। किरण चौधरी ने सरकार से मांग की है कि कोरोना के नाम पर हुए खर्च की निष्पक्ष जांच कराई जाए और सच्चाई सामने लाई जाए।

भाजपा सरकार ने देश की आत्मा पर किया घिनौना प्रहार : सुखबीर चहल

नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता।

फूंका सरकार का पुतला, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

पीएल वर्मा। कैथल

लोकसभा के बाद राज्य सभा में सभी मर्यादायों को ताक पर बिना बहस पास कराये गए कृषि सबंधी तीन विधेयकों के खिलाफ राज्य सभा सांसद, आप हरियाणा के सहप्रभारी डॉ. सुशील गुप्ता के नेतृत्व में वीरवार को इसका विरोध राज्य भर में जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया।

कैथल में आम आदमी पार्टी उतरी हरियाणा संगठन मंत्री सुखवीर सिंह ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक जिला मुख्यालय पर काली पट्टी बांध कर विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। काले कानूनों को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपे। इंजी सुखवीर ने कहा है कि देश के सर्वोच्च सदन राज्य सभा में सभी नियम कायदों और मर्यादायों को तार-तार करते हुए किसानों की आपत्तिओं को नजर अंदाज कर विधेयकों का पास कराया है, वह दुर्भाग्य पूर्ण है। उन्होंने बताया कि राज्य सभा में सदस्यों ने सदन के उप सभापति से बार-बार ये अनुरोध किया था कि इन बिलों पर सदस्यों की वोटिंग कराई जाए लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं कराई। इसलिए ये बिल अवैध है। अत: राष्ट्रपति से इन बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील भी की है। निरंजन गुज्जर, राजबीर, जसविंदर राणा, महेंद्र राणा, जोगिंदर यादव, दर्शन चहल, सत्यवान शीलम, मोनू कांगड़ा, अरुण जाटव, सुरेश कौल, सुनील सेन, युद्धवीर वालिया, प्रदीप कुमार, आदित्य पतलान, बिट्ठू राणा आदि मौजूद थे।

एकात्म मानववाद का विचार विश्व के लिए प्रेरणीय

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के अवसर पर आयोजित वेबिनार

पायनियर समाचार सेवा। भिवानी

भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का विचार भारत राष्ट्र ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए प्रेरणीय है। यह एक ऐसा चिंतन और दर्शन है जसमें विश्व शांति, विश्व कल्याण और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है।

यह बात आरएसएस के पूर्व प्रदेश कार्यवाहक व केएलपी कॉलेज के प्रो. देव प्रसाद भारद्वाज ने स्थानीय पंचायत भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के अवसर पर आयोजित वेबिनार में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष शंकर धूपड़ ने अतिथिगणों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई।

वेबिनार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया प्रो. देव प्रसाद भारद्वाज ने बताया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय एक महान चिंतक, कर्मयोगी, विचारक और दार्शनिक थे। 1951 में तत्कालीन प.पू. गुरुजी की प्रेरणा से पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। पं. दीनदयाल उपाध्याय को राष्ट्रीय महामंत्री जैसा महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। 1967 में वे भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे केवल 43 दिन तक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रह पाए। 11 फरवरी 1968 की रात्रि को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उनकी हत्या की साजिश आज तक सुलझ नहीं पाई है।

भारतीय जनसंघ के कुशल संगठनकर्ता के रूप में उनकी अनूठी व अनमोल प्रतिभा शक्ति थी। भाजपा प्रदेश सचिव मुकेश गौड़ ने कहा कि आज भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है। वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान कर्मयोगी की तपस्या का ही परिणाम है। भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने बताया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पूरे जिले में बूथ स्तर पर बड़े उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर गांधी जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ा का प्रवास रहेगा। पूर्व जिला अध्यक्ष नंदराम धानिया ने पं. उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष ताराचंद अग्रवाल, सभी मण्डल अध्यक्ष व पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

त्योहारी मौसम : फ्लिपकार्ट व्होलसेल 12 नए शहरों में अपने कदम रखेगी

12 नए शहरों में फैशन श्रेणी के साथ नेटवर्क विस्तार किया जाएगा हजारों किराना एवं एमएसएमई को डिजिटल कॉमर्स तक पहुंच मिलेगी

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद /गाजियाबाद

भारत में विकसित फ्लिपकार्ट ग्रुप के डिजिटल बी2बी मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट व्होलसेल ने 12 नए शहरों में अपने परिचालन विस्तार की घोषणा की है। फ्लिपकार्ट व्होलसेल रिटेल ईकोसिस्टम के लिए वन-स्टॉप डिजिटल मार्केटप्लेस सॉल्यूशन है जो छोटे कारोबारों को चुनने के लिए उत्पादों का विस्तृत संग्रह पेश करता है और वह भी बहुत खास कीमत पर। फ्लिपकार्ट व्होलसेल फैशन श्रेणी के साथ इन शहरों में विस्तार आरंभ करेगा तथा डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए किराना व सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों (एम एस एम ई) को तेजी से बढने, ग्राहकों को जोडे रखने व लाभदेयता सुधारने में मदद करेगा।

आगामी त्योहारी मौसम से पहले फ्लिपकार्ट व्होलसेल गाजियाबाद, फरीदाबाद, मैसूर, चंडीगढ़ ट्राइसिटी, मेरठ, आगरा, जयपुर, ठाणे-भिवंडी-उल्हासनगर, ग्रेटर मुंबई, वसई-विरार-मिरा-भाईंदर, ठाणे (कल्याण-डॉम्बिवली) और ठाणे (नवी मुंबई) में परिचालन शुरु कर देगा।

फ्लिपकार्ट व्होलसेल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं हैड आदर्श मेनन ने कहा, त्योहारी मौसम के आने से पहले 12 शहरों में अपनी उपस्थिति कायम करते हुए हम बहुत उत्साहित हैं। हमारा लक्ष्य एमएसएमई और किराना के लिए अधिक अवसर निर्मित करने का है। ट्रैंडी जयपुरी कुर्तियों से लेकर सदाबहार मैसूर सिल्क साड़ियों तक हमारा लक्ष्य छोटे कारोबारों की मदद करना है कि वे डिजिटल बदलाव को अपनाएं तथा ज्यादा मजबूत व्यापार के तौर पर उभरें। फ्लिपकार्ट व्होलसेल लांच होने के बाद से हमने बहुत से अग्रणी ब्रांडों के साथ हाथ मिलाया है और डिजिटल तकनीक से एम एस एम ई और किराना के लिए कारोबार करना आसान बनाया है। फ्लिपकार्ट ईकोसिस्टम से हासिल बी2बी और बी2सी जानकारी के आधार पर हम उन्हें ग्राहकों की बेहतर समझ देते हैं व उनके इलाके की खास मांगों के बारे में बताते हैं ताकि वे उसी के मुताबिक उत्पाद खरीदें और आगे बेचें। हमें यह देख कर खुशी हो रही है कि हमारी पहलकदमी से एम एस एम ई और किराना की समृद्धि बढ़ी है और भारत में आजीविका के लाखों नए अवसर बने हैं।

इस साल के अंत तक फ्लिपकार्ट व्होलसेल की योजना होम एंड किचन और ग्रौसरी की श्रेणियों में विस्तार करने की भी है।

एडीसी ने ली विजलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक

कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा ने वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय विजलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी के अधिकारियों व सदस्यों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि कमेटी से सम्बन्धित जो लम्बित मामले है उनका निर्धारित समय के अंदर निपटान करें। इस विषय में किसी प्रकार की कोई लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।

एडीसी ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बारे में एक्ट के अधीन अनुसूचित जाति के लोगों पर गैर अनुसूचित जाति के अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 85 हजार से 8 लाख 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी कमल धीमान को निर्देश दिए कि लाभ पात्रों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरजीत कौर, डीएसपी ममता सौदा, सदस्य कंवर पाल, कर्ण सिंह, कश्मीर, जय भगवान सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

सांसद सैनी ने क्षेत्र की प्रमुख मांगों को रखा सदन के पटल पर

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी है। इसकी धार्मिक मान्यता के कारण ही इस नगरी में पड़ने वाले अनेक तीर्थ व धार्मिक स्थलों के दर्शन व भ्रमण करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं व पर्यटकों का कुरुक्षेत्र में आना-जाना लगा रहता है।

कुरुक्षेत्र में भारी संख्या में श्रद्धालुओं व पर्यटकों के आगमन के दौरान काफी भीड़ रहती है, जिससे कई बार ट्रैफिक जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। पर्यटकों व आमजन की ट्रैफिक जाम की समस्या का जल्द ही निदान किया जाएगा। इसके लिए पटियाला से हरिद्वार तक के मार्ग जो कि कुरुक्षेत्र शहर के बीचों-बीच से होकर गुजरता है को फौर लैन करने और कुरुक्षेत्र के चारों तरफ रिंग रोड बनाने के लिए सरकार के समक्ष मांग रखी गई है। सांसद नायब सिंह सैनी लोकसभा की कार्रवाई के दौरान संसद में विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल-जवाब कर रहे थे। इससे पहले सांसद नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष रखा और इन मांगों को पूरा करने के मांग की है।

सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र महाभारत कालीन विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है। इस नगरी में करीब 134 धार्मिक स्थल हैं। प्राचीन व विश्वप्रसिद्ध स्थल होने की वजह से इस धर्मनगरी में हर वर्ष लाखों की संख्या में देश-विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। कुरुक्षेत्र जाने के लिए एक ही सड़क है जो शहर के बीच से निकल कर कैथल-पिहोवा-पूंडरी की तरफ निकलती है और राजस्थान बार्डर को टच करती है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की एक सड़क जो पटियाला से हरिद्वार को जाती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को आपस में जोड़ती है। यह सड़क पटियाला से हरिद्वार, चीका, पिहोवा, कुरुक्षेत्र, लाडवा, रादौर व यमुनानगर से होकर निकलती है जिसकी कुल लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है।

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 25 सितंबर 2020

कैग रिपोर्ट : ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे खराब, तकनीक भी पुरानी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस की ओर से लगाए गए 3,870 सीसीटीवी कैमरों में से संतोषजनक काम कर रहे कैमरों की संख्या बेहद कम है। संसद में बुधवार को पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में भारतीय दंड संहिता के तहत 2019 में पंजीकृत अपराधों की संख्या 2013 के मुकाबले 275 फीसदी तक बढ़ गई है। इस बारे में दिल्ली पुलिस ने स्वीकार किया कि अपराधों को दर्ज कराने की संख्या में व्यापक बढ़ोतरी और ई-प्राथमिकी दर्ज करने की सुविधा से आंकड़ें बढ़े हैं।

कैग की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस में श्रमबल और साजो-समान प्रबंधन से सामने आए तथ्यों के अनुसार दिल्ली

पुलिस ने शहर भर में सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थानों पर 3,870 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। संतोषजनक काम कर रहे कैमरों की संख्या बेहद कम है, (प्रायोगिक चरण) वाले 31 फीसदी कैमरे जबकि अन्य चरण वाले 44 फीसदी तक कैमरे बेकार हैं।

दिल्ली पुलिस 20 साल पुरानी ट्रंकिंग प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है, इनकी कार्यसीमा 10 वर्ष की है जिसे बीते हुए 10 साल हो चुके हैं। ट्रंकिंग प्रणाली ऐसी रेडियो संचार प्रणाली है, जिसमें दो तरफ से संपर्क हो सकता है। वायरलेस सेट को अद्यतन करने के लिए 10 साल पहले ही प्रस्ताव रखे गए थे लेकिन अब तक निविदा पर अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है। पारंपरिक प्रणाली के तहत आनेवाले वायरलेस सेट की संख्या जून 2000 के 9,638 के मुकाबले जून,2019 में घटकर 6,172 रह रह गई है क्योंकि इस अवधि में जो सेट खराब हुए थे। उन्हें नियमित तौर पर नहीं बदला गया।

कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि श्रमबल की कमी की वजह से भी दिल्ली पुलिस के कामकाज पर असर पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12,518 पदों को मंजूरी देते हुए सलाह दी थी कि पहले 3,139 पदों को भरकर काम शुरू किया जाए और इन कर्मियों की जमीन पर तैनाती के बाद 9,379 पदों पर भर्ती की जाए लेकिन दिल्ली पुलिस 3,139 पदों पर भर्तियां करने में असफल रही जिसकी वजह से 9,379 मंजूरी पदों के लिए भी कार्य आगे नहीं बढ़ सका।

दवाई बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, लोग फंसे

नोएडा। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में सेक्टर-59 की दवा निर्माता कंपनी जुब्लीयंट लाइफ साइंस में भीषण आग लग गई। इसके बाद कंपनी प्रबंधन द्वारा फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई।

समाचार लिखे जाने तक मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी सावधानी बरतते हुए पुलिस ने कंपनी के आसपास की स्थित दूसरी फैक्ट्रियों को भी खाली करवा लिया था। कंपनी में कुछ कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने की वजह अभी पता नहीं चली है।

निवेशकों को लुभाने लगी फिल्म सिटी

सामने आई सिंगापुर की कंपनी ने की एक करोड़ डॉलर के निवेश की पेशकश

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर फिल्म सिटी बसाने की घोषणा की है, जिसका बेहद सकारात्मक रुझान आ रहा है। सिंगापुर की एक मीडिया कंपनी ने प्रदेश में प्रस्तावित फिल्म सिटी में फिल्म अकादमी स्थापित करने के लिये एक करोड़ डॉलर लगभग 73.51 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश की पेशकश की है। एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई।

बयान में कहा गया है कि यह प्रस्ताव नई फिल्म सिटी परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री के साथ फिल्म निर्माताओं और कलाकारों की मंगलवार को हुई एक बैठक के दौरान सामने आया। यह फिल्म सिटी नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर 1,000 एकड़ के क्षेत्र में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा, राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई को तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली फिल्म बिरादरी से। कला निर्देशक नितिन देसाई ने मुंबई में स्थापित सेट की तर्ज पर एक पूरी फिल्म सिटी स्थापित करने की पेशकश की। उनका मत था कि मुंबई फिल्म उद्योग में लगभग 80 प्रतिशत तकनीशियन और कार्यबल उत्तर प्रदेश से है, अत: यहां फिल्म सिटी बनने के बाद श्रमबल की उपलब्धता की कभी भी समस्या नहीं होगी।

बयान के अनुसार, सिंगापुर स्थित एक कंपनी विस्टास मीडिया के संदीप सिंह ने एक करोड़ डॉलर लगभग 73.51 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश के साथ एक फिल्म अकादमी स्थापित करने की पेशकश की है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिये फिल्म बिरादरी के कुछ सदस्य लखनऊ पहुंचे थे, जबकि अनुपम खेर और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत में शामिल हुए। फिल्म निर्माता संघ के अध्यक्ष अशोक पंडित ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि हिंदी फिल्मों से परे देखना चाहिये और यहां तक कि बहुभाषी फिल्में भी बनायी जा सकती हैं। बयान के अनुसार गायक उदित नारायण, कैलाश खेर और अनूप जलोटा ने भी निर्णय की सराहना की।

पुलिस हिरासत में युवक की मौत, हंगामा

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

● थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित

कैला भट्टा निवासी शमशेर ने बुधवार रात विजयनगर थाने की हवालात में अपने शर्ट से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने रात में अस्पताल में पुलिस पर शमशेर की जान लेने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उसके बाद बृहस्पतिवार सुबह भी परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पर जमकर हंगामा करते हुए मृतक का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत कर शमशेर का पोस्टमार्टम कराया।

जानकारी के मुताबिक सेक्टर-9 विजयनगर में शमशेर पत्नी और 4 बच्चों के साथ किराए पर रहता था। वह विजयनगर थाना क्षेत्र के मवई में मस्जिद के पास परचून की दुकान चलाता था। परिजनों ने बताया कि शमशेर बुधवार शाम करीब 4.30 बजे शराब के नशे में घर आया और परिवारवालों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। शमशेर का हंगामा बढ़ता देखकर उसकी पत्नी तमन्ना ने यूपी-112 पर कॉल करके पुलिस बुला ली जो शमशेर को विजयनगर थाने ले गई। थाने में तलाशी लेने के बाद उसे हवालात में बंद कर दिया गया।

बताया गया कि इस दौरान शमशेर ने थाने की हवालात में ही अपनी शर्ट से फंदा लगा लिया। कुछ देर बाद पहरा दे रहे पुलिसकर्मी ने हवालात में देखा तो शमशेर अचेत अवस्था में पड़ा था और उसके गले में शर्ट लिपटी हुई थी। आनन-फानन में शमशेर को पुलिस जिला अस्पताल लेकर गई जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया।

वहीं मामले में लापरवाही बरतने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने विजयनगर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट व मुख्य आरक्षी मोहर सिंह, कांस्टेबल अमित कुमार तथा संतरी हरीश तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच एसपी सिटी को सौंपी है।

केजरीवाल के शासन में सरकारी कर्मियों का शोषण : भाजपा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी की सरकार के शासन में सरकारी कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए बार-बार गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। पहले गेस्ट टीचर, फिर डीयू टीचर और अब सरकारी वकीलों को फीस नहीं मिल रही है। सरकारी वकीलों के बिल पिछले कई सालों से लंबित पड़े हैं।

आदेश गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन में एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निजी संस्थाना व लोगों से अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं काटने का अनुरोध कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ खुद अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे है। कोरोनाकाल में जब हर कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा था केजरीवाल सरकार ने गेस्ट टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर और सरकारी वकीलों को पाई-पाई के लिए मोहताज कर दिया है। उनके लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। केजरीवाल के पास विज्ञापन देने के लिए तो रुपए हैं, लेकिन अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है।

पिछले 16 सालों का सबसे सूखा सितंबर

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार दिल्ली में सितंबर में 21 मिलीमीटर से भी कम बारिश हुई जो कि 16 साल में इस महीने में हुई सबसे कम बारिश है। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली में मानसून की अंतिम बारिश हो चुकी है और अब बारिश होने की संभावना नहीं के बरा है।

आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, सफदरजंग वेधशाला में 109.3 मिलीमीटर सामान्य बारिश की बजाय केवल 20.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई जो कि 81 प्रतिशत कम थी। वेधशाला में अंतिम बार आठ सितंबर को 1.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में इस वर्ष सितंबर में केवल तीन दिन अच्छी बारिश हुई। इससे पहले वर्ष 2016 के सितंबर में सबसे कम बरसात हुई थी जब केवल दो दिन अच्छी बारिश हुई थी।

दिलचस्प बात यह भी है कि दिल्ली में इस साल अगस्त में 237 मिलीमीटर बारिश हुई जो पिछले सात वर्षों में अगस्त महीने में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में एक जून से लेकर अब तक 633.1 मिलीमीटर सामान्य बारिश की बजाय 576.5 मिलीमीटर बारिश हुई जो कि नौ प्रतिशत कम है।

प्रेसवार्ता करते गाजियाबाद पैरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी।

'दोबारा शुरू हो ऑनलाइन क्लास, फीस की जाए माफ'

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

अभिभावकों का प्रदर्शन

गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा अभिभावकों के प्रति प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के लगातार उदासीन रवैये एवं निजी स्कूलों की मनमानियों को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया गया। साथ ही संस्था के पदाधिकारियों ने एडीएम सिटी को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। इससे पूर्व पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को पूरी स्थिति से अवगत कराया।

पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि लॉकडाउन समय की एक तिमाही फीस माफी, ऑनलाइन क्लास के अनुसार फीस निर्धारण, आर्थिक संकट के कारण फीस जमा ना कर पाने वाले अभिभावकों के बच्चों की बंद की गई ऑनलाईन क्लास को तत्काल प्रभाव से शुरू कराई जाये। साथ ही फीस जमा नहीं कर पाने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के होने वाले बोर्ड रजिस्ट्रेशन को न रोका जाये।

पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के 56 प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए संशाधन नहीं है। वहीं सरकारें बिना किसी तैयारी के अभिभावकों पर निजी स्कूलों के साथ मिलकर ऑनलाइन शिक्षा का बोझ डाल रही हैं जो शिक्षा समानता के अधिकार का हनन है।

बदमाशों की गोली से घायल हुआ शख्स

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा फ्लाईओवर पर लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल सवार दो हमलावर वहां से भाग गए। पीड़ित की पहचान मनीष के रूप में हुई थी। उनके पेट में गोलियां लगीं हैं और पटपड़गंज के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मनीष की हालत हालत पहले से बेहतर है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है और उन्हें पकड़ने के लिए टीम बनाई गईं हैं। घटना बुधवार शाम करीब 7.30 बजे हुई जब मनीष और उसका भाई अरुण घर लौट रहे थे। वे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के रामप्रस्थ के रहने वाले हैं।

आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने की तैयारी में दिल्ली सरकार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि राष्ट्रीय राजधानी में आरटी-पीसीआर के जरिए अधिक से अधिक जांच करने के लिए क्या करना चाहिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक हफ्ते पहले उच्च न्यायालय ने जांच क्षमता बढ़ाने को कहा था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते आप सरकार को सुझाव दिया था कि आरटी-पीसीआर जांच क्षमता जितनी अधिक बढ़ाई जा सकती है, उतनी बढ़ा दी जाए ताकि कोविड-19 के मामलों का पता चल सके क्योंकि रैपिड एंटिजन जांच के 60 फीसदी परिणाम ही सही होते हैं। उच्च न्यायालय की सलाह के बाद भी आरटी-पीसीआर जांच की संख्या नहीं बढ़ी और अभी इस प्रक्रिया से करीब 10,000 जांच ही की जा रही है।

अदालत ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति जल्द से जल्द एक बैठक बुलाए जिसमें यह विचार करे कि आरटी-पीसीआर की जांच क्षमता किस हद तक बढ़ाई जानी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि 8 से 15 सितंबर के बीच कुल जांचों में से एक चौथाई से भी कम जांचें आरटी-पीसीआर के जरिए की गईं। राष्ट्रीय राजधानी की आरटी-पीसीआर से दैनिक तौर पर 14,000 जांच करने की क्षमता है।

ज्वैलरी की दुकान में लूट का प्रयास नाकाम

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

● घटना की सूचना के कई घंटे बाद पहुंची पुलिस

शहर में बदमाशों के हौंसले लगातार बुलंद हो रहे है। बृहस्पतिवार को दिनदहाडे लगभग 2 बजे राजनगर एक्स्टेशन स्थित एक ज्वैलरीशॉप को हथियार बन्द बदमाशों ने लूटने का असफल प्रयास किया। यहां सन्त ज्वैलर के नाम से आभूषण खरीदने व बेचने का शॉप है। जानकारी के अनुसार बाइकों पर सवार होकर आए आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने शॉप का दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो दुकान के अन्दर मौजूद कर्मचारियों ने दरवाजा नहीं खोला।

इस पर बदमाशों ने उन्हे डराने के लिए दुकान के बाहर से छ राउन्ड गोलियां इधर उधर चलाईं। गोलियों की आवाज सुनकर राजनगर एक्स्टेशन के मुख्य द्वार पर मौजूद सुरक्षाकर्मी भी इतने भयभीत हो गये कि वे घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। संत ज्वैलर के मालिक हिमान्शु सोनी ने बताया कि जब बदमाशों को लगा कि वे लूट में कामयाब नहीं हो पाएंगे तो वे वापस लौट गये। यह सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सोनी ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने सौ नंबर पर फोन करके पुलिस को जानकारी दी मगर पुलिस कई घन्टे बाद मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस सावधानी से काम लेती तो बदमाशों की नाकाबन्दी करके पकडा जा सकता था। उधर सीओ महिपाल सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और बहुत जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

शस्त्र लाइसेन्स देने की मांग

अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी जिलों में स्वर्ण का कारोबार करने वाले कारोबारियों को अविलम्ब शस्त्र लाइसेन्स उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि आये दिन स्वर्णकार और सर्राफ के साथ लूट की घटनाएं घटित हो रही हैं। इस कारोबार में काम करने वाले कारोबारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर है। उन्होंने पत्र में मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि हम अपनी समस्याये उक्त अधिकारी के समक्ष रख सकें।

वारदात की जानकारी देते सन्त ज्वैलर के मालिक हिमांशु सोनी।

राशन डीलर ने किशोर को बुरी तरह से पीटा

नोएडा। यहां के कस्बा निवासी राशन डीलर ने किशोर के साथ मारपीट की। आरोप है कि डीलर किशोर को कम राशन दे रहा था जिसका उसने विरोध किया तो नाराज होकर राशन डीलर ने किशोर को बुरी तरह से पीटा।

कुलदीप सिंघल ने पुलिस से शिकायत में बताया कि उनका कहना है कि उनका 12 वर्षीय बेटा मंगलवार को राशन डीलर के यहां राशन लेने के लिए गया था। डीलर उनकी यूनिटों के अनुसार राशन कम देने लगा इस पर उनके बेटे ने इसका विरोध किया तो गुस्साए डीलर ने उनके बेटे के साथ गाली गलौज व मारपीट की। आरोप है कि जब किशोर के पिता शिकायत लेकर डीलर के पास पहुंचे तो डीलर ने उनसे भी दुर्व्यवहार किया और पीटने का प्रयास किया।

संक्षिप्त समाचार

मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते आसपा के कार्यकर्ता।

आजाद समाज पार्टी का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

गाजियाबाद। आजाद समाज पार्टी ने बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया। पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि सरकारी विभागों में निजीकरण पर रोक लगाई जाए साथ ही निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चत किया जाए और युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सफाईकर्मियों की अस्थाई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थानीय किया जाए और किसान विरोधी कृषि बिलों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। प्रदर्शन के दौरान नरेश गौतम, विजय कुमार जाटव, शाहरुख, सुरेन्द्र गौतम, रामलाल, मुकेश सिद्धार्थ, सुशील गौतम, सूरज गौतम, नंदलाल जाटव, पवन कुमार गौतम आदि मौजूद रहे।

सदीक नगर में अवैध निर्माण तोड़ती निगम की जेसीबी मशीन।

निगम ने भू-माफिया से मुक्त कराई जमीन

गाजियाबाद। हिंडन नदी के समीप गांव सदीक नगर इलाके में भूमाफियाओं द्वारा कब्जायी गयी लगभग दस बीघा जमीन को गाजियाबाद नगर निगम के दस्ते ने मुक्त करा ली। इस जमीन की कीमत लगभग 21 करोड बारह लाख पचास हजार आंकी गई है। बृहस्पतिवार सुबह लगभग 11 बजे नगर निगम का मोबाइल दस्ता मौके पर पहुंचा और वहां मौजूद अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। नगर आयुक्त महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि यह जमीन सिटी जोन के खसरा संख्या 278,93 95, 96,98,पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि यहां भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर विभिन्न प्रकार के निर्माण करके कब्जा कर लिया गया था। इस संबंध में थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए निगमायुक्त ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।

पांच हजार करोड़ का निवेश करेगा भूटानी ग्रुप

नोएडा। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन का व्यवसायियों पर खासा असर पड़ा हैं। कई रियल स्टेट प्रोजेक्टों का काम रुकने से मजदूर भी पलायन कर गए हैं इससे बेरोजगारी में भी बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे हालात में भूटानी ग्रुप ने चार हजार से अधिक लोगों को रोजगार देने का फैसला किया है। ग्रुप आने वाले तीन सालों में अपने अलग-अलग परियोजनाओं में लगभग पांच हजार करोड़ का निवेश करेगी। भूटानी ग्रुप के सीईओ आशीष भूटानी ने बताया कि इसके अतिरिक्त कंपनी पहली बार बीआइसीई यानी भूटानी ईंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी लाएगी।

दो परिवारों में जमकर चले लाठी-डंडे

नोएडा। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में बुधवार को दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर बुरी तरह मारपीट हुई है जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस को मामले की जानकारी मिल गई है। बताया जा रहा है कि यह मामला दनकौर थाना क्षेत्र के ऊंची दनकौर का है।

उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली दंगा

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में कठोर आतंकवाद रोधी कानून, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली की एक अदालत ने 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खालिद को 10 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था। उसे 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 14 सितंबर को हिरासत में पूछताछ शुरू हुई थी।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उसे और हिरासत की जरूरत नहीं है। ऐसे में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को आरोपी की सुरक्षा के लिए नियमों के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। खालिद ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उन्होंने पुलिस हिरासत के दौरान किसी भी तरह के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

पुलिस ने प्राथमिकी में दावा किया है कि सांप्रदायिक हिंसा पूर्व-नियोजित साजिश थी, जिसे कथित रूप से खालिद और दो अन्य लोगों ने अंजाम दिया था।

पराली के प्रदूषण से निपटने को विज्ञान का सहारा

मुख्यमंत्री ने पूसा में लिया निस्तारण तकनीक का जायजा, पड़ोसी राज्यों से करेंगे अपनाने का आग्रह

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सर्दियों में राजधानी दिल्ली को दम घोटों प्रदूषण से बचाने की कवायद जारी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा) ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे पराली से खेत में ही खाद बनाई जा सकेगी। दिल्ली एनसीआर समेत पड़ोसी राज्यों के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली बॉयो डीकंपोजर तकनीक का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को पूसा कृषि संस्थान में निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि यह तकनीक पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने में व्यावहारिक और काफी उपयोगी है। यह वैज्ञानिकों की कई वर्षों की मेहनत और कोशिशों का परिणाम है। वह केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करेंगे और उनसे पराली के निस्तारण के लिए पूसा द्वारा विकसित तकनीक का इस्तेमाल करने के निर्देश पड़ोसी राज्यों को देने का अनुरोध करेंगे।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित बॉयो डी-कंपोजर को देखते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साथ में संस्थान के वैज्ञानिक। फोटो : रंजन डिमरी

पूसा संस्थान द्वारा विकसित किए गए कैप्सूल का घोल बना कर खेतों में छिड़का जाता है, जिससे पराली का डंठल गल कर खाद बना जाता है। इससे उनकी उपज बढ़ेगी और खाद का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह तकनीकी बहुत ही साधारण, इस्तेमाल योग्य और व्यवहारिक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा पराली जालने की वजह से हर वर्ष प्रदूषण होता है, इससे किसान भी परेशान हैं।

पूसा इंस्टीट्यूट का दौरा करने के दौरान सीएम ने कहा कि दिसंबर के महीने में किसान अपने खेत में खड़ी धान की पराली जलाने के लिए विवश होता है। उसका धुंआ दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के ऊपर छा जाता है। पूसा के निदेशक ने एक नई किस्म की तकनीकी इजाद की है। जिसके जरिए संस्थान कैप्सूल देता है। चार कैप्सूल एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होते हैं। इस कैप्सूल की कीमत प्रति एकड़ लगभग 150 से 250 रुपए आ रही है। कैप्सूल के जरिए एक किसान लगभग 25 लीटर घोल बना लेता है। उसमें गुड़, नमक और बेसन डालकर यह घोल बनाया जाता है और जब किसान उस घोल को अपने खेत में छिड़कता है, तो पराली का जो मोटा मजबूत डंठल होता है वह डंठल करीब 20 दिन के अंदर मुलायम होकर गल जाता है।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक: चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादक: उषा श्रीवास्तव। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

टीबी समाप्ति को दवा से ज्यादा जागरूकता की जरूरत : डॉ. विजय

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

जिला उप चिकित्सा अधिकारी एवं टीबी रोग विशेषज्ञ डॉ. विजय कुमार ने कहा कि टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ पंचायत, शिक्षा और सामाजिक संगठनों को भी साथ आना होगा। टीबी रोग को समाप्त करने के लिए दवा से ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। कोरोना काल में टीबी के रोगियों की संख्या कम हुई है।

गुरुवार को सोहना के नागरिक अस्पताल परिसर में निक्षय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला उपचिकित्सा अधिकारी एवं टीबी रोग विशेषज्ञ डॉ. विजय कुमार, स्थानीय

कोरोना काल में टीबी के रोगियों की संख्या कम हुई

अस्पताल के प्रभारी डॉ. नवल किशोर, घंघौला एसएमओ डॉ. विकास कुमार व आयुष विभाग के डॉ. कुलभूषण आदि ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉ. विजय कुमार ने बताया कि टीवी को जड़ समाप्त करने के लिए ग्राम सभा की बैठकों से लेकर स्कूलों में, पंचायत भवन आदि में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ताकि सभाओं के माध्यम से टीवी की बीमारी को जड़ समाप्त किया जा सके। ये काम अकेला स्वास्थ्य

सोहना के नागरिक अस्पताल में डॉ. विजय कुमार निक्षय दिवस के अवसर पर संबोधन करते हुए।

विभाग नहीं कर सकता। इसके लिए पंचायत विभाग, ग्राम पंचायत, शिक्षा विभाग को आगे आना होगा। आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं को जागरूकता के अभियानों में हिस्सा लेकर लोगों को जागरूक करना होगा। क्योंकि टीबी या कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए दवाओं से ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। डॉ. विजय ने कहा कि कोरोना काल में अपनाएं जा रहे सुरक्षा उपाय से टीबी के रोगियों की संख्या में गिरावट आई है।

10 से 12 लाख रुपये एक रोगी पर खर्च

प्रदेश सरकार टीवी के एक रोगी का उपचार कराने में 10 से 12 लाख रुपये खर्च कर रही है। यदि रोगी सही समय पर, सही उपचार करवाता है। उसकी यह बीमारी समाप्त हो जाती है, लेकिन यह छूत का रोग होने के कारण रोगी समय पर अपनी जांच कराए। वह रोग को लेकर आम जनता के बीच न जाए। जागरूकता ही सबसे बड़ा और सरल उपचार है।

डॉ. विजय कुमार,
जिला उपचिकित्सा अधिकारी एवं टीवी रोग विशेषज्ञ

एक करोड़ 22 लाख रुपये की राशि वितरित

टीबी रोगी को अब उपचार के दौरान हर माह सरकार से प्रोटीन युक्त खाना खाने के लिए 500 रुपये देती है। यह राशि रोगी के बैंक खाते में ऑन लाइन आती है। यह योजना वर्ष 2018 में शुरू की थी। स्वास्थ्य विभाग ने जिला गुरुग्राम में अब तक एक करोड़ 22 लाख रुपये की राशि टीवी रोगियों को वितरण की है। जो रोगी के द्वारा टीवी का प्राइवेट डॉक्टर से उपचार कराने पर भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

सरकारी राशन की अवैध सप्लाई पर सीआईडी का छापा

आढ़ती से बरामद किए गए कट्टे।

पायनियर समाचार सेवा। तावडू

एक आढ़ती से सीआईडी ने बरामद किए गेंहू के 34 कट्टे

पुलिस ने मामले में गाड़ी मालिक और आढ़ती को बनाया आरोपी

यहां सरकारी राशन की हेराफेरी का मामला सामने आया है। नूंह जिले की सीआईडी ने तावडू नई अनाज मंडी के एक आढ़ती के प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर गेंहू के 34 कट्टों (17 क्विंटल) को बरामद किया है। सीआईडी अधिकारियों का कहना है ये कट्टे गांव मोहम्मदपुर अहीर से अवैध तौर पर यहां पहुंचाए गए हैं। अब ये किसी आंगनवाड़ी से यहां पहुंचाए गए हैं या डिपो से इसकी जांच फूड विभाग व पुलिस कर रही है। इस मामले में स्थानीय खाद्य एवं पूर्ति विभाग के निरीक्षक की शिकायत पर पिकअप के अज्ञात चालक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

सीआईडी को सूचना मिली कि तावडू उपमंडल के गांव मोहम्मदपुर अहीर से सरकारी राशन तावडू की नई अनाज मंडी के एक आढती के यहां अवैध तौर पर सप्लाई होता है। मामले का पर्दाफाश करने को लेकर बुधवार को सीआइडी ने जाल बिछाया। सूचना के मुताबिक सीआईडी टीम नई अनाज मंडी की आढत नंबर 91 पर पहुंची। जहां पर एक पिकअप गाडी से गेहूं के कट्टे उतारे जा रहे थे। सीआइडी टीम को देखकर पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। उसके बाद सीआइडी ने फूड सप्लाई विभाग को मामले की सूचना दी। सूचना पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक उमर मोहम्मद मौके पर पहुंचे व दोनों टीमों ने जांच पड़ताल की। इन अधिकारियों ने आढती कृष्णलाल से भी पूछताछ की। जिसमें आढती ने बताया कि इन कट्टों में कीडा लगने के चलते वह गांव मोहम्मदपुर अहीर में स्थित अपने घर से लाया है। वहीं मामले के जांच अधिकारी सब इंसपेक्टर कल्लू खान ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की तफ्तीश जारी है। गाड़ी बरामद कर ली है। मामले में गाड़ी मालिक व आढ़ती को आरोपी बनाया गया है। वहीं नूंह जिले के सीआइडी इंसपेक्टर राजेंद्र कुमार ने कहा कि सूचना पर सीआईडी ने यह कार्रवाई की है। ये सरकारी राशन है। यह आंगनवाड़ी या राशन डिपो से यहां लाया गया इसकी जांच फूड सप्लाई विभाग व पुलिस कर रही है। वहीं खाद्य एवं पूर्ति विभाग के निरीक्षक से जब इस संदर्भ में बात करनी चाही तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।

जिले की पांच मंडियों में पहली से होगी बाजरा की खरीद

मंडियों में केवल 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा'पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की ही फसल की खरीद होगी

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

जिला में बाजरा फसल की खरीद प्रक्रिया एक अक्टूबर से शुरू होगी। जिला की पांच मंडियों सोहना, फरुखनगर, पटौदी, हेलीमंडी, खोड़ मंडी में बाजरे की खरीद होगी।

उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि मंडियों में आने वाले किसानों को गेट पास के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। गेट पास किसान मंडी में आने पर गेट से प्राप्त कर सकता है। गौरतलब है कि 2150 रूपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद होगी। उन्होंने बताया कि मंडियों में केवल 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा ' पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की ही फसल की खरीद की जाएगी। खत्री ने बताया कि कोरोना संकमण को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसान एक साथ मंडी में इकठ्ठा ना हो, सभी बारी-बारी से अपनी फसल लेकर मंडी में आए। यह सुनिश्चित करने के लिये मंडियों में खरीद का कार्य दो शिफ्टों में किया जाएगा। उन्होंने सभी किसानों से कहा कि खरीद कार्य के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो , इसके लिए मंडियों में आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बारे में अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि पंजीकृत किसानों को प्रशासन की ओर से निर्धारित शेड्यूल अनुसार ही उनकी बाजरे की फसल बेचने के लिए एक दिन पहले सूचना देकर बुलाया जाएगा तथा एसएमएस के माध्यम से भी उन्हें अवगत कराया जाएगा ताकि कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में निर्धारित स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की अनुपालना बनी रहे। खत्री ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के साथ साथ उनकी फसल का दाना दाना खरीदा जाए। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिये मंडियों में फेस मास्क, हैंड सेनिटाइजर सहित कोविड-19 प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करवाया जाएगा। इसके साथ ही मंडियों में आने वाले किसानों की एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। मंडियों में किसान जब अपनी फसल लाएं, उस समय सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जारी हिदायतों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी।

प्याज के बीज पर पांच सौ रुपये प्रति किलो का अनुदान : डीसी

पायनियर समाचार सेवा। नूंह।

नूंह जिले के उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने बताया कि किसान खेती के साथ-साथ बागवानी अपना कर अपनी आय दोगुना कर सकते हैं। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं क्रियांवित की गई हैं। योजनाओं के माध्यम से किसानों को बेहतर अनुदान भी दिया जाता है। सरकार द्वारा किसानों का रबी प्याज की खेती की ओर रुझान बढ़ाने के लिए प्याज के बीज पर 500 रुपये प्रति किलोग्राम अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि जिला बागवानी विभाग द्वारा समय-समय पर जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को बागवानी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन योजनाओं के तहत अनुदान पाने के लिए किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यदि किसान पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो उन्हें इन योजनाओं के तहत अनुदान राशि नहीं मिलेगी।

प्याज के एक किलो बीज पर 500 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। एक किसान अधिकतम एक हेक्टेयर के लिए 10 किलोग्राम बीज तक ले सकता है। औसतन एक एकड़ में करीब चार किलो प्याज का बीज लगता है। इस पर प्रति किलोग्राम 500 रुपये अनुदान के अनुसार किसान को प्रति एकड़ दो हजार का अनुदान मिलेगा। वहीं एक किसान अधिकतम अनुदान राशि 5 हजार तक ले सकता है। किसान उच्च बीज को एनएचआरडीएफ के बीज बिक्री केंद्र जिला उद्यान अधिकारी नूंह के बीज बिक्री केंद्र से ले सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि किसान बीज के बिल को आवेदन करते हुए बागवानी विभाग में जमा करवा दें ताकि उन किसानों की अनुदान राशि उनके खाते में आ सके।

आंगनबाड़ी के 212 केन्द्रों पर पोषण सप्ताह की शुरूआत की

सोहना। महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग अपने सभी 212 केन्द्रों पर 30 सितम्बर तक पोषण सप्ताह मनाएगा। इस पोषण सप्ताह के अवसर पर हर रोज कोविड-19 के निमयमों को एजेंडा में लिखा जाएगा। गुरूवार से ब्लॉक के सभी आंगनबाड़ी सेंटरों पर औषधि वाले पौधों का रोपण करते हुए पोषण सप्ताह मनाने की शुरूआत की गई। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर लगाया गया औषधि पौधा के लाभ और उसकी उपयोगिता की जानकारी ग्रामीण महिलाओं को दी जाएगी। सुपरवाइजर रेखा सोनी ने बताया कि पोषण सप्ताह के दौरान आंगनबाड़ी केंन्द्रों पर तैयार किया गया।

मुठभेड़ के बाद दो हथियार तस्कर काबू

गुरुग्राम। क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम ने मुठभेड़ के बाद दो हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर टोयोटा कार से हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया। टोयोटा कार से 11 ऑटोमेटिक पिस्टल एवं सात कारतूस की बरामदगी की गई। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है।

क्राइम ब्रांच मानेसर के प्रभारी अमित कुमार को सूचना मिली कि राजस्थान से हथियार तस्कर गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। जिस पर टीम गठित कर गांव सहरावन एवं मानेसर इलाके में नाकेबंदी की गई। तस्कर टोयोटा कार में सवार होकर गांव सहरावन में कच्चे रास्ते से होते हुए गुरुग्राम जा रहे थे। पुलिस को देखते ही आरोपितों ने कार से गोलियां चलाई, लेकिन, पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और कार में सवार दो तस्करों को दबोच लिया।

कार की जांच की गई तो उसमें से हथियारों का जखीरा मिला। टोयोटा कार से 11 ऑटोमेटिक पिस्टल एवं सात कारतूस मिले। पकड़े गए युवक हरियाणा के भिवानी जिले के कुलदीप व यूपी अलीगढ़ का सचिन हैं। वे काफी समय से अवैध हथियार बेचने का धंधा कर रहे थे। वे गुरुग्राम के विभिन्न इलाकों में हथियार लाकर बेचते थे।

कोरोना से बचने को स्वास्थ्य विभाग के आदेशों का पालन जरूरी

नूंह। कोरोना से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अनुसार खान-पान और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने जरुरत है। खांसते या छींकते समय मुंह पर मास्क या कपडा लगाएं। हाथों को लगातार साबुन से धोएं या सेनेटाइजर का प्रयोग करें। ये जानकारी नूंह के सिविल सर्जन डाक्टर सुरेंद्र कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों के अनुसार यह संक्रमण उन लोगों के लिए बहुत ही घातक है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। इसलिए इस महामारी से बचने के लिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।

अस्पताल की दीवार फांदकर घर में घुसे दो अज्ञात युवक

अस्पताल में सुरक्षा की अवस्थाओं से नाराज लोगों ने किया हंगामा

पुलिस और सीएमओ को शिकायत देकर की कार्रवाई की मांग

पायनियर समाचार सेवा। तावडू

तावडू के अस्पताल परिसर में एकत्रित लोग।

बुधवार रात शहर के सरकारी अस्पताल की दीवार के साथ बने एक मकान में दो युवकों द्वारा दीवार फांद कर घर में घुसने का मामला सामने आया है। हालांकि मकान में रहने वाले लोगों की सजगता के चलते आरोपी किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दे सके लेकिन पुलिस गहनता से मामले की जांच में जुटी है।

वार्ड नंबर-10 निवासी शक्ति किरण ने बताया कि बुधवार की रात के करीब ढाई बजे सरकारी अस्पताल की दीवार से दो व्यक्ति उनके घर में घुस आए। उन्होंने बताया कि उस समय उनकी पत्नी शौच के लिए उठी थी। आरोपियों के घर में प्रवेश करने पर उनकी पत्नी ने शोर मचा दिया जिसके बाद वह भी उठ गए और दो अज्ञात व्यक्ति सरकारी अस्पताल परिसर की ओर कूद गए। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने शोर मचाया तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी और देकर फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद सुबह होने पर अस्पताल भवन परिसर के नजदीक रहने वाले और अन्य नगरवासी रज्जू सहरावत, सुशील भारद्वाज, भाजपा नेता नरेश ढल, धर्मेंद्र भारद्वाज, अमित सोनी, अश्वनी नासा मौके पर पहुंच गए और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान जिले के नवनियुक्त सीएमओ सुरेंद्र यादव भी मौके पर पहुंच गए। जिनके सामने शहरवासियों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाया और अपनी पीड़ा उनके सामने रखी। पीड़ित व्यक्ति ने सीएमओ से कहा कि रात को अस्पताल में 6 कर्मचारी थे, जिनमें 1-1 वार्ड ब्वॉय, सिक्योरिटी गार्ड, चपडासी व 3 नर्स शामिल हैं। इस घटना में तीन पुरूष कर्मचारियों में से दो ने अंजाम दिया है इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अस्पताल भवन परिसर में हंगामा कर रहे शहरवासियों ने सीएमओ के सामने हाल ही में अस्पताल में ठेकेदार के द्वारा की गई भर्तियों पर भी सवाल उठाया व इन भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार होने की बात कही।

लोगों ने सीएमओ से इन भर्तियों की गहनता से जांच करने की भी बात कही। वहीं लोगों ने यह भी कहा कि अस्पताल में एनजीटी के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आसपास के सामने कूड़ा व मेडिकल वेस्ट फेंककर जलाया जाता है। नूंह के सीएमओ डा. सुरेंद्र यादव का कहना है कि पीड़ित व्यक्ति व लोगों ने जो शिकायत दी है उसकी गहनता से जांच होगी।

शराब पिलाने के बाद सिर पर पत्थर मारकर की हत्या

गुरुग्राम। गार्ड की हत्या के आरोपित को पुलिस ने नाथुपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने पुलिस को बताया कि उसने गार्ड सुरेश के साथ शराब पी, इसके बाद उसके सिर पर पत्थर मारकर गटर में फेंक दिया। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

गांव ग्वालपहाड़ी निवासी 48 वर्षीय सुरेश का शव गत दिवस द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक गटर में मिला। वह डीएलएफ फेज-तीन इलाके की एक सोसायटी में गार्ड की नौकरी करते थे। डीएलएफ फेज-तीन थाना पुलिस ने शक के आधार पर सोसायटी में ही चालक का काम करने वाले उत्तराखंड के अलमोड़ा निवासी जगत सिंह को गांव नाथूपुर इलाके से गिरफ्तार किया तो पूरी सच्चाई सामने आ गई।

जगत सिंह ने पुलिस को बताया कि बीती 14 सितंबर की रात उसने सुरेश ने एक साथ बैठकर मेट्रो स्टेशन के नजदीक शराब पी थी। उसी दौरान उसने सुरेश के सिर पर पहले पत्थर से हमला किया था। जब वह बेहोश हो गए तो उन्हें उठाकर गटर में डाल दिया था। ग्रामीण मंगल सिंह ने बताया कि 14 सितंबर से ही सुरेश लापता थे। वह घर से ड्यूटी करने गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। कई दिनों तक खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिले।

रंजिश में फायरिंग के आरोप में तीन पकड़े

पायनियर समाचार सेवा। पलवल

एन्टी व्हीकल थैप्ट स्टाफ हथीन ने 16 सितंबर को अन्धुआ पट्टी होडल में हुई गोलीबारी के सम्बन्ध मे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ व बरामदगी के लिये पुलिस रिमांड पर लिया है।

एन्टी व्हीकल थैप्ट प्रभारी निरीक्षक सुरेश भडाना ने बताया कि उनकी टीम से उप निरीक्षक ईश्वर सिंह व पुलिस पार्टी पलवल शहर मे गश्त मे मौजूद थी। उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि अन्धुआ पट्टी होडल मे पुरानी रंजिश के चलते गोलीबारी करने वाले तीन आरोपी किठवाडी पुल के पास मौजूद हैं। जो कहीं जाने की फिराक में हैं। टीम द्वारा तुरन्त मौके पर रेड करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश करके पूछताछ व बरामदगी के लिए पुलिस रिमान्ड पर लिया है। इस सम्बन्ध में पीड़ित पवन निवासी अन्धुआ पट्टी होडल की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला थाना होडल में दर्ज है।

पुलिस द्वारा पकड़े आरोपी।

सोहना आईटीआई में 1160 बच्चों ने किए ऑनलाइन आवेदन

सोहना। सोहना की आईटीआई में अलग-अलग ट्रेडों में अब तक 1160 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें सबसे ज्यादा आवेदन वैल्डर ट्रेड में प्राप्त हुए है।

आईटीआई में आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 सितम्बर है। सोहना आईटीआई के प्रधानाचार्य विनोद कुमार खंगवाल ने बताया कि कोविड-19 के चलते विद्यार्थियों में दाखिला लेने का जोश कम नहीं है।

लैंक्सेस इंडिया ने छह वेंटिलेटर किए दान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

देश में कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद के लिए, केमिकल कंपनी लैंक्सेस ने ठाणे, महाराष्ट्र में कौशल्या मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट हॉस्पिटल और बेथानी हॉस्पिटल में एक करोड़ रुपये से अधिक के 6 वेंटिलेटर डोनेट किए हैं। दोनों अस्पतालों को तीन-तीन वेंटिलेटर दिए गए हैं। यह पहल साल 2020-21 के लिए कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) का एक हिस्सा है। ठाणे में स्थित ये अस्पताल इन वेंटिलेटर का उपयोग क्षेत्र के रोगियों के इलाज के लिए करेंगे। लैंक्सेस स्थानीय समुदाय को महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए अधिकारियों और चिकित्सा संस्थानों के साथ सहयोग कर रही है। गौरतलब है कि लैंक्सेस इंडिया ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के संबंध में कई पहल की हैं। कंपनी ने दो करोड़ रुपये प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड (पीएम केयर्स) में दान किए और 30 लाख रुपये की राहत सामग्री महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थानीय प्रशासन को प्रदान की। इसमें अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ सहयोग भी शामिल था, जिसके माध्यम से कंपनी ने जरूरतमंदों को मुफ्त में 30 हजार से अधिक भोजन के पैकेट बांटे। लैंक्सेस ने महाराष्ट्र सरकार के राहत समन्वय केंद्र के माध्यम से बीएमसी और टीएमसी को अपने अत्यधिक प्रभावी सर्फेस डिसइंफेक्टेंट रिलाय प्लस ऑन विक्रोन दान किया। कंपनी ने एक टन डिसइंफेक्टेंट मुहैया कराया ताकि कोरोनो वायरस के संक्रमण को कम करने में मदद मिले।

कृषि विधेयकों के खिलाफ आप ने पीएम और सीएम का पुतला फूंका

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

लोकसभा के बाद राज्य सभा में बिना बहस पास कराये गए कृषि संबंधी तीन विधेयकों के खिलाफ आम आदमी पार्टी दक्षिण हरियाणा इकाई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला फूंका। वहीं सोहना चौक से लेकर लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला। राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त की अनुपस्थिति में एसडीएम जितेन्द्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी ने बिल वापस करने के नारे लगाए और बृहस्पतिवार को काला दिवस घोषित किया गया।

इस अवसर पर आप पार्टी के दक्षिण हरियाणा इकाई के अध्यक्ष आरएस राठी ने कहा कि देश के सर्वोच्च सदन राज्य सभा में सभी मर्यादाओं को ताक पर रख, किसानों की आपत्तिओं को नजरंदाज तथा विपक्ष की आवाज को दबाते हुए बिना वोटिंग के जिस तरह ध्वनिमत एवं

राज्य सभा में बिना बहस पास कराये गए कृषि संबंधी तीन विधेयकों के खिलाफ आम आदमी पार्टी दक्षिण हरियाणा इकाई।

धक्के से इन विधेयकों का पास कराया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सभा में सदस्यों ने सदन के उपसभापति से बार-बार इन बिलों पर सदस्यों की वोटिंग कराने की मांग की, लेकिन वोटिंग नहीं कराई इसलिए ये बिल अवैध है। राष्ट्रपति से इन बिलों पर हस्ताक्षर न करने की अपील की गई है। युवा अध्यक्ष धीरज यादव, बादशाहपुर अध्यक्ष डॉ सारिका वर्मा ने कहा कि अन्नदाताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच कर भाजपा सरकार ने किसान विरोधी विधेयक ला कर देश की आत्मा पर घिनौना प्रहार किया है। भाजपा देश को निजीकरण की तरफ ले जाकर पूंजीपतियों के हाथ में देने की गहरी साजिश का खेल रही है तथा इन कृषि विरोधी जैसे काले कानून बना कर व्यापारियों के साथ साथ एवं किसानों को भी पूंजी पतियों का गुलाम बना रही है। पार्टी सरकार से जवाब मांगती है कि अगर अनाज मण्डी समाप्त हो आएंगी तो छोटे किसानों को एमएसपी कौन देगा और कैसे देगा। क्या एफसीआई 15.5 करोड़ कसानों के खेत से एमएसपी पर फसल खरीद सकेगी। क्या आढ़ती एवं मजदूर किसानों की फसल बेचने में बाधक बन रहे थे। इस दौरान दक्षिण हरियाणा अध्यक्ष आरएस राठी, युवा अध्यक्ष धीरज यादव, बादशाहपुर विधानसभा अध्यक्ष डॉ सारिका वर्मा, गुरुग्राम युवा अध्यक्ष रूस्तम चौहान, ऋषि गोयल, एडवोकेट अशोक वर्मा काननूी सैल अध्यक्ष, अखिल सचदेवा, मीनू सिंह, चांद मोहम्मद, संदीप जाखड़, दिनेश कुमार, मुकेश प्रजापति, राम गौतम, संत राम, कुशेश्वर भगत, अलरीना, महिपाल यादव, अरूण भूपेन्द्र शर्मा सहित शामिल रहे।

आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर फूंका पुतला

पलवल। आम आदमी पार्टी जिला इकाई पलवल ने अपना विरोध दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का अलावलपुर चौक पर पुतला फूंका। कार्यक्रम का आयोजन जिला इकाई पलवल के जिलाध्यक्ष कुलदीप कौशिक के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर कुलदीप कौशिक ने कहा कि भारत भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पूरे देश में एक तरफ जहां कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने में नाकाम रही, वहीं दूसरी तरफ कोरोना की आड़ में इस भयंकर महामारी के दौरान किसान विरोधी बिल लेकर आई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पास किए गए इस बिल से पूरे देश में मोदी विरोधी लहर चल रही है। ये बिल केवल और केवल पूंजीपतियों को अधिक मुनाफा कमाने, जमाखोरी करने, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई रोककर उनकी कीमत बढ़ाने और आमजन का जीवन यापन दुर्लभ करने के उद्देश्य से पास किया गया है। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में किसान विरोधी बिल का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रही है। सरकार को चाहिए कि युवाओं को रोजगार दे बच्चों को शिक्षा दें, मरीजों को इलाज दें और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दे। इस मौके पर दक्षिण जोन हरियाणा के संगठन मंत्री ओम प्रकाश गुप्ता, प्रवक्ता कौशल ततारपुर, जिला संगठन मंत्री धर्मेंद्र सिंह, जिला सचिव सचिन बंसल, कोषाध्यक्ष एसपी मित्तल, उपाध्यक्ष नेपाल तंवर, सीताराम, रहीम खान, वीरेंद्र सिंह आदि समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कोरोना की आड़ में कर्मचारियों की मनमानी से मरीज परेशान

- बीके अस्पताल में मुंह पर कपड़ा बांधने वालों की एंट्री की बंद
- चिकित्सक के द्वारा लिखे गई कोरोना जांच पर भी लग रहा चार्ज

कविता। फरीदाबाद

एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कपड़े का मास्क लगाकर कोरोना वायरस से बचाव का संदेश रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीके अस्पताल प्रबंधन ने ओपीडी में मुंह पर कपड़ा, रूमाल और चुन्नी बांधकर इलाज को आने वाले मरीजों के घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इलाज को आने वाले मरीजों के कार्ड पर लिखी कोविड-19 की जांच का भी शुल्क लिया जा रहा। जबकि स्वास्थ्य विभाग ने यह शुल्क नौकरी, मेडिकल और यात्रा से सम्बंधित कोरोना की जांच के लिए निर्धारित किया था, लेकिन मरीजों को भी शुल्क देने को बाध्य किया जा रहा है। अस्पताल के कर्मचारियों की अज्ञानता और अस्पताल लापरवाही के बीच मरीज पीस रहे हैं।

कपड़ा बांधने पर नोएंट्री : बीके की ओपीडी में पर तैनात सुरक्षाकर्मी मुंह पर रूमाल, कपड़ा या चुन्नी बांधकर आने वालों मरीजों को अंदर जाने से रोक रहा था। इस तुगलकी नियम से मरीज काफी परेशान हुए। एक बुजुर्ग व्यक्ति चिकित्सक के रूम में मुंह पर रूमाल बांधकर जाने की जिद करने लगा तो कर्मचारी ने उसे मास्क पहन कर आने के लिए भेज दिया। वहीं तीन महिलाएं मुंह पर चुन्नी बांधकर पहुंची तो सुरक्षाकर्मी ने उन्हें भी मास्क लगाने की बात कहकर लौटा दिया।

कोरोना जांच शुल्क : गत 18 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नौकरी, मेडिकल और यात्रा के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के 1600 रुपये, रैपिड एंटीजन के लिए 600 और एलाइजा जांच के लिए 250 रुपये का शुल्क निर्धारित किया था। जिस पर बीके सिविल अस्पताल की पीएमओ डॉ. सविता यादव ने भी यह निर्देश ओपीडी में जारी कर दिए, लेकिन कर्मचारियों ने मामले को समझे बिना अस्पताल में इलाज करवाने के दौरान लिखी कोविड-19 की जांच के भी पैसे मरीजों से लेने शुरू कर दिए। जिसका मरीजों के द्वारा विरोध किया जा रहा है।

बढ़ सकती है बीमारी

अस्पताल के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेशों को समझने बिना निमोनिया, बुखार, जुकाम व खांसी जैसी बीमारी से पीड़ितों की कोरोना जांच करने का भी शुल्क ले रहे हैं। मरीजों द्वारा शिकायत करने पर डाक्टरों ने कर्मचारियों को समझाने का भी प्रयास किया। लेकिन वे बिना शुल्क के कोरोना जांच करने को तैयार नहीं हैं। जिससे कोरोना के फैलने का खतरा और बढ़ गया है।

डेयरी संचालक की हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद। रुपयों के लेनदेन के विवाद में जीवन नगर निवासी एक डेयरी संचालक के सिर पर डंडे से वार कर उसकी हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने नेकपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में लिप्त अन्य दो आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है।

जीवन नगर भाग दो निवासी चांद बाबू ने 21 सितंबर को यह मामला थाना मुजेसर में दर्ज करवाया था। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि उसका भाई वाहिद कालोनी में भैंसों की डेयरी चलाता है। इसी इलाके में रहने वाला मनोज भी डेयरी चलाता है। जबकि योगेश भैंस की खरीद फरोख्त करता है। कुछ समय पहले वाहिद ने एक गाय और भैंस खरीदने के लिए एडवांस के रूप में योगेश को 6200 रुपये दिए थे। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी योगेश ने उसे गाय व भैंस नहीं दिलवाई। जिसके कारण वाहिद ने योगश से अपने रुपये लौटाने की मांग शुरू कर दी। इस बात को लेकर दोनों के बीच गाली गलौच और झगड़ा भी हुआ था। जिसके कारण योगेश ने मनोज, गौरव व रोहित के साथ मिल कर वाहिद को सबक सिखाने की योजना बनाई थी।

अब घर बैठे ही हासिल करें नो ड्यूज सर्टीफिकेट : यश गर्ग

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

सम्पत्तियों को क्रय-विक्रय करने के लिए होने वाली रजिस्ट्रियों से पूर्व फरीदाबाद नगर निगम से नो ड्यूज़ सर्टीफिकेट प्राप्त करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के द्वारा लांच किए गए नो ड्यूज़ सार्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम को एक बेहतर सिस्टम बताते हुए निगमायुक्त डा. यश गर्ग ने नागरिकों को निगम कार्यालयों में आने की बजाए अपने घर बैठे-बैठे ulbhryndc.org के माध्यम से अपना नो ड्यूज प्राप्त करने की सलाह दी है। निगमायुक्त के अनुसार नो ड्यूज़ जारी करने या इस सम्बन्ध में नागरिकों के द्वारा सिस्टम के माध्यम से उठाई जा रही आपत्तियों का एक निर्धारित समय सीमा में निगम के सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा समाधान किया जाना आवश्यक है और इसमें कोताही बरतने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

डा. गर्ग ने नो ड्यूज़ सर्टीफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि

हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में नागरिकों को अपनी सम्पत्ति को बेचने, उसे ट्रांसफर करने, लीज पर देने आदि-आदि से पूर्व नगर निगम से नो ड्यूज प्राप्त किया जाना आवश्यक किया गया है और इसे प्राप्त करने के लिए पूर्व में प्रचलित जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए उक्त नो ड्यूज़ सार्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम को सरकार के द्वारा लांच किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी प्रार्पटी का नो ड्यूज बिना किसी परेशानी के प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसका तरीका बड़ा ही आसान है। जिन नागरिकों को निगम से अपनी प्रार्पटी की आई.डी. नहीं मिली हुई है उसे स्वयं को अपने मोबाईल नम्बर के माध्यम से ulbhryndc.org पर जाकर पंजीकृत करना होगा। इसके बाद लाग-इन करके सर्च प्रार्पटी के विकल्प में उपलब्ध अपनी कालोनी या सेक्टर को चयन करेगा तो उस क्षेत्र की सीमा लाल रंग में सिस्टम पर दर्शित होगी, जहां पर नागरिक अपनी प्रार्पटी का चयन करके आनलाईन ही सेल्फ असेसमेंट करके सम्पत्ति कर जमा कर सकते हैं। जैसे ही नागरिक सम्पत्ति कर व विकास शुल्क जमा करेगा तो उसे अस्थाई प्रार्पटी आईडी मिल जायेगी और इसके बाद ही रजिस्ट्री के लिए उसे टोकन प्राप्त हो सकेगा। निगमायुक्त के अनुसार जिन नागरिकों की प्रार्पटी एनडीसी पोर्टल पर दर्ज है, उसे नागरिक प्रार्पटी आईडी (जोकि उनकी पिछले साल की संपत्ति कर की रसीद पर उल्लेखित है) से सर्च कर सकते हैं। प्रार्पटी आईडी पर निगम के द्वारा संपति कर के दर्ज किये गये ब्यौरे से यदि नागरिक सहमत हैं तो वे आनलाईन अदायगी कर दें और यदि उक्त ब्यौरे से असहमत हैं तो वे दस्तावेज के प्रमाण के साथ अपनी आनलाईन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिससे कि निगम के संबधित कर्मचारियों के द्वारा ऐसे दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करके नागरिकों के द्वारा दर्ज की गई आपत्ति का निर्धारित समय सीमा में निपटारा किया जा सके।

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने की तोड़फोड़

फरीदाबाद। जिला प्रशासन की मदद से नरेश कुमार, जिला नगर योजनाकार ने बताया की इंफोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस द्वारा दुर्गा बिल्डर फेस-2 लाईसेंस कालोनी में किये जा रहे अवैध निर्माणों को तोड़फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई। तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान बनाये गये, रिहायशी निर्माण, एक ऑफिस व 20 डीपीसी/बाउंड्रीवाल में तोड़फोड़ की कार्यवाई की गई। ये अवैध निर्माण मुकेश गिरी व सुभाष गुप्ता द्वारा करवाये जा रहे हैं। ये अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ अधिनियम के प्रावधान में आगे की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट ने बताया कि दुर्गा बिल्डर लाईसेंस कालोनी का केस अभी माननीय् सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित स्पेशल

कमेटी के अधीन विचाराधीन है इसलिए विवादित भूमि में किसी प्रकार के प्लाट की खरीद-फरोख्त न करें व न ही किसी प्रकार का निर्माण करें, विभाग से भवन प्लान स्वीकृत कराये बगैर किये गये निर्माण को अधिनियम के प्रावधान में गिरा दिया जायेगा। विभाग द्वारा आजकल भू-माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है।

कोरोना से 2 मौतें, 240 पॉजिटिव से आंकड़ा पहुंचा 18,705

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बृहस्पतिवार को 240 मामले सामने आने से कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 18,705 पर पहुंच गया। इनमें सर्वाधिक नीमका जेल से 11 मरीज सामने आए है। वहीं कोरोना पॉजिटिव दो मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिससे जिले में मृतकों की संख्या का आंकड़ा 211 पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में राहत की बात यह रही कि 248 मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली। जिससे जिले का रिकवरी रेट 90.6 प्रतिशत पहुंच गया।

मृतक और पॉजिटिव

पदम नगर निवासी 27 वर्षीय महिला और बड़खल निवासी 51 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव पुरुष ने विभिन्न

गंभीर बीमारियों के कारण दम तोड़ दिया। वहीं 240 पॉजिटिव में फतेहपुर बिल्लौच, नेहरू कालोनी, जमाई कालोनी, कृष्णा कालोनी, सूर्या कालोनी, सेक्टर-16, 21, 23, 65, 81, 86, 77, स्प्रींग फिल्ड कालोनी, प्रहलादपुर, भुपानी, पुरी प्रणायाम, बसंतपुर, पदम नगर, मिल्हाड़ कालोनी, चाचा चौक, भूड कालोनी, अजरौंदा, नंगला, गोपी कालोनी, सिही, तजूपुर, खेड़ी कला, श्याम कालोनी, मोहना, सीकरी, विनय नगर, पुलिस लाइन, भगत सिंह कालोनी से 1-1 मरीज है। कपड़ा कालोनी, सेक्टर-8, 55, 29, 81, 35, 84, 82, 33, 7, 8, 17, 20, ईसमाइलपुर, एनआईटी-5, तिलपत, ग्रीन फिल्ड कालोनी, जीवन नगर, विष्णु कालोनी, चावला कालोनी, श्याम कालोनी, एसी नगर, सारन, जवाहर कालोनी, बड़ौली, सराय, एतमादपुर से 2-2 मरीज है। सेक्टर-21, 88, 34, 11, 41, 35, 9, 19, एनएच-तीन, पर्वतीया कालोनी, भूड कालोनी, शिव दुर्गा विहार, संजय इंक्लेव से 3-3 मरीज है। सेक्टर-30, 16, 18, 15, 3, अशोका इंक्लेव से 4-4 मरीज है। एनएच-एक, डबुआ कालोनी से 5-5 और बल्लभगढ़, एसजीएम नगर से 6-6 मरीज है। वहीं नीमका जेल से 11 और अन्य एरियों से 45 मरीज है।

यह है आंकड़े

अब तक कुल सैम्पल	190142
रिपोर्ट नेगेटिव आई है	171144
रिपोर्ट आनी है शेष	293
कुल पॉजिटिव है	18705
अब तक ठीक हुए	16945
अब तक कुल मौत	211
गंभीर हालत में भती	43
आईसीयू में भर्ती	10

आरपीएफ के जवानों से मारपीट में तीन गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जीआरपी ने न्यू टाउन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के दो जवानों के साथ मारपीट करने व सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है।

जानकारी के मुताबिक 20 सितंबर की रात 9.30 बजे आरपीएफ के जवान गुरुदत्त और भूपेंद्र सिंह स्टेशन पर ड्यूटी दे रहे थे। उस समय फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर बैठकर तीन व्यक्ति शराब पीकर आसपास के माहौल को खराब कर रहे थे। इन दोनों जवानों ने शराब पी रहे व्यक्तियों को वहां से जाने के लिए कहा, जिससे की तीनों ने जवानों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इससे की जवानों ने उन्हें सही ढंग से बात करने की नसीहत दी, बावजूद तीनों जवानों के साथ मारपीट कर भाग गए। गुरुदत्त की शिकायत पर जीआरपी ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने व मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले की जांच एएसआई भीमप्रकाश को दी गई। उधर आरपीएफ के जवान भी तीनों आरोपितों को लेकर अलर्ट थे। पुलिस ने आरपीएफ के जवानों की शिनाख्त पर बुधवार को तीनों को न्यू टाउन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने अपने नाम बत्रे सिंह, दीपक और विनोद कुमार बताए, हैं, जो संजय नगर एनआईटी के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

भारत बंद को लेकर पुलिस अलर्ट

फरीदाबाद। किसानों द्वारा भारत बंद को लेकर फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। हमारे भाई हैं। उनसे अपील है कि वह शांतिपूर्वक रहे असामाजिक तत्वों से दूर रहे, अप्रिय घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति यों को बख्शा नहीं जाएगा। फरीदाबाद शहर में करीब 700 कैमरे लगे हुए हैं, जिससे प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति एवं संगठन पर विशेष नजर रखी जाएगी। इस दौरान असामाजिक तत्वों के लिए विशेष पुलिस बल और रिजर्व बल तैयार किया गया है जो कि एंटी राइट इक्विपमेंट सहित तैयार रहेंगे। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल और रिजर्व बल को तैनात किया जाएगा। कुछ असमाजिक तत्व समाज में अहिंसा फैलाने की मंशा से भीड़ का फायदा उठाते हुए किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जिसके मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम को भी इस बारे में अवगत कराया गया है।

नॉर्थ टेक्सास के साथ ड्यूल डिग्री पाठ्यक्रम होगा शुरू

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

दोनों विश्वविद्यालयों के बीच अकादमिक क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए हुआ समझौता

वाईएमसीए जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने वैश्विक परिवेश में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं शोध के क्षेत्र में रोजगार के लिए विद्यार्थियों की बढ़ती मांग को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास, अमेरिका के साथ अकादमिक क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए समझौता किया है। जिसमें रणनीतिक साझेदारी, अनुसंधान सहयोग, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए एक्सेंज प्रोग्राम के अलावा ड्यूल डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करना शामिल हैं। जेसी बोस विश्वविद्यालय जल्द ही यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के साथ ड्यूल डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अमेरिका के टेक्सास स्थिति कैंपस में अध्ययन करने की संभावनाओं पर काम करेगा।

इस समझौता पर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास की प्रोवोस्ट तथा अकादमिक मामलों की वाइस प्रेजिडेंट डॉ. जेनिफर इवांस-काउली ने हस्ताक्षर किए गए हैं और दोनों विश्वविद्यालयों के बीच अकादमिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। जेसी बोस विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस अकादमिक समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास अमेरिका में सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़ अनुसंधान विश्वविद्यालयों में से एक है। यह साझेदारी हमारे शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन का अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी। शुरुआती चरण में विश्वविद्यालय क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, साइबर सुरक्षा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सहयोग को आगे बढ़ाने का इच्छुक है। कुलपति ने समझौते को सफल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों की निदेशक डॉ. शिल्पा सेठी और उनकी टीम के निरंतर प्रयासों की सराहना की। यह साझेदारी इसी वर्ष जनवरी में जेसी बोस विश्वविद्यालय द्वारा फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईएसएफटी 2020) पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दोनों विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के बीच हुए विचार-विमर्श का परिणाम है। कुलपति ने दोनों विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने में कुलसचिव डॉ. एसके गर्ग और दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रो. नवीन कुमार के योगदान की भी सराहना की।

डकैती की कौशिश में पांच आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद। क्राईम ब्रांच सेक्टर-85 ने डकैती की कोशिश करने वाले पांच आरोपियों को दबोचा है। पांच नौजवान लड़के सेक्टर-88 मास्टर रोड पर डकैती करने की फिराक में घूम रहे थे। जिसकी सूचना किसी ने क्राइम ब्रांच को दी थी।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उप निरीक्षक सुमेर सिंह ने टीम तैयार कर सेक्टर 88 मास्टर रोड की तरफ रवाना हुए। मास्टर रोड पर पहुंचने के बाद क्राईम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को पकड़ने की अपनी योजना के अनुसार किसी गाडी का आने का इंतजार किया। पिकअप गाड़ी जब एमवीएन स्कूल मास्टर रोड सेक्टर 88 के नजदीक पहुंची तो बदमाशों ने पिकअप को रूकवाने के लिए उसको पिस्तौल और डंडे दिखाए, लेकिन पिकअप ड्राईवर ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए कट मारकर गाडी को भगा ले गया। गिरफ्तार आरोपियों में संत नगर निवासी सुनिल, रामकुमार, गांधी कालोनी निवासी देवेन्द्र और एनआईटी निवासी सागर शामिल है।

सेनिटाइजर, फल और मिठाईयां बांट मनाया जन्मदिन

फरीदाबाद। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी सैलजा का जन्मदिन आज जिले के कांग्रेसियों ने प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ के सेक्टर-10 स्थित कांग्रेस भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया।

इस दौरान कांग्रेसियों ने मास्क पहनकर व सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना करते हुए केक काटा और सेनिटाइजर, फल व मिठाईयां वितरित की और कुमारी सैलजा की दीर्घायु की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि उनके कुशल नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस निरंतर मजबूती की ओर अग्रसर रहेगी। इस मौके पर कांग्रेसियों ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रदेश कांग्रेस कुमारी सैलजा के नेतृत्व में निरंतर मजबूती की ओर अग्रसर हो रही है, जिस प्रकार वे हर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दे रही है, उससे कार्यकर्ताओं में भी पार्टी के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठा बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि जनता के अहित मुद्दों पर कुमारी सैलजा की सरकार पर बेबाकी टिप्पणियां से भाजपा सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है क्योंकि भाजपा सरकार में कोरोना काल में जितने भ्रष्टाचार हुए है, उस सभी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया है और लोगों के समक्ष इस सरकार का असली चेहरा उजागर किया है।

उपाध्याय की जयंती को लेकर की बैठक

बल्लभगढ़। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुक्रवार को वेबीनार के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर विधानसभा बल्लभगढ़ के प्रभारी राजकुमार वोहरा ने सेक्टर 8 स्थित हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा नेता पंडित टिपर चंद शर्मा ने की। बैठक में भाजपा के पदाधिकारियों को 25 सितंबर के दिन प्रत्येक शक्ति केंद्र पर शाम 4 बजे मनाई जाने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के बारे में अवगत कराया गया। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल के जीवन पर चर्चा की। भाजपा नेता राजकुमार वोहरा ने बताया कि पंडित दीनदयाल की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के कार्यक्रम हर बूथ स्तर पर आयोजित होंगे, जिनको लाइव डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा।

प्राइवेट शिक्षकों का कोरोना टेस्ट भी हो फ्री : चंद्र सेन

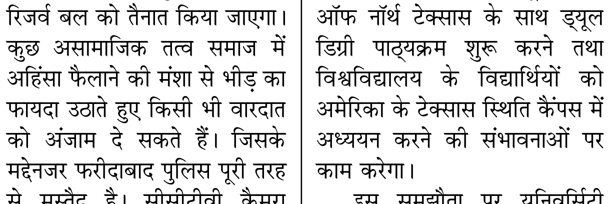

फरीदाबाद। बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष चंद्र सेन शर्मा के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी सतेंद्र कौर वर्मा से उनके कार्यालय में मिला। जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें एक ज्ञापन सरकार के नाम सौंपा। जिसमें एसोसिएशन ने मांग की है कि सभी स्कूल कोरोना महामारी के कारण पिछले 6 महीने से बंद पड़े हैं। अब सरकार ने कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों को अभिभावकों की सहमति पर स्कूल में पढ़ाई हेतु संपर्क की छूट दी है, तो सरकार ने प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के कोरोना टेस्ट की फीस निर्धारित कर दी है, जबकि सरकारी शिक्षकों का कोरोना टेस्ट फ्री में हो रहा है, ऐसा भेदभाव शिक्षकों से क्यों? आखिर शिक्षक तो शिक्षक है फिर सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, प्राइवेट स्कूलों की आर्थिक हालात पहले से ही ठीक नहीं है। सरकारी स्कूलों की भांति प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों का भी टेस्ट फ्री होना चाहिए।

दुकानों से हजारों का सामान चोरी

फरीदाबाद। एक मिठाई की दुकान व एक इलेक्ट्रिकल एवं मशीनरी की दुकान से चोरों ने बीती रात अपना निशाना बना लिया। चोर दुकानों से हजारों रुपये का सामान, नकदी आदि चोरी करके फरार हो गए। दुकानदारों का आरोप है कि चोर छतों के रास्ते से दुकान में घुसे। दुकानदारों की शिकायत पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू करते हुए मामला दर्ज कर लिया है।

मोहना रोड स्थित गुप्ता स्वीट्स के मालिक राम किशन मित्तल ने पुलिस को बताया कि रोजाना की तरह बुधवार की रात वह अपनी दुकान बंद करके गए थे। बृहस्पतिवार सुबह जब वह दुकान पर आए और उन्होंने दुकान खोली तो दुकान में लगी एलसीडी व गल्ले में रखे 12 हजार रुपये नही थे। छानबीन में पता चला कि चोर उनकी छत से दुकान में आए थे। इसी प्रकार उनके पड़ोसी देवेंद्र इलेक्ट्रिकल एवं मशीनरी के मालिक ने बताया कि चोर बुधवार की रात उनकी दुकान की छत से अंदर घुस आए।

कृषि विधेयकों के विरोध में आप का प्रदर्शन

प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री का पुतला फूंक भेजा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

लोकसभा के बाद राज्य सभा में सभी मर्यादाओं को ताक पर बिना बहस पास कराये गए कृषि सबंधी तीन विधेयकों के खिलाफ राज्यसभा सांसद एवं आम आदमी पार्टी हरियाणा के सहप्रभारी डॉ सुशील गुप्ता के नेतृत्व में वीरवार को आम आदमी पार्टी द्वारा बीके चौक पर धरना प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मबीर भड़ाना ने की। डॉ. सुशील गुप्ता ने कहा है कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में सभी नियम कायदों तथा मर्यादाओं को तार तार करते हुए, किसानों की आपत्तियों को नज़र अंदाज कर तथा विपक्ष की आवाज को दबाते हुए बिना वोटिंग के जिस तरह ध्वनिमत एवं धक्के से इन

विधेयकों का पास कराया है वह दुर्भाग्य पूर्ण है। उन्होंने बताया कि राज्य सभा में माननीय सदस्यों ने सदन के उप सभापति से बार बार ये अनुरोध किया था कि इन बिलों पर सदस्यों की वोटिंग कराई जाए लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं कराई, इसलिए ये बिल अवैध है। उन्होंने राष्ट्रपति से इन बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अवैध रूप से ये बिल पास किये गए हैं, इसलिए यह दिन देश के इतिहास में एक काले दिवस के रूप सदैव गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच कर भाजपा सरकार ने किसान विरोधी विधेयक ला कर देश की आत्मा पर घिनोना प्रहार किया है, जिसे देश की जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगी। भाजपा देश को निजीकरण की तरफ ले जाकर पूंजीपतियों के हाथ में देने की गहरी साज़िश का खेल रही है और ये तीनों विधेयक भी उसी साज़िश का हिस्सा हैं तथा इन कृषि विरोधी जैसे काले कानून बना कर व्यापारियों के साथ साथ एवं किसानों को भी पूंजी पतियों का गुलाम बना रही है। जिसे देश कभी भी सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि मंडी व्यवस्था को समाप्त करने का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य का समाप्त होना है। उन्होंने सरकार से जवाब माँगा कि अगर अनाज मण्डी ही समाप्त हो जाएँगी तो छोटे किसानों को एमएसपी कौन देगा और कैसे देगा? क्या एफसीआई 15.5 करोड़ किसानों के खेत से एमएसपी पर फसल खरीद सकेगी? क्या आढ़ती एवं मजदूर किसानों की फसल बेचने में बाधक बन रहे थे? उन्होंने कहा की अगर भाजपा की नीयत किसानों के प्रति ईमानदारी की होती तो इस विधेयकों में एमएसपी का प्रावधान होता तथा किसानों को पूरी कीमत देने की गारंटी होती। उन्होंने राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि राज्य सभा में सदस्यों ने सदन के उप सभापति से बार बार ये अनुरोध किया था कि इन बिलों पर सदस्यों की वोटिंग कराई जाए लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं कराई,जिसके चलते ये बिल अवैध है, इसलिए इन बिलों पर आप अपने हस्ताक्षर न करें तथा तुरंत ही किसानों के लिए आत्मघाती बने इन तीनों बिलों को निरस्त किया जाए और पहले जैसी ही व्यवस्था बहाल की जाए।

सदन में विपक्षी एकता

जमीनी कार्रवाई पर सवाल

जमीनी स्तर पर बदलाव न लाने पर नैतिक विजय महत्वहीन होती है। हालांकि, विपक्ष ने कृषि विधेयकों पर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार द्वारा संसदीय प्रक्रियायें उलटने की शिकायत की तथा राज्य सभा में ध्वनि मत से प्रस्ताव पास कराए, पर अब नए कानूनों को कैसे रोका जा सकता है? राष्ट्रपति से विधेयकों को रोकने या उनको वापस भेजने की उम्मीद नहीं है। यदि थोड़ी देर के मान लिया जाए कि वे ऐसा करते तो भी संशोधनों या बिना संशोधनों के इनको फिर पास कर दिया जाता क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है और बिना चर्चा या सहमति के ध्वनि मत से विवादास्पद विधेयक पास करने का उदाहरण स्थापित हो गया है। राष्ट्रपति किसी समय-सीमा में कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं हैं। इसके अलावा पूरे विपक्ष द्वारा विरोध में सदन का बहिष्कार करने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी ने कई विधेयक पास कराए। इसलिए विपक्षी सदस्य चाहे जितना चीखें-चिल्लाएं पर उनको संसदीय प्रक्रियाओं से कोई राहत नहीं मिल सकती है। जहां तक सड़कों पर संघर्ष का सवाल है, पिछले साल के आम चुनाव ने दिखा दिया है कि व्यापक भाजपा-विरोधी गठबंधन स्वार्थी व क्षेत्रीय हितों में कैसे बिखर जाता है। जब तक यह एकजुट आंदोलन में नहीं बदलता है, तब तक विपक्ष को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चिन्ता की बात है कि उच्च सदन ने तीन प्रमुख श्रम सुधार विधेयक भी पास कर दिए हैं जिनकी संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए उन पर बहस व चर्चा होनी चाहिए थी। तीन विधेयकों का संबंध औद्योगिक संबंधों, सामाजिक सुरक्षा तथा पेशेवर सुरक्षा के बारे में नई श्रम संहिता से है। संभवत: बिजनेस सुगमता के नाम पर कामगारों के अधिकार कमजोर हो रहे

हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सरकार वैश्विक महामारी के बाद वाली अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक कल्याणकारी उपाय करेगी, पर उसने बिना सरकारी अनुमति के 300 कामगारों वाली कंपनियों को कर्मचारियों को निकालने की अनुमति दे दी है। सरकार को लगता है कि इससे सेवायोजक ज्यादा लोगों को काम पर रखने के लिए प्रेरित होंगे जिनकी संख्या पहले 100 निर्धारित थी। लेकिन संकट के समय सेवायोजकों से उदारता की उम्मीद नहीं की जाती है। देश के कार्यबल में असंगठित श्रमिकों की बड़ी संख्या है जो पहले ही बाजार शक्तियों के सामने असहाय हैं। राज्यसभा ने फारेन कांट्रीब्यूशन रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल, 2020 भी पास कर दिया है जो भारत में काम कर रहे संगठनों को विदेशी स्त्रोतों से धन प्राप्त करने व उसके नियमन की व्यवस्था करता है। आशंका है कि सरकार इस कानून के अंतर्गत ऐसे एनजीओ, शाध संगठनों, थिंक टैंकों व सिविल सोसाइटी एक्टिविस्टों पर निगरानी रख सकती है जो उसके पक्ष में न हों। कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि विदेशी स्त्रोतों से की जाने वाली गतिविधियों में ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए, पर इसका प्रयोग चयनित ढंग से 'राष्ट्र-विरोधी' एनजीओ के खिलाफनहीं होना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए आधार व एसबीआई बैंक खातों को अनिवार्य बना कर विधेयक नियंत्रण कठोर करना चाहता है, पर इससे लेनदेन का खर्च बढ़ेगा तथा बाधायें खड़ी होंगी। कृषि संबंधी विधेयक भी सुधारवादी लगते हैं तथा वे कृषि उत्पादन मंडी समितियों-एपीएमसी में मौजूद बड़े कार्टेलों व बिचौलियों का सफाया कर किसानों को आवागमन व व्यापार की स्वतंत्रता देना चाहते हैं। लेकिन किसानों के पास अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर पहुंचने के लिए विशेषज्ञता कैसे आएगी और उनको 'व्यापारियों' या निगमों पर निर्भर होना पड़ेगा। उनको डर है कि खुले प्रतियोगी बाजार में वे एमएसपी से वंचित हो सकते हैं, हालांकि सरकार ने इसे बनाए रखने का वादा किया है। विधेयक में कहीं पर जोर नहीं दिया गया है कि 'व्यापारी' या 'प्रायोजक' कृषि उत्पाद खरीदते समय एमएसपी देने को बाध्य होंगे। ऐसे में अगले चुनावों में किसानों का गुस्सा सामने आ सकता है।

संकट में फंसे शी जिनपिंग

चीनी राष्ट्रपति आर्थिक लक्ष्य पूरा करने में विफल रहे हैं और उनको भारी चुनौती मिल रही है। ऐसे में पीएलए के पीछे हटने को पराजय तथा मजबूत सेना का लक्ष्य विफल होने के रूप में देखा जाएगा।

अनिल गुप्ता
(लेखक सुरक्षा व रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

मॉस्को में पांच बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद पहली बार सैनिक कमांडर स्तर की वार्ता 12 घंटे चली। लेकिन सारे संकेत हैं कि इसकी समाप्ति भी गतिरोध में हुई है। भारत ने अपनी ओर से 29-30 अगस्त को शानदार पूर्व-नियोजित कार्रवाई करते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा-एलएसी के अपनी ओर पैगांग सो के दक्षिणी किनारे के ऊंचे रणनीतिक स्थानों पर उपस्थिति मजबूत की है। इसके बाद उत्तरी किनारे पर रक्षा व्यवस्था मजबूत की गई तथा फिंगर क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित किया जहां चीनियों ने घुसपैठ की थी और वे यथास्थिति बहाल नहीं करना चाहते थे। भारतीय सेना के इन कदमों से भारतीय वार्ताकारों की स्थिति मजबूत हुई और वे शक्तिशाली दृष्टिकोण से बात कर सकते थे। लेकिन चीन अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स व अपने नियंत्रण वाले मीडिया के माध्यम से यह स्थिति स्वीकार करने से इनकार करते हुए उल्टा भारत पर गतिरोध का आरोप लगाता रहता है। चीनी दावों के बावजूद, चीनी राष्ट्रपति व शक्तिशाली नेता शी जिनपिंग को दुनिया भर में आक्रामक समझा जाता है जो दुनिया के सबसे मजबूत व शक्तिशाली नेता बनना चाहते हैं।

भारत का दृष्टिकोण अब तक प्रतिबद्ध, सुसंगत तथा कठोर रहा है। भारत ने 'आधे रास्ते तक आने' का चीनी सुझाव एकदम अस्वीकार कर दिया। उसने लगातार 'पहले आए, पहले जाओ' पर जोर दिया है क्योंकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी-पीएलए सैनिकों ने स्थापित समझौतों व प्रोटोकालों का उल्लंघन कर मई की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख के हमारे क्षेत्र में बहुआयामी घुसपैठ की थी। पीएलए ने 5 जून को कार्प्स कमांडरों की पहली बैठक में तनाव घटाने तथा सैनिक पीछे हटाने के बारे में लिए निर्णयों का पालन नहीं किया जिससे गलवान में संकट की स्थिति पैदा हुई। गलवान टकराव से दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए। इससे भारत तथा दुनिया ने समझ लिया कि यह चीनी सैनिकों का सुनियोजित आक्रमण था जिसे शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले केन्द्रीय सैनिक आयोग-सीएमसी की स्पष्ट अनुमति प्राप्त थी। इसके बाद चीन द्वारा दिखाई जिद से स्पष्ट है कि निसंदेह इस मामले में अंतिम निर्णय शी जिनपिंग के अलावा किसी अन्य ने नहीं लिया था जिनका 'चीनी सपना' और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा दांव पर लगी है।

शी एक कॅरियर राजनेता हैं जो अपने मुंह में 'लाल चम्मच' लेकर पैदा हुए थे। उनके पिता शी झोंगशुन 'लाल शाही' समूह के नायक और कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे जिसका माओत्से तुंग के बाद पतन हो गया। पिता को पद से हटाए जाने के बाद शी जिनपिंग बीजिंग की विशिष्ट जीवनशैली छोड़ कर ग्रामीण क्षेत्र में रहने पर मजबूर हुए। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की युवा शाखा में शामिल होने के लिए संघर्ष किया और बाद में पार्टी ने उनको स्वीकार किया। इस प्रकार 'लाल शाही' में पैदा होने के बावजूद उनको सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करना पड़ा। इससे वे जिद्दी और महत्वाकांक्षी बन गए। उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की और अंतत: उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी-सीपीसी की 'सामूहिक नेतृत्व' व्यवस्था समाप्त कर दी। वे न केवल चीन के तीन सर्वोच्च पदों पर कब्जा करने, बल्कि संविधान में राष्ट्रपति कार्यकाल की सीमा समाप्त कर अनन्त काल तक शासक बनने में सफल हुए। इससे सीपीसी के अनेक नेताओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है और वे सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंच सकते हैं। सभी तानाशाहों की तरह शी के भी अपने देश में ही बड़ी संख्या में विरोधी हैं।

अपनी सत्ता मजबूत करते समय शी ने विचारधारा और राष्ट्रवाद पर जोर दिया। उनका विश्वास है कि चीनी जनता में अन्य चीजों पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभुत्व बना रहेगा। पीएलए की 'थ्री डब्लू' रणनीति का लक्ष्य इस विचारधारा का प्रोत्साहन सुनिश्चित करना है। इस प्रकार पीएलए राष्ट्रीय सेना के बजाय सीपीसी की सेना है। कॅरियर राजनयिकों के बजाय संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग द्वारा शिक्षित कार्यकर्ताओं पर शी की निर्भरता के कारण दक्षिण एशिया व अन्य लक्षित देशों में नियुक्त राजनयिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं। शी ने राजनयिकों को 'वुल्फ वैरियर' बता कर चीनी राजनय को आक्रामक बनाया है। वे स्वयं को अमेरिकी राष्ट्रपति के वर्चस्व को चुनौती देने वाले सर्वाधिक शक्तिशाली चीनी नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति तथा राष्ट्रवाद को समाहित करते हुए शी ने 'चीनी सपने' का रोडमैप पेश किया है।

सेवानिवृत्त कर्नल व लेखक लियू मिंगफू के अनुसार, 'राष्ट्रपति शी का सपना मजबूत सेना वाला मजबूत देश' है। 'चीनी सपने' के पीछे विचार पूर्व-मध्यवर्ती साम्राज्य की गरिमा बहाल कर विस्तारवाद के माध्यम से चीन का वर्चस्व स्थापित करना है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय एकता के माध्यम से आंतरिक विरोध को न्यूनतम करना है। शी चीन को न केवल मजबूत, बल्कि आक्रामक भी बनाना चाहते हैं। यह वर्ष 2049 तक 'चीनी सपना' पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना का शताब्दी वर्ष होगा। इसमें 2021 व 2025 भी महत्वपूर्ण वर्ष हैं। 2021 में सीपीसी की सौवीं वर्षगांठ होगी। शी ने वादा किया था कि 2020 तक देश सभी चीनियों को गरीबी रेखा से ऊपर ला कर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा व सशस्त्र सेनाओं को मजबूत कर गरीबी उन्मूलन कर देगा।

लेकिन चीनी अर्थव्यवस्था में 2019 में ही गिरावट दिखने लगी थी और यह लगभग तीन दशक में सबसे धीमी हो गई थी। कोविड-19 महामारी के बाद शी समझ गए हैं कि वे 2020 के आर्थिक लक्ष्य पूरे नहीं कर सकेंगे। चीन के बड़बोलेपन के बावजूद निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था संकट में है। बैंकिंग पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है, बेरोजगारी बढ़ रही है तथा वैश्विक सप्लाई श्रृंखला टूटने से दबाव बढ़ा है। चीजें स्वाभाविक स्थिति में होने पर कामों का केन्द्रीकरण ठीक रहता है। लेकिन संकट के समय में अनेक विरोधी विचार भी सामने आते हैं। अपने देश में शी को इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। चीन में बिना उनकी सहमति या अनुमति के कुछ भी नहीं चलता है। अत: शी स्पष्ट रूप से गरीबी उन्मूलन का अपना लक्ष्य पाने में विफल रहे हैं और उनकी सत्ता को भारी चुनौती मिल रही है। ऐसे में पीएलए के पीछे हटने को चीन की पराजय के रूप में देखा जाएगा तथा मजबूत सेना का दूसरा लक्ष्य संदिग्ध हो जाएगा।

शी इस मोड़ पर जोखिम लेकर पीछे नहीं हट सकते हैं। इसी कारण चीनी मीडिया जाड़े में 'लांग हाल' की बात कर रहा है। शी का गणित इस अनुमान पर आधारित है कि लंबी सैनिक तैनाती का चीनी अर्थव्यवस्था के बजाय भारतीय अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उनकी सोच गलत है। भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए एकजुट है और वह घुसपैठ वाले क्षेत्रों से चीन के पीछे हटने तक शांत नहीं होगा। दूसरी ओर शी को अपने देश में बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

पीएलए की अजेयता के बारे में राज्य-नियंत्रित चीनी मीडिया के प्रचार के बावजूद शी विजय के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। एक गतिरोध को भी भारत की विजय तथा चीन की विफलता के रूप में देखा जाएगा। चीन में ऐसे विरोधियों की कोई कमी नहीं है जो उनकी विफलता की प्रतीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनको दूसरा मौका न मिले। शी के सामने झुकने या पीछे हटने का द्वंद्व है। महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व को देखते हुए स्पष्ट है कि शी आसानी से अपने विरोधियों के सामने नहीं झुकेंगे। इस्तीफा देने के लिए मजबूर किए जाने के बजाय वे उपयुक्त समय पर झुकने व पीएलए को पीछे हटने का आदेश देना ज्यादा पसंद करेंगे। वार्ताओं और समय पर निर्भर है कि यह कैसे और कब होगा। इस बीच भारत को किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनरीक्षण की आवश्यकता

कल्याणी शंकर
(लेखिका वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार एवं स्तम्भकार हैं)

अगले महीने संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। यह सापेक्षत: एक युवा संगठन है लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण जन्मदिन अर्थ है कि अब इसके पुनरीक्षण का समय आ गया है। अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी संरचना को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत यह अस्तित्वमान हुआ था, जिसमें भारत समेत 50 देशों ने भाग लिया था। तब से यह फला-फूला है और आज संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 193 है। इसके अतिरिक्त, आज का संयुक्त राष्ट्र 75 वर्ष पूर्व के संयुक्त राष्ट्र की तुलना में व्यापक रूप से भिन्न है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विश्व निकाय ने अपनी भूमिका का उचित ढंग से निर्वहन किया है अथवा यह अप्रासंगिक हो गया है? संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव स्वर्गीय डैग हैमर्सकजोल्ड, जिनका एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, ''मनुष्य को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए हुआ है।''

रोचक ढंग से, जो लोग संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करते हैं उनका मानना है कि इस विश्व निकाय ने कुल मिलाकर अपना उद्देश्य पूर्ण किया है। तथ्य यह है कि उतार-चढ़ावों के बावजूद यह कायम हे, सफलता को दर्शाता है। वे उल्लेख करते हैं कि पिछले 75 वर्षों के दौरान कोई नाभिकीय युद्ध नहीं हुआ है। अन्य लोग संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना मिशनों की सराहना करते हैं। वे इसके सतत विकास कार्यक्रमों की भी सराहना करते हैं। लेकिन विविध कारणों से प्रभावी न हो पाने के कारण संयुक्त राष्ट्र की आलोचना भी होती है। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में कुछ स्वेच्छाचारी शासकों ने निरपराध नागरिकों के खिलाफ परम्परागत हथियारों का प्रयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव अबाध्यकारी होते हैं। विश्व निकाय से संघर्षों व युद्ध को रोकने की अपेक्षा की जाती हे और फिर भी उसके प्रादुर्भाव के बाद से 80 संघर्ष हो चुके हैं। पिछले तीन दशकों में, बुश से लेकर ट्रंप तक, अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली को लेकर उसकी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र संसाधनों के अभाव से भी जूझ रहा है क्योंकि अमेरिका समेत सभी सदस्य समय से अपना योगदान नहीं देते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत का जुड़ाव उल्लेखनीय है। संस्थापक सदस्य के तौर पर, संयुक्त राष्ट्र अधिकार प्रपत्र के लक्ष्यों व कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में नई दिल्ली का योगदान प्रचुर मात्रा में रहा है। यह बहुत से संयुक्त राष्ट्र निकायों में संलिप्त रहा है और भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी समिति का वर्तमान अध्यक्ष है। भारत अब महिला प्रस्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य 2021 से 2025 तक बना है।

भारत जून में दो वर्षों के लिए शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर-स्थायी सदस्य चुना गया था और दो वर्ष के आठ कार्यकाल पहले भी पूर्ण कर चुका है। नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए लाबीइंग कर रही है और उसमें स्थान प्राप्त करने का दावा भी पेश किया है। कई वर्षों से, जब कभी भी हमारे किसी प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा की अथवा किसी राज्य के प्रमुख भारत आए, तो एक मुद्दा जो हमेशा उठाया जाता रहा है वह है विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अभ्यर्थन का समर्थन प्राप्त करना। हालांकि, सुधारों का आगाज़ विविध कारणों से नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए, प्रथम पांच सदस्य अपनी वीटो शक्ति को खोने के लिए तैयार नहीं हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने शांति सेनाओं में भारत के योगदान की सराहना की है क्योंकि यह उपनिवेशवाद एवं रंगभेद के अंत एवं वैश्विक निशस्त्रीकरण एवं आतंकवाद की समाप्ति जैसे बहुत से मुद्दों के पीछे एक वाहक शक्ति बनकर काम करता रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुधारों का प्रबल हिमायती है। शुरुआत में नई दिल्ली का परिषद का सदस्य बनने की कोई इच्छा नहीं थी। हालांकि, जब, महासभा ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए कदम बढ़ाया, जापान, जर्मनी और ब्राजील ने विस्तारित सुरक्षा परिषद में सदस्यता की मांग की। भारत भी इस मांग का हिस्सा बन गया। हालांकि, कई यूरोपीय सदस्यों ने जर्मनी के दावे पर आपत्ति जताई, अर्जेंटीना ने ब्राजील का और पाकिस्तान ने भारत का विरोध किया, आदि। उसके पश्चात, चार देशों ने मिलकर काम करने के लिए ब्रिक्स का गठन किया।

एक सवाल जो आज की परिस्थितियों में बार-बार पूछा जा रहा है वह यह कि संयुक्त राष्ट्र का भविष्य क्या है? कुछ देश चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व के मामलों में बड़ी भूमिमा अदा करे, जबकि अन्यों की इच्छा है कि उसकी भूमिका विशिष्ट रूप से मानवीय कार्यों पर केंद्रित रहे। व्यवस्था को सुधारना एवं व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं धन प्राप्त करना संयुक्त राष्ट्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। लगभग नब्बे के दशक के पूर्वार्द्ध से, सुधारों की बातें की जाती रही हैं मगर इस बाबत कोई प्रगति नहीं हुई है, जो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र को आधुनिकीकृत किए जाने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि वर्तमान ढांचा दोषपूर्ण है और बहुत से कार्यक्रम प्राय: बनावटी होते हैं। तीसरे, यह भावना बढ़ती जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र को मजबूत किया जाना चाहिए। विश्व निकाय में गलत काम करने वाले सदस्यों से निबटने के लिए और अधिक शक्तियां समाहित की जानी चाहिए।

चौथे, संयुक्त राष्ट्र के वित्त पोषण को किसी भी वजह से रोका नहीं जाना चाहिए क्योंकि विश्व निकाय को स्वतंत्र रहने दिया जाना अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र नकदी, वस्तुएं एवं सेवाओं के लिए अपने सदस्य देशों द्वारा किए जाने वाले वित्तीय एवं मदद पर आश्रित है। कर्मचारियों की संख्या को कम करने की आवश्यकता है। जैसा कि दि गार्जियन समाचार पत्र ने कुछ समय पूर्व उल्लेख किया था, ''85,000 नौकरशाह, 40 अरब डॉलर के वार्षिक खर्चे, जो 1946 में संगठन के बजट का 2,000 गुना है। पिछले 20 वर्षों में खर्च चौगुना बढ़ गया है और अभी भी, कुछ अभिकरण इस बात संघर्ष में लगे हैं।'' हालांकि, सभी शिकायतों एवं आलोचनाओं के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र वर्तमान समय में एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था संस्था है जहां राज्यो के मुखिया महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हो सकते हैं तथा विश्व की समस्याओं का निराकरण करने हेतु सदस्य देश एकजुट होकर काम कर सकते हैं। कुलमिलाकर संयुक्त राष्ट्र एक मिश्रण है और उसके सदस्यों का काम है उसे प्रभावी बनाना। इस स्थिति में, संयुक्त राष्ट्र को ध्वस्त करने के बजाए उसे सुधारने की जरूरत है।

आप की बात

दिल्ली में बढ़ता संक्रमण

एक समय कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की मिसाल बन रही दिल्ली इस समय फिर संक्रमण की तेज रफ्तार की चपेट में है। लगातार बढ़ रहे मामलों से सरकार सतर्क और निश्चिंत हैं, तो वह सामुदायिक संक्रमण की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही हैं। अगर जल्द ही इस ओर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। कभी कोरोना को पछाड़ने और देश-विदेश में मॉडल बनी दिल्ली फिर कोरोना वायरस के गड्ढे में गिरती दिख रही हैं। प्रतिदिन आ रहे संक्रमण के बड़े आंकड़ों से सरकार की नींद हराम होती जा रही हैं। उस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान कि जिस तरह से दिल्ली में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा हैं, उसे देखते हुए सामुदायिक संक्रमण से इंकार नहीं किया जा सकता निश्चित रूप से यह बयान ताजा हालातों में ठीक ही हैं। दिल्ली के प्रति 100 में से 10 व्यक्ति संक्रमित निकल रहे हैं। अब तक दिल्ली में 2,38828 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 21प्रतिशत मृत्यु दर हैं जो देश की मृत्यु दर से 1.6 अधिक हैं। दिल्ली में बढ़ी हुई मृत्यु दर भी चिंता का विषय हैं। राज्य के साथ केंद्र सरकार भी ठोस उपाय करे जिससे हालात बिगड़ने से रोका जा सके।

- **अमृतलाल मारू,** दसई, मप्र

दोषियों को सजा मिले

ऐसा कहा जाता रहा है कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती है और उसमें कार्य करने वाले कलाकार अपने किरदार से समाज के लोगों को प्रभावित करते हैं। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो बालीवुड में जिस तरह की फिल्में अब बनती है, फूहड़ता और अश्लीलता की जो चरम सीमा का चित्रण फिल्मों में किया जाता है, वो समाज का आईना नहीं बल्कि समाज को एक गलत दिशा में ले जाने का एक दूषित प्रयास है। भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बड़ी भावुकता से इन कलाकारों के साथ हृदय से जुड़ जाता है, उन कलाकारों को अपना आदर्श तक समझने लगता है। परन्तु वहीं कलाकारो के जब वास्तविक जीवन के चरित्र का खुलासा होता है तो वह दर्शक अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। जब से सुशांत राजपूत के केस में ड्रग्स के काले बाजार का एक नया मोड़ आया है और जिस तरह से आये दिन ड्रग्स के सेवन करने वालों की कड़ी दिन पर दिन खुलती जा रही है मानो लगता है पूरा का पूरा बालीवुड ही इस नशे की चपेट में हैं, वो फिर चाहे नये कलाकार हो या पुराने, कोई भी इससे अछूता नहीं है। खुलासा निष्पक्ष होकर करना चाहिए जिससे सभी की असलियत समाज को पता हो सके और इन सभी को उचित दण्ड मिले।

- **अभिनव दीक्षित,** बांगरमऊ

विरोध का दमन

आज की व्यवस्था में किसी भी मुद्दे या समस्या पर विरोध करना या आवाज उठाना भारी पड़ता जा रहा है। नोएडा में सफाई कर्मियों को हटाने के नोटिस दिए जाने के बाद सभी सफाई कर्मियों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध करने व उनकी समस्याओं को सुनने की बजाय सफाई कर्मियों को पुलिस की लाठियां खाने को मिली। नौकरी से निकाले जाने के भय से एक सफाई कर्मी ने खुदकुशी कर ली। बिल के विरोध में किसान सड़क पर है तो उन्हें भी लाठियों से ठोका पीटा गया यानी बातचीत व संवाद का उपक्रम इस कोरोना काल में बंद हो गया है या जमींदोज कर दिया गया है। पिछले कुछ समय से यह ट्रेंड देखने में आया है कि बहुमत में मगरूर हो कर जो भी करना है वो कर दो लेकिन विरोध करने वालों की एक ना सुनो। अगर ज्यादा विरोध करते हैं तो पुलिस की लाठियां तैयार है । आजकल तो बिना वर्दी वाले बाउंसर भी मोर्चा संभालने लगे हैं । चाहे जो हो सरकार का फर्ज है कि वह जो भी कानून बनाए, नियम बनाएं जनता को पूरी तरह संतुष्ट करना चाहिए लेकिन नहीं किया जा रहा है।

- **विषधर खरा,** उज्जैन

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

फरमाया

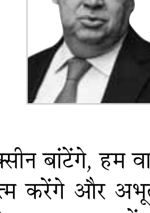

हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकासशील जगत बर्बादी, निर्धनता वृद्धि एवं ऋणग्रस्तता के भंवर में न डूबने पाए।

- **एंटोनियो गुटरेस**
संयुक्त राष्ट्र महासचिव

हम वैक्सीन बांटेंगे, हम वायरस को हराएंगे, महामारी को खत्म करेंगे और अभूतपूर्व समृद्धि, सहयोग एवं शांति के एक नए युग में प्रवेश करेंगे।

- **डोनाल्ड ट्रंप**
अमेरिकी राष्ट्रपति

अर्थव्यवस्था की तरह स्वास्थ्यरक्षा के क्षेत्र में भी अब हमें साझीदारी संबंधों में आने वाले अवरोधों को समाप्त करने की आवश्यकता है।

- **व्लादिमीर पुतिन**
रूस के राष्ट्रपति

तकनीक से जुड़कर चुनौतियों का सामना करें: योगी

सीएम ने लांच किया यू-राइज पोर्टल, 20 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं होंगे लाभान्वित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र में समानता से समरस समाज का सपना साकार होगा। भविष्य की जरूरतों के लिहाज से शिक्षण संस्थानों में और शिक्षा के सभी चरणों में एक सहज एकीकरण और समन्वय होना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को उनके सीखने की क्षमता के अनुसार विकल्पों को चुनने का अवसर मिलेगा। वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार सफलता हासिल कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने यू-राइज़ पोर्टल के लान्च तथा दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत चेक वितरण एवं नवीन कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये कहा कि यू-राइज पोर्टल एक यूनिफाइड पोर्टल है। यह पोर्टल प्राविधिक, व्यावसायिक व कौशल विकास से जुड़े छात्र-छात्राओं के साथ ही उनके जितने भी विशेषज्ञ हैं, उन सबको एक प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहा है। इसमें विद्यार्थियों के जीवन चक्र को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश के तकनीकी संस्थाओं के उन्नयन की दृष्टि से दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का जो शुभारम्भ किया गया था उसके दूसरे चरण के इस अभियान के साथ आज हम जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 आजादी के बाद शिक्षा क्षेत्र में सुधार का सबसे बड़ा अभियान है। यह हमें केवल सैद्धान्तिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि यह छात्र-छात्राओं को व्यावहारिक व तकनीकी ज्ञान से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब तकनीक से जुड़कर ही आगे बढ़ सकते हैं और बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तकनीक जीवन में कितना परिवर्तन ला सकती है, कोरोना काल खण्ड में इस बात को हम सभी ने महसूस किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। बहुत सारे लोगों ने फर्जी डिग्री लेकर नौकरियां हासिल कर ली। वर्षों से यह मामला चलता आ रहा था। तकनीक के माध्यम से उन्हें ट्रैक करके उन लोगों पर समुचित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यू-राइज पोर्टल के माध्यम से किसी भी छात्र-छात्रा के बारे में किसी संस्था या संस्थान को जानकारी प्राप्त करना हो तो वह आसानी से प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से 20 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यू-राइज पोर्टल किसी भी विद्यार्थी के पूरे जीवन चक्र को लेकर चल रहा है। विद्यार्थी के प्रवेश, उनके पाठ्यक्रम, प्रैक्टिकल, शुल्क, परीक्षा व परिणाम को प्रस्तुत करने के साथ ही, आने वाले समय में उनके रोजगार एवं नौकरी को भी इससे जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर तकनीक नहीं होती तो इस सदी की सबसे बड़ी कोरोना महामारी मानवता के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर देती। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से ही बिना भ्रष्टाचार के लाभार्थी को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। उन्होंने जनधन खाते का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोगों को डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड.19 के कारण पिछले 6 महीनों से शिक्षण संस्थान बन्द चल रहे हैं। इस दौरान भी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। यह भी तकनीक से ही सम्भव हुआ है। तकनीक को लेकर लोगों में नई रुचि देखने को मिली है। लोग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो समाज के लिए एक अच्छा संकेत है। पोर्टल लांचिंग के मौके पर मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के दूसरे चरण में 100 करोड़ भी जारी किए। कोविड.19 महामारी के दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अंतर्गत द्वितीय चरण में जारी यह राशि प्रदेश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों में डिजिटल और फिजिकल इन्फ्रा के विकास पर खर्च होगी। इस धनराशि से छात्रावासों का निर्माण, क्लास रूम, लैब, नवनिर्मित भवन के फर्नीचर, पुस्तकालय का विस्तार, कोविड के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं का विनिर्माण एवं ऑनलाइन क्लासेज, स्मार्ट क्लास रूमएवर्चुअल लैब आदि खरीदे जाएंगे।

इस मौके पर वर्चुअल प्लेटफार्म से व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व विभिन्न संस्थानों के प्रमुख ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा एस राधा चौहान, कुलपति एकेटीयू विनय कुमार पाठक, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पहली फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोलने के प्रयासों में तेजी लाएं: सीएम

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

- कुलपति, कुल सचिव व वित्त अधिकारी के पदों का हुआ सृजन, निर्माण कार्यों के लिए दी गयी 20 करोड़ रुपए की धनराशि

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस की विवेचना में वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित साक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में एक ओर जहां विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को और अधिक सुदृढ़ कर उनकी क्षमता का विस्तार किया जा रहा है, वहीं प्रदेश की पहली फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, लखनऊ में खोलने की दिशा में कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में और अधिक तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में फोरेंसिक साइंस, आचार विज्ञान, प्रोद्योगिकी और प्रबन्धन के क्षेत्र में अभिनव शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने के उद्देश्य में फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी शासन के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त कार्रवाई चल रही है । इसके निर्माण से आपराधिक मामलों की जांच, प्रबन्धन एवं संचालन में आवश्यक प्रोद्योगिकियों में विशेषज्ञता उत्पन्न होगी तथा प्रोद्योगिकीय सम्बन्धी कार्यों में दक्ष जनशक्ति भी प्राप्त हो सकेगी। जिससे विवेचना की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को लोक भवन में इस संबंध में अब तक हुई कार्रवाई की गहन समीक्षा हुई। समीक्षा में जानकारी दी गयी कि लखनऊ जनपद की तहसील सरोजनीनगर के ग्राम पीपरसण्ड में खुलने वाले इस फोरेंसिक साईस विश्वविद्यालय के लिए कुलपति, कुल सचिव एवं वित्त अधिकारी के पदों का सृजन कर दिया गया है। साथ ही शासन द्वारा विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों के लिए 20 करोड़ उपाय की धनराशि भी मंजूर की जा चुकी है। बैठक में जानकारी दी गई कि अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं संदीप सालुंके को इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है तथा अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टेयरिंग कमेटी का भी गठन किया जा चुका है । इस स्टेयरिंग कमेटी के लिए दो फोरेंसिक विशेषज्ञ क्रमशः डा.एके बापुली चीफ फोरेंसिक साइंटिस्ट, डीएसएफ रॉची, झारखण्ड एवं डा. दीपा वर्मा निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को नामित किया गया है। अवस्थी ने बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए डा. एपीजे अब्दुल कलाम, प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से भी सहयोग एंव सहकार्य के लिए एमओयू किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है । साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु इजराइल देश से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है ।

आपदा में मरने वालों को चार-चार लाख की मदद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, मऊ, प्रतापगढ़ तथा सुलतानपुर में आपदा से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिए हैं कि वे अपने जनपद में फसलों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन करते हुए शासन को अविलम्ब आख्या उपलब्ध कराएं। ज्ञातव्य है कि अम्बेडकर नगर में आकाशीय बिजली से 1, गाजीपुर में सर्पदंश से 1, दीवार गिरने से 2, मऊ में आकाशीय बिजली से 1, प्रतापगढ़ में दीवार गिरने से 1 तथा सुल्तानपुर में दीवार गिरने से 1 मौत हुई है।

कृषि सुधार विधेयकों को लेकर विपक्ष फैला रहा भ्रम: स्वतंत्र देव

पायनियर समाचा सेवा। लखनऊ

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार विधेयकों को किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कृषि सुधार विधेयकों को लेकर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों द्वारा किये जा रहे विरोध को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही देश के किसानों को कानून के नाम पर जकड़े रखा।

कांग्रेस ने आज तक तो किसानों के हित में कोई फैसला लिया नहीं और आज जब कृषि सुधार पर फैसले लिए जा रहे है तो किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार चाहती है कि किसान अपनी भूमि को पूंजीपतियों को बेच दे जबकि तथ्य यह है कि किसानों को इन विधेयकों में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है किसानों की भूमि की बिक्री या गिरवी रखना पूर्णतः निषिद्ध है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को सशक्त करने के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। 55 साल में एक बार कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने की योजना बनाई और उसमे भी बड़ा घोटाला किया। कांग्रेस के पास कृषि व्यवस्था में कोई भी सुधार करने की न तो नीयत थी न ही कोई इच्छाशक्ति।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह विधेयक 70 वर्षो से हमारे अन्नदाताओं के होने वाले शोषण को समाप्त कर एक नई व सुगम व्यवस्था को स्थापित करेंगे। पूर्व में किसानों को अपनी फसलों का भुगतान लेने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वहीं हाल ही में पारित हुए विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक व्यापारी को उसी दिन या अधिकतम तीन कार्य दिवसों के भीतर ही किसान की फसल का भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध कराएंगे जहा किसी भी विवाद व समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में किसान तुरंत अपने स्थानीय एसडीएम के पास जा कर अपनी समस्याओं का निवारण करा सकेगा। बकाया राशि होने की स्थिति में किसानों की जमीन पर किसी भी तरह की कार्यवाही करने का अधिकार यह विधेयक नहीं देता है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस द्वारा किये जा रहे विरोध पर पलटवार करते हुए कि आश्चर्य की बात तो यह है कि 2013 में खुद राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के शासन वाले 12 राज्य फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी ही इस एक्ट में बदलाव का विरोध कर रही है। यहां तक कि यदि हम कांग्रेस का वर्ष 2019 का घोषणा पत्र पढेंगे तो उसमे उन्होंने स्पष्ट रूप से 11 वें बिंदु में एपीएमसी को हटाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम से किसानों को एपीएमसी की जकड़ से आजाद करेगा।

दीन दयाल की जयंती पर बीजेपी आज करेगी विविध कार्यक्रम

लखनऊ। बीजेपी शुक्रवार 25 सितम्बर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयन्ती को बूथ स्तर पर मनाएगी। पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय की जयन्ती से गांधी जयन्ती 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को विभिन्न प्रकार के संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाएगी। दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर 26 से 27 व 28 सितम्बर को जिला स्तर पर वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया जाएगा जबकि 29 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक आत्मनिर्भर भारत के पैकैज के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित अलग-अलग श्रेणी के प्रदेश स्तरीय 8 वेबिनार आयोजित किये जाएगें। दो अक्टूबर को गांधी जयन्ती के दिन भी पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धाजंलि देंगे।

फर्रुखाबाद हादसे में घायलों के उपचार के निर्देश

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बोरवेल के सफाई कार्य में हुई दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस हादसे में घायल मजदूरों का समुचित उपचार सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं।

किसानों को विश्वास में लेकर केंद्र काम करता तो बेहतर होता: मायावती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

किसानों से जुड़े तीन अहम अध्यादेश भले ही संसद के दोनों सदनों से पास हो गए लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां बिल के खिलाफ राजनीतिक दल बयानबाजी कर रहे हैं। वही बिल से जुड़े आशंकाओं को लेकर किसान भी आंदोलित है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र किसानों को विश्वास में लेकर काम करता तो बेहतर होता। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि जैसाकि विदित है कि बीएसपी ने यूपी में अपनी सरकार के दौरान कृषि से जुड़े अनेकों मामलों में किसानों की कई पंचायतें बुलाकर उनसे समुचित विचार विमर्श करने के बाद ही उनके हितों में फैसले लिए थे। यदि केन्द्र सरकार भी किसानों को विश्वास में लेकर ही निर्णय लेती तो यह बेहतर होता।

विद्युत दरों के स्लैब परिवर्तन को लेकर नियामक आयोग में हुई सुनवाई

लखनऊ। बिजली दरों की स्लैब में परिवर्तन को लेकर विद्युत नियामक आयोग में गुरूवार को हुई सुनवाई में बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के सवालों का जबाव नहीं दे पाई। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने जनता टैरिफ लागू करते हुए बिजली दरों में 16 प्रतिशत कमी करने की वकालत की है। गुरूवार को हुई सुनवाई में दक्षिणांचल, पश्चिमांचल व केष्कों कम्पनी के उपभोक्ताओं व सम्बन्धित कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक व निदेशकगण सहित वरिष्ठ अभियन्ता शामिल हुए। तीनों बिजली कम्पनियों द्वारा अपनी-अपनी कम्पनी का एक प्रस्तुतीकरण किया गया उसके बाद प्रदेश के विद्युत उपभोगताओं की तरफ से अपनी बात रखते हुए उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा की उपभोगता परिषद द्वारा प्रदेश के विद्युत उपभोगताओं बिजली दरों में 16 प्रतिशत कमी किये जाने सहित घरेलू बिजली उपभोगताओं के फिक्स चार्ज समाप्त करने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के मिनिमम गारण्टी चार्ज समाप्त करने की बात कही है। परिषद ने कहा कि जब प्रदेश की विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कम्पनियों पर लगभग 13337 करोड़ निकल रहा है ऐसे में उसका लाभ आयोग को दरों में कमी करके उपभोक्ताओं को देना चाहिए।

अनलॉक में सामाजिक दूरी के निरीक्षण की व्यवस्था नहीं: रालोद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता सुरेन्द्र नाथ त्रिवेदी ने वैश्विक महामारी कोरोना के कारण प्रदेश में चरमराती हुई शिक्षा व्यवस्था के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा है कि अनलॉक के प्रथम चरण से लेकर अब तक स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों को छोड़कर लगभग सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान फैक्ट्रियाँ, बाजार और पर्यटन स्थलों को भी आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इन सभी स्थानों पर सामाजिक दूरी का सर्वथा अभाव देखने को मिल रहा है क्योंकि इस प्रकार के निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से जनता को जागरूक ही किया जा रहा है।

त्रिवेदी ने कहा कि स्कूल और कालेज बंद होने से बच्चों की शिक्षा निश्चित रूप से प्रभावित हो रही है तथा यूपी बोर्ड के सरकारी एवं वित्तीय सहायता प्राप्त कालेजों की शिक्षा व्यवस्था पूर्व में भी गुणवत्तापरक नहीं रही है। आनलाइन शिक्षण व्यवस्था सरकारी स्कूलों और कालेजों के छात्रों के लिए संतोषजनक नहीं है। स्कूल और कालेजों को सशर्त खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए क्योंकि इनमें सामाजिक दूरी का निरीक्षण करने के लिए प्रधानाचार्य के साथ अध्यापक, अध्यापिकाएं और अन्य कर्मचारी भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि बेसिक शिक्षा अधिकारियों और जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा कक्षाओं को दो या तीन पालियों में विभाजित करके कक्षाएँ चालू कर दी जाय तो बच्चों का इतना नुकसान न होगा। यद्यपि वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। एक भी सत्र में समय से छात्रों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध न कराना प्रमाण के लिए काफी है। उन्होंने बताया कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्डों से प्रतिस्पर्धा के कारण यूपी बोर्ड का कोर्स और परीक्षण व्यवस्था अवश्य तहस नहस कर दी गई जबकि यूपी बोर्ड एशिया में सबसे अच्छा बोर्ड था। वर्तमान महामारी के समय यूपी बोर्ड की कक्षाएँ आनलाईन शिक्षण में अन्य बोर्डों से पिछड़ गईं। रालोद प्रवक्ता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से माँग करते हुए कहा कि वे इस सन्दर्भ में भी शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से डूबती हुई शिक्षा व्यवस्था को बचाने का प्रयास करें ताकि बच्चों का भविष्य अन्धकार के गर्त में जाने से बच सके।

सात जेल अधीक्षकों के तबादले

लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार ने बृहस्पतिवार को सात जेल अधीक्षकों के तबादले कर दिए। आदर्श कारागार लखनऊ के वरिष्ठ अधीक्षक आरएन पाण्डेय को केन्द्रीय कारागार बरेली का वरिष्ठ अधीक्षक बनाया गया। एसपी त्रिपाठी को जिला जेल चित्रकूट में ही कारापाल से कारागार अधीक्षक के रूप में प्रमोट किया गया। अशोक सागर को केंद्रीय कारागार बरेली से जिला कारागार कासगंज में कारागार अधीक्षक बनाया गया। हर्षिता मिश्रा को जिला कारागार बरेली से जिला कारागार अम्बेडकरनगर का अधीक्षक बनाया गया। एसके पाण्डेय को जिला कारागार रामपुर से जिला कारागार जौनपुर का अधीक्षक बनाया गया। डा. विनय दुबे को जिला कारागार बलिया से जिला कारागार बदायूं का अधीक्षक बनाया गया। लाल रत्नाकर सिंह को जिला कारागार हरदोई से जिला कारागार बिजनौर के पद पर भेजा गया।

जेपी कन्वेंशन सेन्टर बेचने का प्रस्ताव बनाने वाले हिमालय भी बेच सकते हैं: रामगोविन्द

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी ने कहा है कि जो लोग जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर को भी बेचने का प्रस्ताव बना सकते हैं, वह मौका मिला तो हिमालय की भी प्लाटिंग करके बेच सकते हैं। देश और प्रदेश के लोगों को ऐसे लोगों और सबकुछ बेच देने पर आमादा उनकी टीम से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके समर्थक इस तरह के देश विरोधी कुकृत्य का हर स्तर पर विरोध करेंगे, इसलिए उनकी आवाज को दबाने के लिए नव गठित फोर्स को वह सब अधिकार दिये गए हैं, जो हिटलर की सीक्रेट पुलिस को हासिल था।

बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य का हालचाल लेने आए समाजवादी साथियों से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमन्त्री कार्यकाल में जेपी की स्मृति में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जो अद्भुत है। इस सरकार ने इसमें खुद तो कुछ किया नहीं, अब इसे बेचने की साजिश भी रच रही है जो किसी कीमत पर क्षम्य नहीं है। चौधरी ने कहा है कि जेपी कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। इसकी रक्षा के लिए इस राष्ट्र के सभी दलों के लोगों को आगे आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को भी आगे आना चाहिए जिनकी आस्था लोकतन्त्र और जेपी में है।

भाजपा सरकार ने आसान कर दिया अत्याचार करना: प्रियंका गांधी

लखनऊ। केंद्र की मोदी सरकार के श्रम सुधार से जुड़े तीन विधेयकों को लेकर बृहस्पतिवार को कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि भाजपा सरकार ने अत्याचार करना आसान कर दिया है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि इस कठिन समय की मांग है कि किसी की नौकरी न जाए। सबकी आजीविका सुरक्षित रहे। भाजपा सरकार की प्राथमिकता देखिए, भाजपा सरकार अब ऐसा कानून लाई है जिसमें कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान हो गया है। वाह री सरकार आसान कर दिया अत्याचार। प्रियंका ने इसके साथ ही किसान बिल को लेकर भी एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भाजपा के कृषि बिल के पहले एमएसपी , किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिल पास हो जाने के बाद एमएसपी, पूंजीपतियों के लिए मैक्सिमम सपोर्ट इन प्रॉफिट। आखिरकार किसान कहां जाएगा।

अब जेल कर्मी बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होकर करेंगे ड्यूटी

- पायलट प्रोजेक्ट के तहत चार राज्यों के लिए राष्ट्रपति ने मंजूर की आवश्यक धनराशि, यूपी को मिले 80 लाख
- बंदियों की मन:स्थिति समझने में मदद मिलेगी
- इससे प्राप्त फीड का मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, विधि-फॉरेंसिक विशेषज्ञों और जेल सुधार विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा विश्लेषण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राष्ट्रपति द्वारा भारत के चार राज्यों राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब और उत्तर प्रदेश की जेलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत बॉडी वॉर्न कैमरा के लिए आवश्यक धनराशि मंजूर कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश को इस कार्य के लिए 80 लाख रुपए मिलेंगे। इस धनराशि से उत्तर प्रदेश की जेलों में विरुद्ध बन्दियों के कार्यव्यवहार की रिकॉर्डिंग के लिए वीडियो कैमरे, डिस्प्ले यूनिट्स, वीडियो प्रोडक्शन करने के उपकरण, शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाने और उनका विश्लेषण करने के लिए जरूरी उपकरण खरीदे जाएंगे। इनसे प्राप्त विजुवल्स का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए

मनोवैज्ञानिकों, मनश्चिकित्सकों, विधि फॉरेंसिक और जेल सुधार विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी।

जेल के स्टाफ यह कैमरे ड्यूटी के दौरान अपने शरीर पर धारण करेंगे और इससे प्राप्त फीड का मनोवैज्ञानिकों, मनश्चिकित्सकों, विधि फॉरेंसिक विशेषज्ञों और जेल सुधार विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण किया जाएगा। इससे जेल में निरुद्ध बंदियों की मन:स्थिति समझने में मदद मिलेगी। इन विशेषज्ञों द्वारा जेल में बन्दियों के व्यवहार का अध्ययन करके सुझाए गए उपायों का उपयोग बन्दियों को अपराध से दूर करने के लिए प्रेरित करने में किया जाएगा।

जेल में मिलने आने वाले बंदियों के परिजनों और शुभचिंतकों को इन कैमरों से प्राप्त वीडियो दिखाया जाएगा जिससे कि वे बन्दियों को अपराध की दुनिया से दूर करने के प्रयासों में जेल प्रशासन की मदद कर सकें और बन्दियों को अपराध से दूर रहने हेतु प्रेरित और उत्साहित कर सकें। चूंकि जेल का स्टाफ बॉडी वॉर्न कैमरा धारण करके ऐसे सभी स्थानों पर ड्यूटी करेगा जहां पर बंदीगण उपस्थित रहते हैं और विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे कि जेल की फैक्ट्रियां, जेल के मुलाकात स्थल, जेल अस्पताल बैरकें आदि। ऐसे में ये कैमरे जेल में बन्दियों द्वारा की गई हिंसक आपराधिक कार्रवाई उपद्रव, नशे की समस्या आत्महत्या और जेल की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का निदान सुझाने और रोकने में बेहद मददगार साबित होंगे। जेल स्टाफ ड्यूटी पर आने के बाद इन कैमरों को धारण करेगा और तत्काल ऑन कर लेगा एक बार ऑन होने के बाद ये बॉडी वॉर्न कैमरे उस कर्मचारी की ड्यूटी समाप्ति के समय ही बंद किए जाएंगे। विशेष परिस्थितियां जबकि बन्दियों या कर्मचारी को निजता की आवश्यकता हो जैसे वाशरूम जाने के लिए ही थोड़ी देर को कैमरे बंद कर सकते हैं किन्तु इसकी सूचना जेल के कर्मचारी को कंट्रोल रूम को देनी पड़ेगी।

बॉडी वॉर्न कैमरे के कुशल संचालन और स्टोरेज और सॉफ्टवेयर के उपयोग और रख रखाव के लिए जेल के बंदी रक्षकों और अधिकारियों की ट्रेनिंग साथ साथ होगी। बीडब्ल्यू से कैमरे के संचालनए मॉनिटरिंगए रिकॉर्डिंग, स्टोरेज आदि के लिए एक कंट्रोल रूम की स्थापना संबंधित जेल में की जाएगी जेल के किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया जाएगा।

> **यह** महत्वाकांक्षी योजना जेल में निरुद्ध बंदियों द्वारा जेल में किए गए कार्य व्यवहार की विजुअल रिकॉर्डिंग और उनकी विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन करके बंदियों को अपराध से दूर रखने के उनके सुझाव के क्रियान्वयन से संबंधित होने के कारण अपनी ऐतिहासिक और उपयोगी पहल साबित होगी।
>
> **आनंद कुमार, महानिदेशक कारागार**

नए कृषि कानून के खिलाफ आज से पूरे प्रदेश में जन अभियान चलाएगी कांग्रेस

- कारपोरेट खेती को बढ़ावा व पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है नया कानून: लल्लू
- 28 सितम्बर को कांग्रेसजन किसानों के साथ विधानसभा का करेंगे घेराव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है देश के संसद में बगैर बहस कराए बिना मत विभाजन को स्वीकार किए तानाशाहीपूर्ण तरीके से किसान विरोधी पारित किए गए तीन कृषि कानून किसानों के हितों के खिलाफ सबसे बड़ा विश्वासघात है।

लल्लू बृहस्पतिवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने तीनों नए कानूनों को काला कानून बताते हुए इनके खिलाफ 25 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में व्यापक जनान्दोलन चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में इस काले कानून के खिलाफ प्रेसवार्ता की जा रही है। कल 25 सितम्बर को सोशल मीडिया के माध्यम से खेती किसानी पर हुए इस हमले के खिलाफ कैम्पेन चलाया जाएगा। 28 सितम्बर को कांग्रेसजन आम जनता व किसानों के साथ प्रदेश की विधानसभा का घेराव करेंगे। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लालबहादुर शास्त्री की जयन्ती पर इस काले कानून के खिलाफ ब्लाक मुख्यालयों पर सत्याग्रह करेगी। इसके उपरान्त 31 अक्टूबर तक लगातार कांग्रेस जनों द्वारा इस मुद्दे को लेकर केन्द्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा बनाए गए किसान विरोधी कानून के खिलाफ आम जनता के बीच जाकर जनजागरण अभियान चलाकर भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे को जनता के बीच बेनकाब किया जायेगा। लल्लू ने कहा कि नए कानून में कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का जिक्र न होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि सरकार ने कृषि व्यवस्था को पूरी तरह से कारपोरेट और पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। इससे देश की कृषि व्यवस्था जिसमें 86.4 प्रतिशत किसान जिसकी जोत 2 एकड़ से कम है वह नई प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था से बाहर हो जायेगा।

नए कृषि व श्रम कानूनों के खिलाफ सपा आज पूरे प्रदेश में जताएगी विरोध

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 25 सितम्बर को समाजवादी पार्टी सभी जनपदों में शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए किसानों एवं श्रमिकों के हितों पर आघात पहुंचाने वाले कृषि एवं श्रम कानूनों के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन सौंपेगी। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला जो कृषि विधेयक भारत सरकार लाई है उससे किसान अपनी जमीन का मालिक न रहकर मजदूर हो जाएगा। कृषि उत्पादन मण्डी की समाप्ति और विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित न होने से किसान अब औनेपौने दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होगा। गेहूं, धान की फसल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटाये जाने से किसान को बड़े आढ़तियों और व्यापारिक घरानों की शर्तों पर अपनी फसल बेचना मजबूरी होगी। समाजवादी पार्टी किसानों की आवाज दबने नहीं देगी।

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020

दिशाहीन हो गई है विपक्ष की राजनीतिः जावड़ेकर

भाषा। नई दिल्ली

केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्षी दलों की राजनीति को दिशाहीन ठहराते हुए संसद में पारित कुछ अहम विधेयकों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिकायत करने पर उन्हें आड़े हाथों लिया। संसद में बोलने के अपने अधिकार को छोड़कर विपक्षी दल बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं। जावड़ेकर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी क्रांतिकारी विधेयकों को पारित किया जा रहा था तब उन्होंने संसद का बहिष्कार किया और जब रास में कृषि सुधार संबंधी विधेयकों पर मत विभाजन के लिए उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह उन्हें अपनी सीट पर लौटने का आग्रह कर रहे थे तो उन्होंने इसे अनसुना कर दिया।

गत रविवार को कृषि सुधार से संबंधित विधेयकों के पारित होने के दौरान राज्यसभा में विपक्षी दलों के रुख की आलोचना करते हुए जावड़ेकर ने कहा, जिस तरह से विपक्ष राज्यसभा में पेश आया, वह लज्जा का विषय है। रास को शर्मसार कर दिया। विपक्ष मत विभाजन चाहिए था। उपसभापति ने उन्हें अपनी सीट पर लौट जाने को कहा तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ये जाकर सब जगह शिकायतें कर रहे हैं। ये तो चोरी और सीनाजोरी का मामला हो गया। विपक्षी दलों की राजनीति दिशाहीन हो गई है। जब उनका अधिकार था संसद में बैठने का, बोलने का और अपनी राय देने का तो वह अधिकार उन्होंने छोड़ दिया, वाकआउट किया। सदन से बाहर जाकर प्रदर्शन किया, राष्ट्रपतिजी से मिलने गए।

जावड़ेकर ने कहा कि इसके लिए तो 300 दिन है जबकि संसद का सत्र 70-80 दिनों का ही होता है। संसद में बोलने से विपक्षी दलों को किसी ने रोका नहीं था। रविवार को उच्च सदन में कृषि संबंधी विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान भारी हंगामा हुआ था। किसान उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (प्रोत्साहन एवं सुविधा) विधेयक 2020 तथा किसान (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन का समझौता एवं कृषि सेवा विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था। अगले ही दिन अमर्यादित व्यवहार के कारण विपक्षी दलों के आठ सदस्यों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था जिसके विरोध में आठों निलंबित सदस्य संसद भवन परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे।

इन विधेयकों के पारित होने को असंवैधानिक बताते हुए विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी और उनसे आग्रह किया था कि वे इन पर अपने हस्ताक्षर ना करें। जावड़ेकर ने कहा कि इन विधेयकों के माध्यम से देश के किसानों को एक वरदान मिला है। विपक्ष की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कृषि उत्पाद विपणन समितियां (एपीएमसी) समाप्त कर दिए जाने के दावे भी झूठे साबित हुए। श्रम सुधार कानूनों को क्रांतिकारी बताते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि इनमें ऐसे सुधार हैं जिनसे देश को मजदूरों को आजादी के बाद 73 सालों से वंचित रखा गया।

सबको न्यूनतम मजदूरी, सबको नियुक्ति का पत्र, सबको समय पर तनख्वाह, पुरूष महिलाओं को समान वेतन, हर मजदूर का मुफ्त चेकअप, साल में एक बार घर जाने के लिए प्रवासी मजदूर को भत्ता, सबको ईएसआई की सुविधा का समावेश इस श्रम संहिता में किया गया है। ए क्रांतिकारी पहल है। संसद ने बुधवार को श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयकों उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को पारित कर दिया था। जावड़ेकर ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, विपक्षी दलों ने इन महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होते समय संसद का बहिष्कार किया।

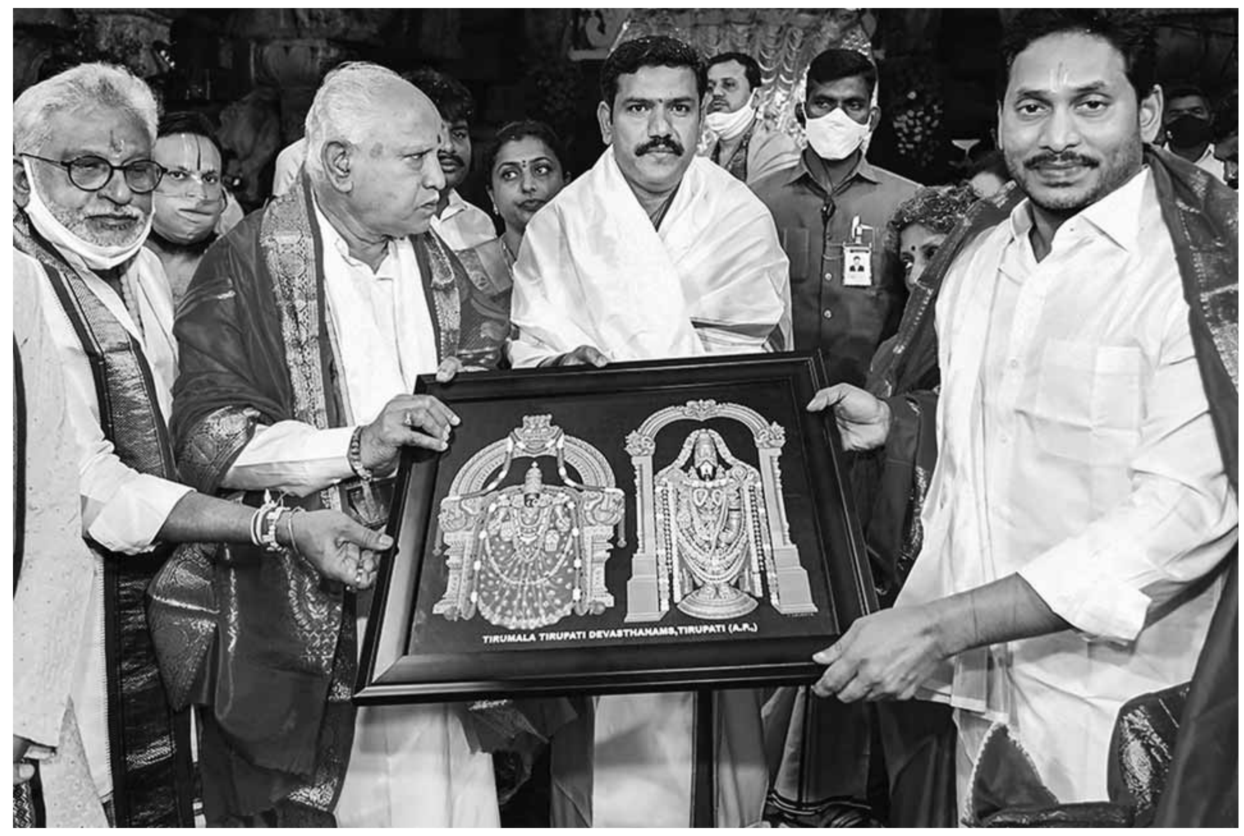

चित्तूर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी तिरूमाला में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का स्मृति चिन्ह देते हुए।

बलों को आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त करने की योजना बना रही सरकार

नई दिल्ली। सरकार सीमा की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे सुरक्षा बलों को चरणबद्ध तरीके से आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों से मुक्त करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य देश की विभिन्न सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। पिछले साल केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इन बलों की बैठक में पहली बार इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। गृह मंत्रालय एक नए मॉडल पर काम कर रहा है, जिसके तहत चुनाव कराने समेत आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों का अधिकतम भार देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उठाएगा। तीन लाख 25 हजार सुरक्षाकर्मियों वाले सीआरपीएफ को पहले ही देश के अग्रणी आंतरिक सुरक्षा बल के तौर पर चिन्हित किया जा चुका है।

सीआरपीएफ के अधिकारियों ने प्रस्ताव के हवाले से बताया कि आगामी बिहार विस चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव के दौरान एक नया प्रयोग किया जाएगा, जिसके तहत इन चुनावों में राज्य के पुलिस बल और सीआरपीएफ को 70:30 के अनुपात में तैनात किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, चुनाव के दौरान सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हाथों में होगी। सीमा की सुरक्षा करने वाले बल जैसे सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को चरणबद्ध तरीके से चुनाव जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

अधिकारी ने कहा, गृह मंत्रालय ने तय किया है कि इन तीनों बलों को चुनाव और कानून-व्यवस्था बरकरार रखने में राज्य के पुलिस बलों की मदद जैसी नियमित आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों से अगले कुछ वर्षो में पूरी तरह मुक्त किया जाए। प्रतिवर्ष, इन बलों के हजारों सैनिकों को सीमा से हटाकर चुनाव और विभिन्न राज्यों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद के लिए भेज दिया जाता है।

ऑक्सीजन का स्तर गिरने के कारण तरुण गोगोई आईसीयू में

गुवाहाटी। कोविड-19 के बाद की जटिलताओं के कारण वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर गिरने के चलते बृहस्पतिवार को उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने यह जानकारी दी। 85 वर्षीय गोगोई 25 अगस्त को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में भर्ती कराया गया था। संक्रमणमुक्त होने के बाद भी गोगोई अस्पताल में भर्ती रहे। अस्पताल के अधीक्षक अभिजीत सरमा ने कहा कि गोगोई पहले से ही कई बीमारियों की चपेट में हैं और फेफड़ों में कुछ परेशानी होने के साथ ऑक्सीजन का स्तर कम होने के बाद उन्हें गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती किया गया। उन्होंने कहा, हालांकि, गोगोई की हालत स्थिर है और हम लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं।

मप्र के गृह मंत्री ने मास्क नहीं पहनने वाले बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर खेद व्यक्त किया

भाषा। भोपाल

किसी भी कार्यक्रम में मास्क नहीं पहनने संबंधी बयान देने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी गलती के लिए बृहस्पतिवार को सार्वजनिक तौर पर खेद व्यक्त किया। मिश्रा ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, मास्क के बारे में मेरा बयान पूर्णतः गलत और माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के विपरीत था। अपने शब्दों को लेकर मुझे भी बेहद आंतरिक पीड़ा महसूस हुई है। मैं खेद प्रकट करते हुए सभी से मास्क पहनने और कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील करता हूँ।

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, मास्क पहनने के बारे में मेरे बयान से कानून की अवहेलना महसूस हुई है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप नहीं था। मैं अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट करता हूँ। मैं स्वयं भी मास्क पहनूंगा। समाज से भी अपील करूंगा कि सभी मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें।

दरअसल मिश्रा ने इंदौर में बुधवार को उनके मास्क नहीं लगाने के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा था, "मैं किसी भी कार्यक्रम में (मास्क) नहीं पहनता। इसमें क्या होता है? हालांकि बाद में बुधवार शाम को ही उन्होंने भोपाल में संवाददाताओं को इस पर सफाई देते हुए कहा, ऐसा नहीं है, लगाता हूं, आवश्यकता होती है तो लगाता हूं। दरअसल लम्बे समय तक नहीं लगा पाता। उसके पीछे कारण है। मुझे पॉलिप्स है (नाक के भीतर नेजल पैसेज या साइनस में कोमल, बिना दर्द वाली, गैर कैंसर वाली गांठ को नेजल पॉलिप्स कहा जाता है), मास्क लगाने पर घुटन होती है। लेकिन उसके बाद भी मैं कई कार्यक्रमों में, कई स्थानों जहां आवश्यकता होती है, (मास्क) लगाता हूं। गृहमंत्री के बृहस्पतिवार को खेद व्यक्त करने से पहले कांग्रेस ने बुधवार को उनकी आलोचना करते हुए कहा था कि जिस प्रदेश में एक लाख से अधिक लोग संक्रमित हो, दो हज़ार से अधिक मौतें हो चुकी हो, जहां मास्क नहीं पहनने पर जनता पर जुर्माना लगता हो, वहाँ के गृह मंत्री कहते है कि मैं मास्क नहीं पहनता।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने गृहमंत्री की माफी पर व्यंगात्मक ट्वीट किया, सुबह - मैं मास्क नहीं पहनता। शाम - मुझे साँस संबंधी (पालीपस) तकलीफ़ है। अगले दिन - मैं गलती मानता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ। मेरा बयान प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुरूप नहीं है।अब मैं मास्क पहनूँगा। जो भी सच्चाई हो लेकिन गृह मंत्री जी देर आए- दुरुस्त आए।

क्विक न्यूज

बीरेन ने तीन मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया

इम्फाल। मणिपुर में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बृहस्पतिवार को तीन मंत्रियो को अपनी मंत्रिमंडल से हटा दिया। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र के अनुसार, राज्यपाल नजमा हेप्तुल्ला ने इस संबंध मे सिंह की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से बाहर गए मंत्री हैं.... कृषि और पशुपालन मंत्री वी. हंगखालियान, सामाजिक कल्याण और सहकारिता मंत्री नेमच किमजेन और शिक्षा, श्रम और रोजगार मंत्री राधेश्याम सिंह। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एस. टिकेन्द्र सिंह हाल मे दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित कई पार्टी नेताओं से मुलाकात की थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस दौरान मंत्रिमंडल मे फेरबदल और विधानसभा उपचुनाव सहित तमाम मुद्दो पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि 60 सदस्ईय विधानसभा के पांच सीट हाल मे विधायकों के इस्तीफे और उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के कारण रिक्त हो गई है।

निलंबित आईएएस शिवशंकर एनआईए के सामने पेश हुए

कोच्चि। केरल मे सोने की तस्करी मे मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी एम शिवशंकर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के सामने पेश हुए। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे दो महीने पहले भी एजेंसी ने इस सनसनीखेज मामले के संबंध में उनसे पूछताछ की थी। मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को भी पूछताछ के लिए यहां एनआईए कार्यालय में लाया गया। समाचार चैनलों पर दिखाई जा रही खबर मे शिवशंकर को एनआईए कार्यालय पहुंचते देखा गया। इस मामले में सुरेश के साथ संबंध उजागर होने के बाद तीसरी बार अधिकारी को एनआईए के सामने पेश होना पड़ा है। सीमा शुल्क विभाग पहले ही उनसे पूछताछ कर चुका है।

सिक्किम के मुख्यमंत्री के बेटे और नौ अन्य की जांच में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि

गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की पत्नी कृष्णा और परिवार के कुछ अन्य सदस्यो के कोरोना वायरस की चपेट में आने के कुछ दिन बाद अब उनके बेटे विधायक आदित्य के भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव पेमा टी भूटिया ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री निवास मे नौ और लोगो की जांच मे संक्रमण की पुष्टि हुई है। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्राथमिक तौर पर उनके संपर्क मे आने वाले लोगों की निश्चित अंतराल पर कोविड-19 जांच की जा रही है। आदित्य, सोरेंग-चखूंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने 21 सितंबर को विधानसभा सत्र में भाग लिया था। बुधवार को उनकी जांच मे संक्रमण की पुष्टि हुई।

लॉकडाउन के दौरान देश में संस्थागत प्रसव में 23.9 प्रतिशत की गिरावट आईः केंद्रीय मंत्री अश्वनि चौबे

नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जून महीने के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में देश में संस्थागत प्रसव में 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने 18 सितंबर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। निचले सदन में अपराजिता सारंगी ने पूछा था कि क्या लॉकडाउन लागू करने के बाद देश मे अस्पतालो मे कराए जाने वाले प्रसव मे कमी आई है। चौबे ने बताया कि स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) पोर्टल के अनुसार, मार्च से अगस्त 2020 तक कुल 10,96,048 प्रसव पूर्व जांच किए गए। कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य मे अप्रैल से जून 2020 मे पिछले वर्ष की तुलना मे देश मे संस्थागत प्रसव मे 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।

परभणी में लाखों रुपए के प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त

औरंगाबाद। महाराष्ट्र के परभणी जिले मे एक टैपो से करीब 16 लाख रुपए मूल्य के प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टैपो को तलाशी के लिए रोका जोकि पथरी रोड से होते हुए परभणी शहर की तरफ जा रहा था। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमे करीब 16 लाख रुपए की कीमत वाले प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद मिले। पुलिस ने वाहन चालक समोल ढोबले (26) और तुकाराम वास्के (32) को हिरासत में लिया है। संबंधित धाराओं मे मुकदमा दर्ज किया गया है।

पर्यटकों को अब नहीं दिखानी होगी कोविड-19 जांच रिपोर्ट

देहरादून। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों मे ढील देते हुए राज्य सरकार ने उन्हें आगमन पर अपनी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से छूट दे दी है। इस संबंध मे जारी संशोधत दिशानिर्देशो मे प्रदेश मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि उत्तराखंड में किसी होटल या होमस्टे मे ठहरने से पहले पर्यटकों को अब अनिवार्य रूप से अपनी कोविड-19 जांच रिपोर्ट देने की जरूरत नही है।

कोच्चि के चेलनाम में समुदी दीवार के निर्माण की मांग करते हुए प्रदर्शन करते स्थानीय निवासी।

हर दुर्गा पूजा समिति को 50-50 हजार रुपए देंगी ममता बनर्जी

भाषा। कोलकाता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की प्रत्एक दुर्गा पूजा समिति को पचास-पचास हजार रुपए उपलब्ध कराने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। राज्य की करीब 37 हजार दुर्गा पूजा समितियों के लिए कई तरह की राहत की घोषणा करते हुए बनर्जी ने कहा कि दमकल विभाग, कोलकाता नगर निगम, अन्य नगर निकाय और पंचायत अपनी सेवाओं के लिए पूजा समितियों से किसी तरह का कर या शुल्क वसूल नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, कोविड महामारी के चलते यह हम सभी के लिए कठिन समय रहा है। हमने राज्य की प्रत्एक दुर्गा समिति को पचास-पचास हजार रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। हमने यह भी निर्णय किया है कि कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम और राज्य विद्युत बोर्ड पूजा समितियों को 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध कराएंगे। बनर्जी ने समितियों से कहा कि वे महामारी के मद्देनजर खुले पंडाल लगाने की तैयारी करें और सुनिश्चित करें कि पंडालों में लोग मास्क लगाकर आएं। मुख्यमंत्री ने राज्य के 75 हजार हॉकरों को दो-दो हजार रुपए की मदद देने की भी घोषणा की क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

दूसरी ओर माकपा नीत वाम मोर्चे और कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संसद से पारित किसान विरोधी और श्रमिक विरोधी विधेयकों पर चर्चा के लिए राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। नेता विपक्ष अब्दुल मन्नान और वाम मोर्चा विधायक दल के नेता सुजान चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री को लिखे संयुक्त पत्र में कहा कि वे जनहित में इन मुद्दों पर विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस द्वारा लाए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव का हिस्सा बनने को तैयार हैं।

महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल न खोलने के राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगी अदालत

भाषा। मुंबई

बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कोविड-19 के मद्देनजर धार्मिक स्थलों को जनता के लिए बंद रखने को कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार होती वृद्धि को देखते हुए अदालत, राज्य सरकार के निर्णय में दखलंदाजी नहीं करना चाहती।

महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने अदालत में कहा कि धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति अभी नहीं दी जा सकती। कुम्भकोणी ने कहा, दुर्भाग्य से प्रतिदिन कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए अभी धार्मिक स्थलों को खोला नहीं जा सकता। पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें धार्मिक स्थलों को जनता के लिए खोले जाने की याचना की गई थी। एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन ने वकील दीपेश सिरोया के माध्यम से याचिका दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि सरकार धार्मिक स्थलों में एक समय में प्रवेश लेने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर सकती है।

पिछली सुनवाई में राज्य ने कहा था कि श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करना संभव नहीं होगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद जनता सारे नियम कायदे मानेगी। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के तर्क को स्वीकार किया और सहमति जताई कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जो चिंताजनक स्थिति है।

मौजूदा सरकार के आलोचक नेताओं, कार्यकर्ताओं को पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही हैः भाकपा

नई दिल्ली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस फरवरी में हुए दंगों के मामले में उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है, जो भाजपा नीत सरकार की जन-विरोधी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। मामले की जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए भाकपा ने कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच एक साजिश है, जिसका लक्ष्य हिंसा के असली गुनहगारों को पकड़ने के बजाय उन लोगों को अपराधी साबित करना है जो मानवाधिकार हनन और अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों के मामलों में दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अपने एक पूरक आरोपपत्र में माकपा महासचिव सीताराम एचुरी, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयती घोष और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक अपूर्वानंद का नाम लिया गया है। उनका नाम कथित रूप से संशोधित सीएए प्रदर्शनकारियों को उकसाने और लामबंद करने के कारण इसमें आया है। भाकपा के बयान में कहा गया है, पार्टी उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की जांच में दिल्ली पुलिस की भूमिका की निंदा करती है, जिसमें भाकपा की राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य और महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इडियन वूमन एनी राजा सहित नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है।

बयान में कहा गया है कि सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रदर्शन कानून के खिलाफ लोगों की असहमति का वैध और संवैधानिक अधिकार है। ए प्रदर्शन इतने प्रभावी थे कि इसने भाजपा को हिला कर रख दिया, जो प्रदर्शनों को दंगों की साजिश के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रही है। भाकपा ने कहा, यह स्तब्ध कर देने वाला है कि दिल्ली पुलिस मौजूदा सरकार की जन विरोधी नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है।

भाकपा महासचिव डी राजा ने कहा कि भाकपा नेता एनी राजा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी मामले में गिरफ्तार लोगों के बयान के आधार पर आरोपपत्र में नामजद किया गया है। इनमें सलमान खुर्शीद, वृंदा करात, कविता कृष्णन और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, योगेंद्र यादव, हर्ष मंदर, राहुल रॉय, अपूर्वानंद और सबा दीवान के नाम भी शामिल हैं। बयान में कहा गया है, इन सभी लोगों ने मुस्लिम महिलाओं के नेतृत्व में हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के प्रति एकजुटता दिखाई थी और अब इसे एक बड़ी साजिश बताया जा रहा है।

कृषि विधेयकों के समर्थन में चौहान ने कहा, किसानों के भगवान हैं प्रधानमंत्री

भाषा। इंदौर

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों का भगवान बताया और कहा कि संसद से पारित कृषि सुधार संबंधी विधेयकों से अन्नदाताओं की आय दोगुनी होगी। चौहान ने इन विधेयकों के विरोध में उतरे विपक्षी दलों को "किसानद्रोही करार दिया और आरोप लगाया कि वे बिचौलियों की पैरवी कर रहे हैं। चौहान ने बुधवार रात यहां संवाददाताओं से कहा कि दूरदृष्टि से फैसले करने वाले प्रधानमंत्री किसानों के भगवान हैं। कृषि सुधारों से संबंधित तीनों विधेयक किसानों के लिए वरदान हैं जिनसे किसानों की आय दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों का विरोध कर रहे विपक्षी दल अन्नदाताओं के शुभचिंतक नहीं, बल्कि किसानद्रोही हैं। वे किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनकी ए कोशिशें सफल नहीं होने दी जाएंगी।

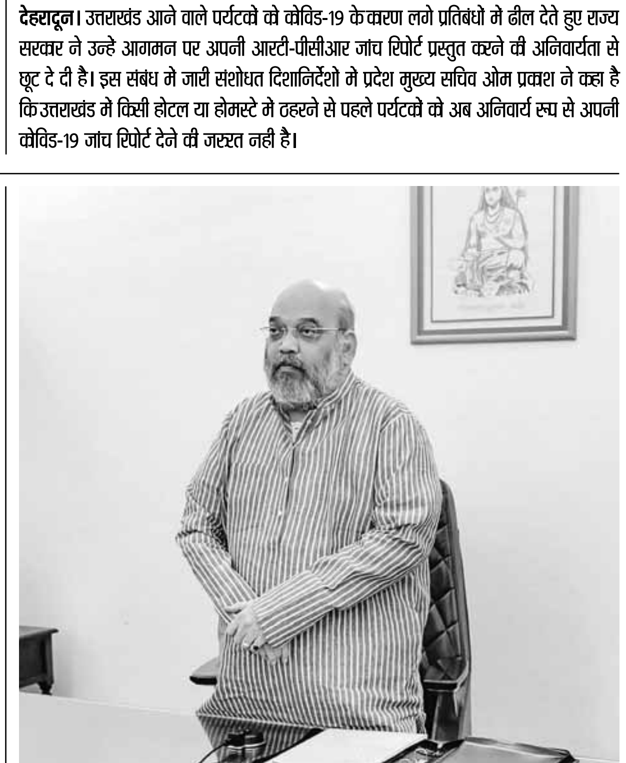

नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह रेल राज्यमंत्री स्वर्गीय सुरेश अंगड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए। सुरेश का एम्स में कोरोना के चलते निधन हो गया था

दक्षेस को आतंकवाद, कारोबार बाधा और संपर्क के मुद्दे का निपटारा करना चाहिए: जयशंकर

भाषा। नई दिल्ली

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दक्षेस को आतंकवाद तथा कारोबार एवं सम्पर्क में बाधा उत्पन्न करने से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण चुनौतियों का निपटारा करने की जरूरत है। विदेश मंत्री ने यह बात दक्षेस समूह की डिजिटल माध्यम से हुई अनौपचारिक बैठक में कही जिसे पाकिस्तान की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है।

दक्षेस विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने आतंक का पोषण, समर्थन और प्रोत्साहित करने वाली ताकतों सहित आतंकवाद की बुराई को परास्त करने के लिए सामूहिक संकल्प की जरूरत बताई। विदेश मंत्री ने पड़ोस प्रथम की भारत की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की और एक दूसरे से जुड़े, समन्वित और समृद्ध दक्षिण एशिया की कामना की। इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी हिस्सा लिया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर इस समूह के विदेश मंत्रियों के बीच विचारों के अनौपचारिक आदान प्रदान की परंपरा को जारी रखते हुए किया गया था। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र अभी जारी है। जयशंकर ने कहा कि दक्षेस ने पिछले 35 वर्षों में काफी प्रगति की है लेकिन सामूहिक सहयोग और समृद्धि की दिशा में प्रयास, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे से जुड़ी गतिविधियों के कारण प्रभावित हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने उनका हवाला देते हुए कई ट्वीट के जरिए यह बात बताई। जयशंकर ने कहा कि ऐसे माहौल में पूर्ण क्षमता के अनुरूप हमारे सामूहिक प्रयास के जरिए साझा उद्देश्य हासिल करने में रूकावट आती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम आतंक का पोषण, समर्थन और प्रोत्साहिन करने वाली ताकतों सहित आतंकवाद की बुराई को परास्त करने के लिए सामूहिक संकल्प लें।

विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे पहल से जरूरी विश्वास और भरोसा कायम होगा और मजबूत एवं समृद्ध दक्षेस का निर्माण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि दक्षेस को सीमापार आतंकवाद, कारोबार एवं संपर्क में बाधा उत्पन्न करने से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण चुनौतियों का निपटारा करने की जरूरत है। इसके बाद ही हम दक्षिण एशिया में टिकाऊ शांति, समृद्धि और सुरक्षा देख सकेंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने छह वर्ष पहले दक्षेस ढांचे के तहत महत्वपूर्ण सम्पर्क पहल तथा समूह के सदस्य देशों के बीच कारोबार के मार्ग को बाधित कर दिया था। दक्षेस 2016 के बाद से उतना प्रभावी नहीं रहा है और इसकी अंतिम बैठक 2014 में काठमांडो में हुई थी।

नई दिल्ली में एशिया में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की विशेष मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेते विदेश मंत्री एस जयशंकर

एनएसएस का कार्य सराहनीय: रामनाथ कोविंद

भाषा। नई दिल्ली

कोविड-19 के समय में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के कार्यों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार को कहा कि इनका सेवा के माध्यम से शिक्षा तथा चरित्र का निर्माण तथा व्यक्तित्व विकास का कार्य अनुकरणीय है।

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं ने कोविड-19 के कारणों और उसकी रोकथाम के सम्बन्ध में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने में सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान की है। इन स्वयंसेवकों ने जनसेवा की नई मिसाल प्रस्तुत की है। यह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के विरुद्ध संघर्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करने तथा मास्क के प्रयोग को लेकर जागरूकता का प्रसार किया। पृथक-वास के दौरान लोगों तक खाद्य-सामग्री एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं पहुंचाने में योगदान दिया है।

कोविंद ने कहा कि भूकम्प और बाढ़ जैसी राष्ट्रीय आपदाओं के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता समाज की सहायता के लिए सदा तत्पर रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में उन्होंने बाढ़ एवं जलभराव के दौरान राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में अथक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा, इन्होंने यह सिद्ध किया है कि हमारी बेटियां भी राष्ट्र-सेवा में अमूल्य योगदान देती हैं। हमारी ए बेटियां उस परंपरा की याद दिलाती हैं जिसमें सावित्री बाई फुले, कस्तूरबा गांधी और मदर टेरेसा जैसे सेवा-भावना के महान और प्रेरक उदाहरण मौजूद हैं। राष्ट्रपति ने कहा, राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य है सेवा के माध्यम से शिक्षा। सेवा के द्वारा युवा स्वयंसेवकों के चरित्र का निर्माण तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आदर्श वाक्य मैं नहीं, बल्कि आप है। इसका भाव है, अपने हित की जगह दूसरे के हित पर ध्यान देना। कोविंद ने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि अनेक तकनीकी संस्थानों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के लगभग 40 लाख युवा विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर, समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। अब तक लगभग सवा चार करोड़ विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अपना योगदान दे चुके हैं।

उन्होंने वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी स्वयंसेवकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने केवल मानवता ही नहीं बल्कि पशु-पक्षियों और प्रकृति के प्रति भी सेवा और करुणा की भावना पर बल दिया था और अपना सम्पूर्ण जीवन, सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि बापू ने कहा था, ईश्वर की पहचान सेवा से ही होगी, यह मानकर मैंने सेवा-धर्म स्वीकार किया था। राष्ट्रपति ने कहा, गांधी जी के आदर्शों से युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत, उनकी जन्म-शताब्दी के उपलक्ष्य में सन् 1969 में की गई थी। यह योजना, आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पांच दशक पहले थी। उन्होंने कहा कि यह तथ्य विशेष रूप से संतोषप्रद है कि वर्ष 2018-19 के 42 पुरस्कार विजेताओं की सूची में 14 बेटियों के नाम भी शामिल हैं।

सीबीएसई ने न्यायालय को बताया

12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा के नतीजे 10 अक्टूबर तक होंगे घोषित

भाषा। नई दिल्ली

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि छात्रों के हितों को देखते हुए 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के नतीजे 10 अक्टूबर तक या इससे पहले ही घोषित कर दिए जाएंगे।

न्यायमूति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी सूचित किया कि स्नातक छात्रों के लिए नया सत्र 31 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा और उस समय तक पूरक परीक्षाओं में शामिल होने वाले लगभग सभी दो लाख छात्रो के नतीजे आ चुके होंगे। पीठ की टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में सीबीएसई और यूजीसी के वक्तव्य काफी महत्वपूर्ण हैं। पीठ ने दोनों संस्थाओं को परस्पर तालमेल से काम करने पर जोर देते यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि पूरक परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों का साल बर्बाद नहीं हो। न्यायालय ने कहा था कि सीबीएसई को पूरक परीक्षाओं के नतीजे यथाशीघ्र घोषित करने चाहिए और यूजीसी को यह देखना चाहिए कि कालेजों में छात्रों को प्रवेश मिल जाए।

कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए न्यायालय ने कहा था कि यह असाधारण समय है और ऐसी स्थिति में प्राधिकारियों को छात्रों की मदद करनी चाहिए। पीठ ने इसके साथ ही अनिका संवेदी की याचिका का निस्तारण कर दिया। इस याचिका में प्राधिकारियों को यह निर्देशे देने का अनुरोध किया गया था कि 12वीं की पूरक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का साल बर्बाद नहीं हो।

भ्रष्टाचार में शुआट्स के दो प्रोफेसर निलंबित, चार रडार पर

- भ्रष्टाचार, अनियमितता धर्मांतरण के दुष्प्रचार और शांति भंग करने की कोशिश के आरोपों में पाए गए दोषी
- संस्थान की आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद की गई कार्रवाई से हड़कंप

पायनियर समाचार सेवा। प्रयागराज

संस्थान के खिलाफ धर्मांतरण के दुष्प्रचार समेत कई संगीन आरोपों से घिरे शुआट्स के दो प्रोफेसरों को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया। कमोवेश इसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त चार अन्य लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। जिनके खिलाफ भी निलंबन की तलवार लटक रही है। शुआटस् प्रशासन ने दोनों निलंबित प्रोफेसरों की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति से जांच कराने की अनुशंसा की है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय शुआट्स के दो प्रोफेसर संस्थान के वाटर रिसोर्स में कार्यरत डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव और इंजीनियरिंग कालेज के डीन डॉक्टर अशोक त्रिपाठी पर भ्रष्टाचार अनियमितता और संस्थान के खिलाफ धर्मांतरण का दुष्प्रचार करने समेत कई संगीन आरोप लगे थे। इनके अलावा संस्थान के चार और लोग हैं जो अभी जांच समिति के राडार पर हैं। इन पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। शुआट्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर रमाकांत ?दुबे ने बताया कि दोनों प्रोफेसरों के खिलाफ शिकायत मिली थी। जिसकी जांच के लिए आंतरिक जांच समिति गठित की गई थी। गठित आंतरिक जांच समिति ने अपनी जांच में दोनों को आपराधिक साजिश रचने घोर कदाचार सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने का प्रयास संस्थान के भीतर शांति भंग करने का प्रयास धर्मांतरण गतिविधियों की खबरें फैलाने का षड्यंत्र संस्थान के नाम और प्रतिष्ठा को बदनाम करने की साजिश संस्थान के अधिकारियों के खिलाफ साजिश करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर्मचारियों को गुमराह करने अशांति और रुकावट पैदा करने के लिए उकसाने की साजिश रचने के कृत्य में प्रथम दृष्टतया दोषी पाया था। जिसके बाद दोनों को निलंबित करने की सिफारिश की गयी थी। जिसके आधार पर दोनों को निलंबित कर दिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के निर्देशन में न्यायिक जांच कराने हेतु एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर रमाकांत दुबे ने बताया कि अन्य चार अन्य लोगों की अभी जांच चल रही है। शुआट्स के निलंबित प्रो. डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव और डॉक्टर अशोक त्रिपाठी वर्ष 2017 से संस्थान की प्रशासनिक विंग से खिलाफ काम कर रहे थे।

प्रोफेसर की बाबू पत्नी को बनाया असिस्टेंट प्रोफेसर

प्रयागराज। शुआट्स के निलंबित दोनों प्रोफेसर एक समय संस्थान के मालिकानों के बेहद करीबियों में गिने जाते थे। सूत्रों की माने तो एक प्रोफेसर की पत्नी जो कि संस्थान में बाबू थी। उसे प्रमोट करके असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया था। जिसका तत्कालीन कुलपति ने विरोध किया था। बाद में विरोध करने वाले कुलपति को ही गंभीर आरोप लगने की वजह से निलंबित कर दिया गया।

रिश्वत लेते हुए नवोदय विद्यालय के प्राचार्य सहित दो लोग गिरफ्तार

भाषा। जयपुर

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बृहस्पतिवार को अलग-अलग कार्रवाई कर जयपुर के पावटा में कार्यरत नवोदय विद्यालय के प्राचार्य और श्रीगंगानगर के आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

ब्यूरो महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि जयपुर के पावटा में कार्यरत आरोपी प्रिंसिपल अशोक कुमार वर्मा को परिवादी से कमीशन के रूप में 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि परिवादी को नवोदय विद्यालय पावटा में भवन रखरखाव का कार्यादेश मिला हुआ है और उसके 4 लाख 70 हजार के बिल मंजूर करने की एवज में आरोपी प्राचार्य अशोक कुमार वर्मा ने उससे पांच प्रतिशत कमीशन के रूप में रिश्वत की राशि मांगी थी। अंत में बात तीन प्रतिशत कमीशन के राशि के रूप में तय हुआ। उन्होंने बताया कि अशोक कुमार वर्मा को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। ब्यूरो ने एक अन्य कार्वाई में श्रीगंगानगर के उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को परिवादी से वेतन निर्धारण की एवज में 15,000 रूपए की कथित रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ब्यूरो के उपाधीक्षक वेद प्रकाश लखोटिया ने बताया कि आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी आरोपी पवन कुमार शर्मा ने परिवादी गोवर्धन लाल शर्मा से उनकी जून 2018 में लगने वाली एसीसी (वित्तीय उन्नयन) लगाने व वेतन निर्धारण की एवज में 18,000 रूपए की मांग की थी। उन्होंने बताया कि आरोपी ने इस मामले में परिवादी से रविवार को 3,000 रूपए अग्रिम प्राप्त कर लिए थे। आरोपी को बृहस्पतिवार को परिवादी से 15,000 रूपए की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी से रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच की जा रही है।

मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र से बिचौलिओं को खत्म किया है: मुख्यमंत्री रावत

भाषा। देहरादून

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कृषि क्षेत्र में बिचौलिओं को 2393ात्म कर दिया और किसानों को मंडी से आज़ाद कर दिया। कृषि विधेयकों के प्रशंसा करते हुए रावत ने यहाँ संवाददाताओं को बताया कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए अब तक सबसे ज़्यादा अभूतपूर्व काम किए हैं। उन्होंने कहा, किसान अब मंडी से आजाद है। उसे कोई भी मंडी शुल्क नहीं देना पड़ेगा और इसी प्रकार सभी तरह के बिचौलिओं को भी खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों को सात घंटे बिजली दी जबकि उसकी मांग केवल दो घंटे की थी। रावत ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि संप्रग सरकार ने 10 साल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रखा और कहा कि अगर किसी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट पर काम किया तो वह नरेंद्र मोदी की सरकार है।

परमाणु वैज्ञानिक शेखर बसु का कोविड-19 से निधन

भाषा। कोलकाता

फाइल फोटो

विख्यात परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. शेखर बसु का यहां एक निजी अस्पताल में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के चलते निधन हो गया। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बसु, तीन दिन पहले ही 68 वर्ष के हुए थे। अधिकारी ने कहा, डॉ बसु कोविड-19 और किडनी संबंधित अन्य रोग से पीड़ित थे। सुबह चार बजकर पचास मिनट पर उनका निधन हो गया। मैकेनिकल इंजीनियर डॉ बसु को देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत की परमाणु ऊर्जा से संचालित पहली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के लिए बेहद जटिल रिएक्टर के निर्माण में बसु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉ बसु के निधन पर शोक प्रकट किया और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, विख्यात परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ शेखर बसु के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके सहकर्मियों और परिजनों को मेरी सांत्वना। प्रख्यात भौतिकविद और पद्म विभूषण से सम्मानित विकास सिन्हा ने कहा कि डॉ. बसु के निधन से भारी क्षति हुई है। सिन्हा ने कहा कि देश ने एक महान इंजीनियर और अच्छा इंसान खो दिया। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान तथा वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन सेंटर के पूर्व निदेशक सिन्हा ने कहा, मैं कहूंगा कि वह हमें कम उम्र में छोड़ कर चले गए। उन्हें अभी और योगदान देना बाकी था। वह एक निपुण इंजीनियर थे जिन्होंने हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया था। उन्होंने कहा, बसु ने परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी के लिए बहुत काम किया था। हमने एक अच्छा इंसान खो दिया। बसु का जन्म 20 सितंबर 1952 को हुआ था। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में लंबे समय तक काम किया था और 2012 में वह केंद्र के निदेशक भी बने। बसु ने तमिलनाडु में भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला के विकास में भी अहम भूमिका निभाई थी।

पेज एक का शेष

आज बंद...

(नांदेड़-अमृतसर) तथा शहीद एक्सप्रेस (अमृतसर-जयनगर) शामिल हैं। कई माल और पार्सल ट्रेनों का भी समय बदला गया है। मौजूदा वक्त में आमतौर चलने वाली यात्री ट्रेनों को कोविड-19 महामारी के कारण नहीं चलाया जा रहा है। गुरुवार की सुबह किसान मजदूर संघर्ष समिति तथा भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान बरनाला, संगरूर, फिरोजपुर तथा अमृतसर में रेल ट्रैकों पर बैठ गए। उन्होंने रेल ट्रैकों पर टेंट लगा दिया है। फजिल्का और अबोहर में उन्होंने ट्रैक्टर रैलियां निकाली। उन्होंने भाजपा नेताओं का घेराव करने तथा कृषि बिलों के पक्ष में मतदान करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला किया है। किसान नेताओं के मुताबिक 100 से अधिक किसान और आढ़ती संगठन राष्ट्रव्यापी बंद में भाग लेंगे। संगठनों के एक प्रतिनिधि ने कहा कि पूरे पंजाब में सड़क और रेलवे ट्रैकों को 125 जगहों पर अवरुद्ध किया जाएगा। सभी किसान यूनियनों के एक प्रतिनिधि बिनोद पांडेय ने कहा ' पूरे राज्य से मिली जानकारी के मुताबिक बंद के आह्वान पर ट्रक, बस, टैंपों, कर्मचारियों, युवा छात्रों, मजदूरों तथा अन्य विभिन्न संगठनों सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा में इनेलो और कांग्रेस ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने कहा कि राष्ट्रव्यापी बंद के मुद्दे पर कई किसान संगठन जैसे भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान महासंघ, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी संयुक्त रूप से एक मंच पर आ गए हैं। घटनाक्रमों से परिचित नेताओं ने कहा कि हरियाणा में किसान नेता राज्य के विभिन्न जिलों में रेल और सड़क यातायात को अवरुद्ध करने पर विचार कर रहे हैं। बीकेयू (चारुनी) और बीकेयू (टिकैत) समेत किसान यूनियन के नेता आढ़तिया एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर और दुकानदारों के विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर सुबह 10 से शाम 4 बजे दुकानों को बंद कर भारत बंद का समर्थन करने के लिए तैयार कर रहे हैं। उनका दावा है कि राज्य में सभी मंडियां शुक्रवार को बंद रहेंगे तथा इस दिन कोई कारोबार नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में किसान सड़क और हाईवे को बाधित करेंगे जबकि उत्तर प्रदेश में किसान अपने अपने गांवों, कस्बों तथा राजमार्गों पर जाम लगाएंगे। रेलवे ने गुरुवार को कहा कि कृषि बिलों पर पंजाब में रेल रोको आंदोलन से अनाजों तथा अन्य जरूरी सामानों के लदान के साथ साथ आपात स्थिति में विशेष ट्रेनों से यात्रा कर रहे लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होगी। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब ने इस साल अगस्त में एफसीआई की 990 रैक अनाज की लदाई की थी और 23 सितंबर तक 816 रैक लद चुके थे। एफसीआई पंजाब में प्रतिदिन 35 से ज्यादा रैको की लदाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजबा कंटेनरों में प्रतिदिन 9-10 रैक खाद, सीमेंट, ऑटो, विभिन्न मालों की लदाई करता है। राज्य को प्रतिदिन 20 रैक कोयला, अनाज, कृषि उत्पाद, मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, आयातित खाद आदि भी मिलती है।

बिल छोटे...

जरिये तय की जाती है, किसान उसी कीमत पर अपनी उपज को बेचने पर मजबूर होते हैं चाहे वे खुश हो या दुखी क्योंकि यदि वे अपनी उपज लेकर घर जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो उन्हें इसे लाने और ले जाने का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है।' इस दौरान तोमर ने कृषि सुधार विधेयकों का विरोध कर रही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के विरोध की तुलना 'हाथी के दांत' से करते हुए विपक्षी दल को चुनौती दी कि उसे इन विधेयकों के विरोध से पहले अपने घोषणापत्र से मुकरने की घोषणा करनी चाहिए। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद कृषि से संबंधित तीनों विधेयक आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 तथा कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 को संसद से पारित कर दिया गया था। इन विधेयकों के पारित होने को 'असंवैधानिक' बताते हुए विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी और उनसे आग्रह किया था कि वह इन पर अपने हस्ताक्षर नहीं करें। तोमर ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के दांत खाने के और तथा दिखाने के और हैं। वह दोमुंही राजनीति कर रही है। वह देश में झूठ बोलने की राजनीति करती है। कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का प्रयत्न कर रही है, इसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी।' उन्होंने कहा, 'कांग्रेस अगर इन विधेयकों का विरोध कर रही है तो उसे पहले अपने घोषणा पत्र से मुकरने की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिये अपने घोषणा पत्र में उसने कहा था कि एपीएमसी (कृषि उत्पाद विपणन समितियां) कानून को बदलेंगे, किसान के व्यापार पर कोई कर नहीं होगा और अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा देंगे। यही चीज संसद से पारित विधेयकों में है।'

उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की बैठक में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है, उसे अब तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। तोमर ने देशभर के किसानों को भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार खेती और किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है और पहले ही दिन से उसने किसानों के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष के किसी भी सदस्य ने विधेयकों के किसी प्रावधान का विरोध नहीं किया बल्कि उनका भाषण उन सब बातों पर केंद्रित रहा जो विधेयक में नहीं थे और विधेयक से संबंध नहीं था। उन्होंने कहा, 'इससे ये सिद्ध होता है कि विधेयक में जो प्रावधान हैं वो किसान हितैषी हैं। इन विधेयकों के माध्यम से किसान नई प्रौद्योगिकी से भी जुड़ेगा। इसके कारण किसान अपनी उपज का सही मूल्य बुआई से पूर्व भी प्राप्त कर सकेगा।'

भारत में...

है। एंटीजन टेस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के कारण स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। कई राज्यों में जब से एंटीजन टेस्ट शुरू हुए, उसके बाद पॉजिटिव केस में भारी कमी दर्ज की गई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोरोनो वायरस के संक्रमण की स्थिति इससे कहीं अधिक खराब हो चुकी है जितनी टेस्ट के परिणामों में दिखाई जाती है। अफ्रीका की स्थिति एशिया की तुलना में कहीं बेहतर है। इस महाद्वीप के 57 राष्ट्रों में गुरुवार को सिर्फ 8000 केस ही आए। यानी एक राष्ट्र में औसतन 150 केस। महाद्वीप में लगभग 16 देशों में एक भी नया मामला दर्ज किया गया, जबकि लगभग दो दर्जन देशों में नए मरीजों की संख्या दोहरे अंक में ही रही। हालांकि यूरोप की ताजा स्थिति खतरनाक होती जा रही है। यहां यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन में हर दिन लगभग 10,000 नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में हालात स्थिर हो गए हैं और दक्षिण अमेरिका के कुछ सबसे अधिक प्रभावित देशों में भी कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है। हालांकि, भारत में स्थिति सुधरने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में स्थिति थोड़ी संभली है और इनमें पिछले एक सप्ताह के दौरान कम केस आए हैं, लेकिन इसकी जगह अन्य राज्यों ने ले ली है जहां तेजी से बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं। उदाहरण के लिए शुरुआती समय में बीमारी को बेहतर तरीके से काबू करने वाले केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 6,324 नए मामले आए और 21 लोगों की मृत्यु हो गई। यह इस राज्य में एक दिन में सबसे अधिक बढ़ोतरी है। अब सर्दियां दरवाजे पर हैं। इसमें कोरोना के अधिक खतरनाक रूप लेने की आशंका जताई जा रही है। भारत में मानवीय प्रयास के सकारात्मक नतीजे अभी तक नहीं दिखे हैं, इसलिए संक्रमण के हमले से बचाने के लिए दैवीय शक्तियों से ही उम्मीद की जा सकती है।

कोरोना संक्रमण...

है। उस दिन सेंसेक्स 2,000 अंक से अधिक अंक टूटा था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 326.30 अंक या 2.93 प्रतिशत टूटकर 10,805.55 अंक पर पहुंच गया। पिछले छह कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 2,749.25 अंक नीचे आ चुका है। इस दौरान निफ्टी में 799 अंक की गिरावट आई है। इस बीच, बीएसई की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 3.95 लाख करोड़ रुपए घटकर 1,48,76,217.22 करोड़ रुपए रह गया। बाजार में आई गिरावट से निवेशकों को 3.95 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का नुकसान हुआ है। सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर को छोड़कर अन्य सभी में नुकसान रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 0.36 प्रतिशत के लाभ में बंद हुआ। इंडसइंड बैंक के शेयर में सबसे अधिक 7.10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। अन्य एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.59 प्रतिशत टूट गया। चीन का शंघाई कम्पोजिट, जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग भी 1.82 प्रतिशत नीचे आए। इस बीच, वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 0.22 प्रतिशत के नुकसान से 41.68 डॉलर प्रति बैरल पर बोला गया।

दिल्ली में...

गए। एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया। तत्काल कदम उठाते हुए जांच को प्रतिदिन करीब 20 हजार से बढ़ाकर 60 हजार कर दिया गया। कोरोना वायरस को हराने का सर्वश्रेष्ठ तरीका तेजी से जांच करना और संक्रमितों का पता लगाकर उन्हें पृथक करना है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं क्योंकि जांच काफी बढ़ा दी गई है। 16 सितम्बर को रोज सामने आने वाले मामले करीब 4,500 थे जो अब घटने शुरू हो गए हैं। मौजूदा समय में प्रतिदिन करीब 3,700 केस सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार यदि जांच को कम करके 20 हजार (प्रतिदिन) के पुराने स्तर पर ला दिया गया होता तो प्रतिदिन कोरोना मामले भी कम होकर करीब 1500 रह जाते। केजरीवाल ने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का ब्योरा देते हुए कहा कि अगस्त के मध्य में निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या 550 से बढ़ाकर 2,000 करने जैसे तमाम उपाय किए गए। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इनके चलते कोविड-19 संक्रमण में जल्द ही अपेक्षित कमी आएगी। बुधवार को दिल्ली में कोविड 19 के 3714 नए मामले सामने आए जिससे इनकी संख्या 2.56 लाख के पार चली गई। दूसरी ओर, मृतक संख्या भी बढ़कर 5 087 हो गई। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में 60,000 से अधिक जांच की गई और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 30,836 थी।

ऑस्ट्रेलिया के...

उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सूत्र ने बताया, उन्हें इसके बाद गिरगांव के हरकिशन दास अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जोन्स का परिवार मेलबर्न में है और आस्ट्रेलियाई उच्चायोग उनके संपर्क में है। जोन्स ने अपने करियर के दौरान 44.61 की औसत से 6068 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय रन बनाए जिसमें सात शतक और 46 अर्धशतक शामिल रहे।

मोदी ने...

प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद कार्यक्रम से शामिल सभी हस्तियों से कहा कि वे भी अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ें। उन्होंने कहा, 'फिट इंडिया मूवमेंट दरअसल हिट इंडिया मूवमेंट भी है। इसलिए, जितना इंडिया फिट होगा, उतना ही इंडिया हिट होगा। इसमें आप सभी के प्रयास हमेशा की तरह देश की बहुत मदद करेंगे।

इन परिस्थितियों में लंबी पारी खेलने में मुश्किल हुई: रोहित शर्मा

अबुधाबी। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने स्वीकार किया कि संयुक्त अरब अमीरात की परिस्थितियों में लंबे समय तक बल्लेबाजी करने मे मुश्किल हो रही थी इसलिए उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ मैच विजई पारी खेलने के बाद थोड़ी थकान महसूस हुई। कप्तान रोहित ने 54 गेंद में 80 रन की पारी खेलकर गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दूसरे मैच में 49 रन से जीत दिलाई। रोहित ने मैच के बाद कहा, यहां लंबी पारियां खेलना आसान नही है। इन परिस्थितियो मे खेलने मे काफी मुश्किल होती है। अंत मे शायद मै थोड़ा थका था और हमारे लिए यह सबक था कि क्रीज पर जमे हुए बल्लेबाजो को अंत तक बल्लेबाजी करने की जरूरत होती है।

महज एक मैच के बाद कमिंस की आलोचना करना अनुचित: कार्तिक

अबुधाबी। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने कहा कि महज एक खराब प्रदर्शन के बाद उनके मुख्य तेज गेंदबाज पैट कमिंस की आलोचना किया जाना अनुचित है क्योंकि वह अपना पृथक्वास पूरा करने के बाद सीधा ही खेले थे। सभी की निगाहे कमिंस पर लगी थी जो विदेशी खिलाड़ियों मे सबसे ज्यादा राशि मे खरीदे गए थे लेकिन मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने उनकी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी और तीन ओवर मे 49 रन जुटा लिए। इससे केकेआर को बुधवार को 49 रन से हार का सामना करना पड़ा। कार्तिक ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस मे कहा, कमिंस की अभी आलोचना करना अनुचित है। वह अभी पृथक्वास से निकला है और साढ़े तीन-चार बजे के करीब ही उसे मैच मे खेलने की अनुमति मिली। उसके टीम मे होने से हम खुश है और मुझे नही लगता कि इस मैच मे हमे उसकी बिलकुल भी आलोचना करने की जरूरत है। वह विश्व चैम्पियन गेंदबाज है, मैने जो कुछ भी सुना है और देखा है कि वह इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों मे से एक है। मुझे उस पर भरोसा है और मुझे पूरा भरोसा है कि वह अच्छा करेगा।

पेयर को कोविड–19 पॉजिटिव आने के बावजूद हैम्बर्ग में खेलने की अनुमति दी गई

हैम्बर्ग। फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी बेनो पेयर का कहना है कि कोरोना वायरस की जांच मे दो बार पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद उन्हे हैम्बर्ग ओपन मे खेलने की अनुमति दी गई। पेयर बुधवार शुरूआती दौर के मैच मे रिटायर हो गए जब वह कैस्पर रड से पिछड़ रहे थे और एटीपी टूर ने कहा कि चक्कर आने की वजह से उन्होंने हटने का फैसला किया। पेयर ने कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद अमेरिकी ओपन से हटने का फैसला किया था और एक हफ्ते से ज्यादा का समय पृथक्वास मे बिताया।

राहुल ने जड़ा रिकार्ड शतक

● **रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ किंग्स इलेवन का बड़ा स्कोर**

भाषा। दुबई

69 गेंदों पर नाबाद 132 रन

कप्तान केएल राहुल के टी20 क्रिकेट में चौथे शतक की मदद से किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में गुरुवार को यहां तीन विकेट पर 206 रन बनाए। राहुल ने विराट कोहली से मिले दो जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और 69 गेंदों पर नाबाद 132 रन बनाए जो उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर भी है। उन्होंने अपनी पारी में 14 चौके और सात छक्के लगाए। उनका स्कोर आईपीएल में किसी भारतीय का सर्वोच्च स्कोर भी है। इससे पहले का रिकार्ड ऋषभ पंत (नाबाद 128) के नाम पर था।राहुल जब 83 और 89 रन पर थे तब कोहली ने उनके कैच छोड़े थे जिसका फायदा उठाकर उन्होंने आखिरी दो ओवरों में 49 रन जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। आरसीबी ने आखिरी चार ओवरों में 74 रन लुटाए। उसकी तरफ से युजवेंद्र चहल (25 रन देकर एक) ने प्रभाव छोड़ा लेकिन डेल स्टेन (चार ओवर 57 रन) और उमेश यादव (तीन ओवर 35 रन) ने निराश किया। राहुल और मयंक अग्रवाल (20 गेंदों पर 26) ने पारी की सहज शुरुआत की और ढीली गेंदों को सीमा रेखा तक पहुंचाया। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े। कोहली ने पिछले मैच की तरह पावरप्ले के बाद अपने तुरुप के इक्के चहल को गेंद सौंपी और उन्होंने फिर से कप्तान को निराश नहीं किया। अग्रवाल के पास चहल की गुगली का कोई जवाब नहीं था जो उनके बल्ले और पैड के बीच से विकेटों में समा गई। पारी का पहला छक्का राहुल ने उमेश पर लगाया। उन्होंने निकोलस पूरण (18 गेंदों पर 17) के साथ भी 57 रन की उपयोगी साझेदारी की। पूरण ने दुबे की गेंद पर आसान कैच थमाया। दुबे ने इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल (पांच) को भी आउट किया।

इस बीच राहुल का भाग्य ने भी साथ दिया। स्टेन की गेंद पर उन्होंने डीप मिडविकेट पर छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर उसी क्षेत्र में उछाली लेकिन कुशल क्षेत्ररक्षक कोहली ने अपेक्षाकृत आसान कैच टपका दिया। यही नहीं कोहली ने बाद में नवदीप सैनी की गेंद पर उनका कैच छोड़ा। इसका खामियाजा स्टेन और आरसीबी दोनों को भुगतना पड़ा। उन्होंने पारी के 19वें ओवर में स्टेन पर तीन छक्के और दो चौके लगाए और इस बीच न सिर्फ अपना शतक पूरा किया बल्कि टी20 में पिछला सर्वोच्च स्कोर (110) भी पीछे छोड़ा। स्टेन के इस ओवर में 26 रन बने। उन्होंने दुबे की पारी की आखिरी दो गेंदों पर छक्के लगाए और करुण नायर (नाबाद 15) के साथ 78 रन की अटूट साझेदारी की।

स्कोर

किंग्स इलेवन पंजाब : केएल राहुल नाबाद 132,मयंक अग्रवाल बो चहल 26,निकोलस पूरण का डिविलियर्स बो दुबे 17,ग्लेन मैक्सवेल का फिंच बो दुबे 05,करुण नायर नाबाद 15,**अतिरिक्त** (बाई 02, लेग बाई 04, नोबाल 01, वाइड 04) 11,कुल (20 ओवर में, तीन विकेट पर) 206,**विकेट पतन** :I-57, 2-114, 3-128 ,**गेंदबाजी**:उमेश 3-0-35-0,स्टेन 4-0-57-0,सैनी 4-0-37-0,चहल 4-0-25-I,सुंदर 2-0-13-0, दुबे 3-0-33-2

बल्लेबाजी क्रम में धोनी के स्थान पर विचार करेगी चेन्नई

● **अश्विन की चोट पर फैसला करेगी दिल्ली**

भाषा। दुबई

चेन्नई सुपर किंग्स शुक्रवार को आत्मविश्वास से भरी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपने तीसरे मुकाबले से पहले बल्लेबाजी क्रम में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर विचार करना चाहेगी। शारजाह की बल्लेबाजी की मुफीद पिच पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के लिए उनके स्पिनरों के खराब प्रदर्शन और निराशाजनक 20वें ओवर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है लेकिन बल्लेबाज खुद को पूरी तरह से इससे दोषमुक्त नहीं कर सकते विशेषकर मुरली विजय, केदार जाधव और खुद कप्तान धोनी।धोनी सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने सैम कुरेन, जाधव और रुतुराज गायकवाड़ को खुद से पहले बल्लेबाजी से भेजा लेकिन यह रणनीति उनके लिए बुरी तरह से विफल रही जिससे फाफ डु प्लेसिस पर कम समय में काफी ज्यादा रन बनाने का दबाव बढ़ गया। धोनी के प्रशंसक उनके छक्के जड़ने की काबिलियत के अब भी मुरीद हैं लेकिन करीब से देखा जाए तो वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से नहीं खेल पाए और जब मध्यम गति के गेंदबाज टॉम कुरेन गेंदबाजी करने उतरे तो ही धोनी आक्रामक हो सके। और वह भी मैच में तब हुआ जब मुकाबला ही खत्म हो चुका था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए शुरूआती मैच में जीत से उसके खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है, हालांकि रविचंद्रन अश्विन कंधे की चोट के कारण अनुपस्थित हो सकते हैं जिससे उन्हें अपने गेंदबाजी लाइन अप में कुछ फेरबदल करना पड़ सकता है। टीम के क्षेत्ररक्षण कोच मोहम्मद कैफ ने मैच की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा, हम आज के अभ्यास सत्र के बाद अश्विन पर फैसला करेंगे। वह ट्रेनिंग के लिए आ रहा है। हमारे फिजियो पैट्रिक फरहार्ट फैसला करेंगे। अगर अश्विन नहीं खेल पाते हैं तो सीनियर स्पिनर अमित मिश्रा को अक्षर पटेल के जोड़ीदार के तौर पर उतारने का विकल्प हो सकता है। कैफ ने आईपीएल के दूसरे सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले स्पिनर के बारे में कहा, यह अच्छी चीज है कि हमारे पास अमित मिश्रा जैसा गेंदबाज उनकी जगह लेने के लिए तैयार है जिन्हें काफी अनुभव है। बड़ी बाउंड्री से कलाई के स्पिनरों को गेंद को और अधिक उछालकर आक्रमण करने में मदद मिल सकती है। एक अन्य पहलू तेज गेंदबाज मोहित शर्मा के प्रदर्शन का होगा। मोहित ने शुरू में किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल को आउट किया था लेकिन अंत में उनकी लूज गेंदों से कैपिटल्स के लिए चीजें मुश्किल हो गई, हालांकि कागिसो रबाडा ने अंत में काफी कसी गेंदबाजी की। चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम अंतिम 10 ओवरों में आक्रमण करना पसंद करती है तो कैपिटल्स हर्षल पटेल को आजमा सकते है।

जोन्स के असामयिक निधन से क्रिकेट जगत स्तब्ध

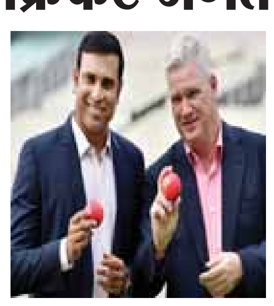

भाषा। नई दिल्ली

आस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डीन जोन्स का गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से अचानक निधन हो गया जिससे क्रिकेट जगत सकते में आ गया तथा क्रिकेटर से कमेंटेटर बने इस खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि खेल को हमेशा उनकी कमी खलेगी। जोन्स इंडियन प्रीमियर लीग के लिए स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम का हिस्सा थे और मुंबई में थे। वह 59 बरस के थे। भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, डीन जोन्स के निधन की खबर दिल तोड़ने वाली है। एक शानदार व्यक्ति काफी जल्दी चला गया। आस्ट्रेलिया के अपने पहले दौरे के दौरान उनके खिलाफ खेलने का मौका मिला। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने लिखा, डीन डीन्स के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। उनके परिवार और मित्रों के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री और पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी उनके निधन पर शोक जताया।आस्ट्रेलिया के मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों ने भी उनके निधन पर शोक जताया। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुआई कर रहे आस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने ट्वीट किया, मुझे इस खबर पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इस बारे में सुनकर काफी दुखी हूं। भगवान डीनो (जोन्स) की आत्मा को शांति दे, आपकी कमी खलेगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से खेल रहे आस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान आरोन फिंच ने कहा, डीनो के निधन की खबर सुनकर अब भी स्तब्ध हूं।

अंकिता फ्रेंच ओपन क्वालीफायर से बाहर

पेरिस। भारत की अंकिता रैना गुरुवार को यहां दूसरे दौर में जापान की कुरूमी नारा के खिलाफ सीधे सेटों में हार के साथ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट क्वालीफायर से बाहर हो गईं।भारत की शीर्ष एकल खिलाड़ी अंकिता को दूसरे दौर के मुकाबले में एक घंटे और 21 मिनट में 3–6 2–6 से शिकस्त का सामना करना पड़ा।अंकिता ने मैच के बाद कहा, मुकाबला बुरा नहीं था। मुझे अपनी सर्विस पर मौके मिले लेकिन आज उससे काफी अच्छा रिटर्न किया। अगर मैं उन गेम को जीतने में सफल रहती जो स्थिति अलग हो सकती थी। साथ ही आज काफी हवा भी चल रही थी। अंकिता की हार का मतलब है कि कोई भी भारतीय एकल खिलाड़ी क्ले कोर्ट पर होने वाले इस ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के एकल मुख्य ड्रॉ में हिस्सा नहीं लेगा। इससे पहले पुरुष एकल क्वालीफायर में सुमित नागल, रामकुमार रामनाथन और प्रजनेश गुणेश्वरन को हार का सामना करना पड़ा था। रोहन बोपन्ना और दिविज शरण अपने अपने साथियों के साथ पुरुष युगल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे।

छह महीने बाद क्रीज पर समय बिताकर अच्छा लगा : रोहित

भाषा। अबुधाबी

मुंबई इंडियन्स के कप्तान रोहित शर्मा ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में पहली जीत दर्ज करने पर राहत की सांस ली और साथ ही वह छह महीने के बाद क्रीज पर पर्याप्त समय बिताकर भी खुश दिखे। रोहित ने पुल शॉट का अच्छा प्रदर्शन करके 80 रन बनाए जिससे मुंबई पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर पांच विकेट पर 195 रन बनाने में सफल रहा। इसके जवाब में कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) नौ विकेट पर 146 रन ही बना पाया। रोहित ने मुंबई की 49 रन से जीत के बाद कहा, मैंने पुल शॉट खेलने का अच्छा अभ्यास किया था। मेरे सभी शॉट बहुत अच्छे थे इसलिए यह नहीं कह सकता कि मेरा कौन सा शॉट सबसे अच्छा था। मैंने पिछले छह महीने से ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली थी और मैं क्रीज पर कुछ समय बिताना चाहता था। पहले मैच में मैं अच्छा नहीं खेल पाया लेकिन खुशी है कि आज मैंने ऐसा किया। मुंबई की यूएई में यह छह मैचों में पहली जीत है। इससे पहले वह 2014 में अपने पांचों मैच गंवा बैठा था जबकि इस सत्र में वह पहले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स से हार गया था। मैन आफ द मैच रोहित ने कहा, जिस टीम ने 2014 में यहां पांच मैच गंवाए थे उसके केवल दो खिलाड़ी (असल में तीन रोहित, कीरन पोलार्ड और जसप्रीत बुमराह) वर्तमान टीम में हैं। हमने आज अपनी रणनीति पर अमल करने पर ध्यान दिया। विकेट अच्छा था और ओस भी पड़ रही थी।

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that the following documents related to property i .e Flat no.562, PKT-E, Mayur Vihar, Phase -2, Delhi-91 has been lost:a) Allotment letter dated 10.6.1986 issued by DDAb) Final Demand letter issued by DDA for the said flat. Anyone who found these two documents are requested to return to the owner of the said flat at Shri Anil Sanan, Flat no.562, PKT-E, Mayur Vihar, Phase-2, Delhi-91.
M. No. :9810048614

PUBLIC NOTICE
The public at large is hereby informed that late Mr. G.G.Arora s/o late Mr.Sita Ram r/o C-90,kalkaji, New Delhi-110019 was having commercial property in our project Vatika One on One,flat no 241,block no 4,sector16 and measuring 500 sq ft which his legal heirs Mrs. Kuldeep Arora (w/o Late Mr. G.G.Arora) Mrs. Sonali Arora(w/o late Mr. Gagan Arora: son), Miss Simran and Mr Raghav Arora (children of late Mr.Gagan Arora) and Mr.Pawan Arora (s/o late Mr.G.G.Arora requested the company to be transferred to Mr Pawan Arora. Any person having an objection on this please may contact the company officer details as under within 15 days after which NO CLAIM would be accepted. Vatika limited Vatika triangle, 4th floor, Sushant Lok-1, Block AMG road, Gurgaon, Haryana

PUBLIC NOTICE
The public at large is hereby informed that late Mr.G.G.Arora s/o late Mr.Sita Ram r/o C-90,kalkaji,New Delhi-110019 was having commercial property in our project Vatika Business Park ,flat no 425,block C,sector 49 and measuring 500sq ft which his legal heirs Mrs.Kuldeep Arora(w/o Late Mr.G.G.Arora)Mrs.Sonali Arora(w/o late Mr.Gagan Arora:son),Miss Simran and Mr Raghav Arora(children of late Mr.Gagan Arora) and Mr.Pawan Arora(s/o late Mr.G.G.Arora) requested the company to be transferred to Mr.Raghav Arora(grandson).Any person having an objection on this please may contact the company officer details as under within 15 days after which NO CLAIM would be accepted.Vatika limitedVatika triangle,4th floor,Sushant Lok-1,Block AMG road,Gurgaon,Haryana

PUBLIC NOTICE
The public at large is hereby informed that late Mr.G.G.Arora s/o late Mr.Sita Ram r/o C-90,kalkaji,New Delhi-110019 was having commercial property in our project Vatika Mindspace,Unit no 935,and measuring 500 sqft which his legal heirs Mrs.Kuldeep Arora(w/o Late Mr.G.G.Arora)Mrs.Sonali Arora(w/o late Mr.Gagan Arora:son),Miss Simran and Mr Raghav Arora(children of late Mr.Gagan Arora) and Mr.Pawan Arora(s/o late Mr.G.G.Arora) requested the company to be transferred to Mr Pawan Arora.Any person having an objection on this please may contact the company officer details as under within 15 days after which NO CLAIM would be accepted.Vatika limitedVatika triangle,4th floor,Sushant Lok-1,Block AMG road,Gurgaon,Haryana

PUBLIC NOTICE
The public at large is hereby informed that late Mr.G.G.Arora s/o late Mr.Sita Ram r/o C-90,kalkaji,New Delhi-110019 was having commercial property in our project Vatika Mindspace,Unit no 1104,and measuring 500 sqft which his legal heirs Mrs.Kuldeep Arora(w/o Late Mr.G.G.Arora)Mrs.Sonali Arora(w/o late Mr.Gagan Arora:son),Miss Simran and Mr Raghav Arora(children of late Mr.Gagan Arora) and Mr.Pawan Arora(s/o late Mr.G.G.Arora) requested the company to be transferred to Mr.Raghav Arora(grandson).Any person having an objection on this please may contact the company officer details as under within 15 days after which NO CLAIM would be accepted.Vatika limitedVatika triangle,4th floor,Sushant Lok-1,Block AMG road,Gurgaon,Haryana

ओएनजीसी के हजीरा संयंत्र में आग से आपूर्ति प्रभावित, दूसरे क्षेत्रों से गैस आपूर्ति शुरू की

नई दिल्ली। देश की प्रमुख तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी के गुजरात, सूरत के समीप गैस प्रसंस्करण इकाई में बृहस्पतिवार तड़के आग लगने के कारण बिजली और उर्वरक कंपनियों को ईंधन की आपूर्ति बाधित हुई। लेकिन कंपनी ने दूसरे उत्पादक क्षेत्रों से आपूर्ति शुरू कर इसकी कमी को दूर किया।ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के हजीरा गैस प्रसंस्करण संयंत्र में आग तड़के तीन बजे लगी। इसके बाद बचाव कार्य तुरंत शुरू कर सुबह 7.30 बजे काबू आगे पर काबू पा लिया गया। ओएनजीसी ने कहा कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हजीरा संयंत्र में लगी आग को पूरी तरीके से बुझा दिया गया है। कामकाज यथाशीघ्र शुरू करने को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। हजीरा संयंत्र को गैस ओएनजीसी के पश्चिमी तट के पश्चिमी अपतटीय बेसिन फील्ड और पन्नामुक्त और ताप्ती फील्ड से मिलती हैं। यहां 3.2 से 3.3 करोड़ घन मीटर गैस प्रतिदिन का प्रबंधन होता है। ओएनजीसी ने कामकाज सुरक्षित तरीके से शुरू करने को लेकर निदेशक (अपतटीय) राजेश कक्कर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को हजीरा भेजा है। व्यवस्था शुक्रवार से सुचारू होने की संभावना है।

रेफ्रिजरेटर बाजार में उतरी हैवेल्स

नई दिल्ली। उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल सामान कंपनी हैवेल्स रेफ्रिजरेटर बाजार में उतर गई है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को अपनी टिकाऊ उपभोक्ता सामान इकाई लॉयड के जरिए देश के रेफ्रिजरेटर बाजार में उतरने की घोषणा की। इस कदम के साथ लॉयड एक पूर्ण टिकाऊ उपभोक्ता सामान ब्रांड बन जाएगा। यह ब्रांड पहले से एयर-कंडीशनर, एलईडी टीवी और वॉशिंग मशीन खंड में मौजूद है। कंपनी ने कहा कि उसने 25 नए इन्वर्टर प्रौद्योगिकी आधारित डायरेक्ट कूल (डीसी), फ्रॉस्ट-फ्री और साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर मॉडल पेश किए हैं। कंपनी का इरादा दिवाली तक 25 और नए मॉडल उतारने का है। इसके अलावा लॉयड की योजना नवंबर में डिशवॉशर खंड में भी उतरने की है। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। ऐसे में डिशवॉशर जैसे उत्पादों की मांग बढ़ी है। लॉयड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शशि अरोड़ा ने कहा, आज हम डीसी, साइड-बाय-साइड, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर की श्रृंखला पेश कर रहे हैं। मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप कंपनी अपने रेफ्रिजरेटर की समूची श्रृंखला का उत्पादन भारत में ही करेगी। लॉयड के रेफ्रिजरेटर 190 से 587 लीटर क्षमता में उपलब्ध होंगे। इन मॉडलों की शुरुआती कीमत 10,000 रुपए से 84,990 रुपए होगी। इनमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के 2020 रेटिंग नियमों का अनुपालन किया जाएगा। एसी के बाजार में लॉयड शीर्ष तीन ब्रांड में है। हैवेल्स ने मई, 2017 में लॉयड का अधिग्रहण किया था।

महामारी समाप्त होने के बाद बाद भी घर से काम करने की व्यवस्था रहेगी जारी : गिल गेट्स

मुंबई। जानेमाने उद्योगपति और परामार्थ कार्यो से जुड़े बिल गेट्स ने बुधवार को कहा कि घर से काम करने की संस्कृति बेहतर तरीके से काम कर रही है और कई कंपनियां कोरोना वायरस महामारी समाप्त होने के बाद भी यह व्यवस्था जारी रखेंगी। गेट्स ने कहा, यह देखना अद्भुत है कि कैसे घर से काम करने की व्यवस्था काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि महामारी के समाप्त होने के बाद यह कार्य संस्कृति बनी रहेगी। उन्होंने इस साल अब तक काम के सिलसिले में यात्रा नहीं की।

एमएसएमई के लिए 1.77 लाख करोड़ का कर्ज मंजूर

● **ऋण गारंटी योजना के तहत 44 लाख को लाभ होगा**

भाषा। नई दिल्ली

वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि बैंकों ने आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 44.2 लाख कारोबारी इकाइयों के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण खास तौर से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मझोले (एमएसएमई) के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी। हालांकि, मंजूर किए गए कर्ज में से 21 सितंबर तक 25.74 लाख एमएसएमई इकाइयों को1,25,425 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। यह योजना लगभग 21 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का हिस्सा है। वित्त मंत्री ने कोविड-19 संकट से प्रभावित एमएसएमई समेत विभिन्न क्षेत्रों की सहायता के लिए इस पैकेज की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर लिखा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 21 सितंबर तक 100 प्रतिशत आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत एमएसएमई और व्यक्तियों को1,77,353 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी। इनमें से1,25,425 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 12, निजी क्षेत्र के 24 बैंकों और 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने ऋण की मंजूरी दी और वितरित किए। सरकार ने समय समय पर इस योजना का दायरा बढ़ाया है। इसमें 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले एमएसएमई को शामिल किया गया। वहीं अगस्त में व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत लोगों को भी इसके दायरे में लाया गया। डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवरों को व्यावसायिक कार्यों के लिए कर्ज दिया गया। मंत्रालय के अनुसार 21 सितंबर, 2020 तक 2.8 लाख लोगों के लिए 9,849 करोड़ रुपए कर्ज मंजूर किए गए। इसमें से 49,393 पेशेवरों को 2,617.08 करोड़ रुपए वितरित किए गए। सीतारमण ने कहा कि तीन सितंबर, 2020 की तुलना में मंजूर किए गए कर्ज में 16,335.32 करोड़ रुपए और वितरण में 11,711.85 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। कुल मंजूर किए गए कर्जों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी बढ़कर 79,347.73 करोड़ रुपए हो गई। इसमें से 65,051.89 करोड़ रुपए 21 सितंबर तक वितरित किए जा चुके हैं।

भारतीय आने वाले समय में खर्च को लेकर सतर्क, 10 में से 9 ने जताई चिंता: सर्वे

मुंबई। कोरोना वायरस संक्रमण में लगातार बढ़ते मामलों के साथ रोजगार और आर्थिक पुनरूद्धार को लेकर एक अनिश्चितता पैदा हो रही है और इसका असर खर्च पर भी दिख रहा है। एक सर्वे में देश में 10 में से 9 लोगों ने इसको लेकर चिंता जताई और आने वाले समय में खर्च को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही। ब्रिटेन के स्टैंर्न्डर्ड चार्टर्ड बैंक ने इस संदर्भ में वैश्विक स्तर पर एक सर्वे किया है। बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा, सर्वे में 90 प्रतिशत भारतीय प्रतिभागियों ने कहा कि महामारी ने उन्हें खर्च को लेकर सतर्क बना दिया है। सर्वे के अनुसार 76 प्रतिशत भारतीय प्रतिभागी यह महसूस करते हैं कि महामारी ने उन्हें अपने खर्चों के बारे में सोचने को मजबूर किया है।

निवेश सलाहकारों के लिए सलाहकार सेवाओं, वितरण गतिविधियों को अलग रखने के दिशानिर्देश जारी

नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेश सलाहकारों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बाजार नियामक ने निवेश सलाहकारों को ग्राहकों के स्तर पर सलाहकार सेवाओं और उत्पाद वितरण गतिविधियों को अलग रखने को सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा सेबी ने निवेश सलाहकारों द्वारा ग्राहकों से लिए जाने वाले शुल्क की अधिकतम सीमा भी तय की है। उसने लेखा परीक्षा और रिकॉर्ड रखने से संबंधित एक प्रक्रियात्मक रूपरेखा भी पेश की है। नियमों के तहत, एक व्यक्तिगत निवेश सलाहकार, गैर-व्यक्तिगत निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा और उसके पास 150 ग्राहक होने चाहिए जिन्हें वह सेवा देगा। निवेश सलाहकार को अपने ग्राहकों के साथ निवेश सलाहकार समझौता करना होगा। नियामक ने कहा कि निवेश सलाहकारों को सलाहकार और वितरण गतिविधि सेवाओं के मामले में ग्राहक के स्तर पर अलगाव के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ग्राहक के स्तर पर सेवाओं के मामले में पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए जो मौजूदा ग्राहक सलाहकार सेवाएं लेना चाहते हैं वह उसी निवेश सलाहकार के समूह अथवा पारिवारिक इकाइयों से वितरण सेवाएं लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

वोडाफोन, एयरटेल ने जून में खोए 59 लाख से अधिक ग्राहक, वहीं जियो ने जोड़े 45 लाख: ट्राई

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार उद्योग में दो पुरानी कंपनियों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) और एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है, जबकि रिलायंस जियो के उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि का क्रम बरकरार है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, जून में वीआईएल और एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में क्रमश: 48.2 लाख और 11.3 लाख की गिरावट आई। हालांकि, इस दौरान जियो के ग्राहकों की संख्या में करीब 45 लाख की वृद्धि हुई।

रुपया 32 पैसे टूटकर करीब एक माह के निचले स्तर पर

नई दिल्ली। कोविड-19 के मामलों में निरंतर वृद्धि को लेकर बढ़ती चिंताओं और घरेलू शेयर बाजार में भारी बिकवाली की घटनाओं के बाद विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की भारी गिरावट के साथ करीब एक माह के निम्न स्तर 73.89 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इसके अलावा प्रमुख वैश्विक मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने तथा घरेलू बाजार से विदेशी निधियों की भारी धन निकासी से बाजार की धारणा प्रभावित हुई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर रुख के साथ 73.82 पर खुला तथा कारोबार के दौरान 73.75 से 73.96 रुपए के दायरे में घूमने के बाद अंत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 32 पैसे की भारी गिरावट को दर्शाता 73.89 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

Public Notice
Be known to all that my client, SMT. JASBIR KAUR W/O SH. GURCHARAN SINGH R/O 55-A, UDAY PARK, NEW DELHI, is the owner of PROPERTY BEARING NO.55-A, UDAY PARK, NEW DELHI, and my client have applied for Substitution and Conversion of leasehold to freehold in respect of said property. The original document i.e. RECOMMENDATION LETTER, DEMANDCUM-ALLOTMENT LETTER, POSSESSION LETTER, POSSESSION SLIP, DFORM and SACNTIONED PLAN, of the above said property have been lost or misplaced by my client and is not traceable inspite of her best efforts. An FIR/NCR to this effect has been lodged in the Police Station, Crime Branch, Delhi (LR No.600129/2020 dated 24.09.2020).
Any person(s) claiming any rights, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/Phone No.9811041585 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to Deputy Director LAB(Residential) or Director LAB (Residential), Vikas Sadan, New Delhi.
Naveen Aggarwal (Advocate)
Ch. No. M-7, Near SBI, Western Wing Tis Hazari Court Delhi-54

PUBLIC NOTICE
Our client MR. ASGHAR JAVED KHAN (ASGHAR KHAN) S/O LATE BABU NOOR MOHD. KHAN, R/O 579/10, GALI NO. 10. ZAKIR NAGAR, NEW DELHI-110025, has served that he has disown and declared from his all immoveable and moveable property to his son MR. SALMAN KHAN and his daughter MS. SAMREEN KHANAM (SHAZIA) W/O MR. FAKHRUDDIN ALI AHMAD and any relationship from them our client shall not be responsible for their acts, deeds and things doing by them.
MD. IRFAN (ADVOCATE)
Chamber No. 362,
Lawyers Chamber Block,
Saket Court, New Delhi
Dated: 23.09.2020

यांग पियांग आइस लैंड पर दक्षिण कोरिया का जहाज। सियोल के अनुसार यहां से उनका एक अधिकारी मछली मारते समय गायब हो गया था जो उत्तर कोरियाई क्षेत्र में मृत मिला था

ट्रम्प ने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को लेकर प्रतिबद्धता जताने से किया इनकार

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तीन नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में हार की स्थिति में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को लेकर प्रतिबद्धता जताते से इनकार कर दिया और ईमेल या डाक के जरिए मतदान (मेल-इन-बैलेट) को लेकर संदेह व्यक्त करते हुए इसे अनर्थ करार दिया।

व्हाइट हाउस में बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में ट्रम्प से सवाल किया गया कि चुनाव में हार मिलने की स्थिति में क्या वह व्हाइट हाउस शांतिपूर्वक छोड़ देंगे? इसके जवाब में ट्रम्प ने कहा, हम देखेंगे कि क्या होता है।ट्रम्प ने कहा, मैं ईमेल या डाक के जरिए मतदान को लेकर लगातार शिकायत करता रहा हूं और यह अनर्थ है..।

उनसे पूछा गया था, राष्ट्रपति जी, चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, भले ही जीत हो, हार हो या मुकाबला बराबरी का रहे, क्या आप चुनाव के बाद सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का आज यहां वादा करते हैं? ट्रम्प के जवाब से संतुष्ट ना होने पर पत्रकार ने फिर पूछा, क्या आप सत्ता के शांतिपूर्ण

हस्तांतरण का वादा करते हैं?

इसके जवाब में, ट्रम्प ने सत्ता में दोबारा आने का विश्वास जाहिर किया। राष्ट्रपति ने कहा, हम ईमेल या डाक के जरिए मतदान की व्यवस्था से छुटकारा चाहते हैं। सब शांतिपूर्ण रहेगा। सत्ता का कोई हस्तांतरण नहीं होगा। सच कहूं तो यही सरकार बरकरार रहेगी। ट्रम्प ने उनसे इस संबंध में सवाल करने वाले पत्रकार के और प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार कर दिया।सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को लेकर प्रतिबद्धता संबंधी ट्रम्प की टिप्पणी के बारे में पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा, हम किस देश में हैं? उन्होंने सबसे तर्कहीन बात की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पर क्या कहूं? इससे पहले भी ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार के दौरान चुनाव परिणाम स्वीकार करने को लेकर प्रतिबद्धता नहीं जताई थी और कहा था, मुझे देखना होगा।

ट्रम्प ने कहा, मैं मेगन का प्रशंसक नहीं, हैरी को दी शुभकामनाएं

वाशिंगटन। अमेरिका के नागरिकों से मतदान की अपील को लेकर टाइम द्वारा बनाई 100 वीडियो में ससेक्स ऑफ डचेस मेगन मर्केल और प्रिंस हैरी द्वारा भाग लिए जाने के बाद बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मर्केल पर निशाना साधा। वीडियो के बारे में पूछे जाने पर ट्रम्प ने कहा कि मैं उनका (मर्केल) प्रशंसक नहीं हूं......मैं प्रिंस हैरी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, उन्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। मूल रूप से अमेरिकी मेगन ने वीडियो में चार साल में आने वाले चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, जब हम मतदान करते हैं, तो हमारे मूल्यों पर अमल होता है और हमारी आवाज सुनी जाती है। ससेक्स ऑफ ड्यूक प्रिंस हैरी ने अमेरिकियों से अभद्र भाषा, गलत सूचना और ऑनलाइन नकारात्मकता को अस्वीकार करने की अपील की।

मेगन और हैरी में से किसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन का नाम नहीं लिया लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा अंदाजा लगाया है कि वे अपने बयान से ट्रम्प पर निशाना साध रहे थे। व्हाइट हाउस में इस वीडियो के संबंध में सवाल किए जाने पर ट्रम्प ने कहा, मैं उनका प्रशंसक नहीं हूं और उन्होंने (मेगन ने) यह सुना भी होगा। लेकिन मैं हैरी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उन्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है।

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पोते हैरी ने लॉस एंजिलिस में पली-बढ़ी अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मर्केल से 2018 में एक शाही समारोह में शादी की थी। जनवरी में इस दम्पत्ति ने शाही परिवार छोड़ने और उत्तरी अमेरिका में बसने की घोषणा की थी।

व्यापक मतभेदों के चलते सुरक्षा परिषद विस्तार के लिए पैकेज समाधान की आवश्यकता: चीन

भाषा। बीजिंग

सुरक्षा परिषद में भारत के प्रवेश को लेकर अड़ंगा लगाते रहे चीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र की इस शक्तिशाली इकाई के विस्तार संबंधी सुधारों को लेकर व्यापक मतभेद हैं तथा इसके लिए ऐसे पैकेज समाधान की आवश्यकता है जिसमें सभी पक्षों के हित और चिंताएं समाहित हो सकें।

भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील की सदस्यता वाले जी-4 समूह ने सुरक्षा परिषद के लंबे समय से लंबित सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सार्थक कदमों की कमी को लेकर बुधवार को चिंता जताई और मुद्दे के तत्काल समाधान की मांग की।विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित जी-4 देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र से इतर एक डिजिटल बैठक की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता पर गहन चर्चा की। जयशंकर ने बुधवार को बैठक के बाद ट्वीट किया, तय समयसीमा में विषय वस्तु आधारित चर्चा के लिए सर्वसम्मत आह्वान। जी-4 विदेश मंत्रियों के आह्वान के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमारा मानना है कि सुरक्षा परिषद में सुधार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो दीर्घकालिक विकास और इसके सदस्यों के सभी तात्कालिक हितों से जुड़ा है। उन्होंने कहा, मुद्दे पर व्यापक मतभेद रहे हैं और सुधार के लिए प्रबंधन पर व्यापक सर्वसम्मति की कमी है। चीन पैकेज समाधान प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्यों के साथ काम करने की इच्छा रखता है जिसमें वार्ता और चर्चा के माध्यम से सभी पक्षों के हित और चिंताएं समाहित की जा सकें। जी-4 देशों ने बुधवार को प्रेस को जारी संयुक्त बयान में समकालीन मामलों को बेहतर ढंग से रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र और इसकी मुख्य निर्णयकारी इकाइयों में तत्काल सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया।भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, जी4 देशों के विदेश मंत्रियों ने इस (सुधार) प्रक्रिया को पटरी से उतारने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की और संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस विषय पर जल्द ही सार्थक कदम उठाने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र के 75वें वर्ष में भारत अगले साल एक जनवरी से सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के रूप में अपने दो साल के कार्यकाल की शुरुआत करेगा। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों का दशकों से नेतृत्व करता रहा है। उसका कहना है कि 1945 में गठित इकाई 21वीं सदी की समकालीन हकीकतों को नहीं दर्शाती और यह वर्तमान चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्षम नहीं है।सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता का भारत प्रबल दावेदार रहा है और उसे स्थाई सीट के लिए इस इकाई के पांच स्थाई सदस्यों में से चार-अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस सहित व्यापक समर्थन प्राप्त है। परिषद के पांच स्थाई सदस्यों में चीन भी शामिल है जिसे वीटो शक्ति प्राप्त है। वह स्थाई सदस्यता के भारत के प्रयासों में वर्षों से अड़ंगा लगाता आ रहा है।

ट्रंप चीन के साथ निष्पक्ष व संतुलित संबंध चाहते हैः पोम्पिओ

वाशिंगटन। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ एक निष्पक्ष और संतुलित संबंध चाहते हैं, जहां एक देश दूसरे देश के लिए अथवा अन्य देशों की आजीविका के लिए खतरा नहीं बने।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में चीन के साथ व्यापार युद्ध शुरू किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए। ट्रंप ने चीन से व्यापार घाटे को कम करने के लिए कहा था जो कि 2017 में 375.6 अरब अमेरिकी डॉलर था। कोविड-19 महामारी के बाद से चीन और अमेरिका के संबंध और भी बिगड़ गए। ट्रंप बार-बार कोरोना वायरस को चीनी वायरस बता रहे हैं और उनका कहना है कि चीन इस महामारी से सही तरह से नहीं निपट पाया, हालांकि चीन इस आरोप से इनकार करता रहा है।विस्कोन्सिन स्टेट कैपिटोल में बुधवार को विस्कोन्सिन के सीनेटर रोगर रोथ के साथ चर्चा के दौरान पोम्पिओ ने कहा कि अमेरिका के पास जो

भी रास्ते हैं, उसे उसका इस्तेमाल करना है और इसमें अमेरिका चीन से निष्पक्ष और परस्पर संबधों की मांग कर सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चीन के साथ एक निष्पक्ष और संतुलित संबंध चाहते हैं, जहां एक देश दूसरे देश के लिए अथवा अन्य देशों की आजीविका के लिए खतरा नहीं बने।

भारतीय-अमेरिकियों को ट्रम्प की ओर खींच रहे हैं 12 कारण : सर्वेक्षण

भाषा। वॉशिंगटन

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय-अमेरिकी 12 कारणों से देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थन में आगे आ रहे हैं, जिनमें से एक कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मित्रता है। ट्रम्प के चुनाव प्रचार अभियान में लगे एक दल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह दावा किया गया है। ट्रम्प विक्ट्री इंडियन अमेरिकन फाइनेंस कमेटी के सह अध्यक्ष अल मैसन और उनके दल के सर्वेक्षण के अनुसार देश के पूर्व राष्ट्रपतियों और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के विपरीत ट्रम्प प्रशासन भारत के आंतरिक मामलों, खासकर कश्मीर जैसे मामलों से दूर रहा है। इसके अलावा वैश्विक मंच पर भारत का दर्जा उंचा करने में ट्रम्प की स्पष्ट भूमिका एक अन्य अहम कारण है।

● भारत व अमेरिका के संबंध मजबूत हैं भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का श्रेय ट्रम्प और मोदी को जाता है

सर्वेक्षण में कहा गया है, यह मुख्य रूप से ट्रम्प-मोदी फैक्टर के बारे में है। इसमें कहा गया है कि भारतीय-अमेरिकियों का काफी हद तक यह मानना है कि आगामी चार साल में मोदी और ट्रम्प के मिलकर काम करने से वैश्विक मंच पर चीन को रोकने में मदद मिलेगी।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि इनके अलावा, चीन के खिलाफ ट्रम्प के कड़े रवैए, देश को युद्ध की स्थिति में ले जाने के बजाए शांति कायम करने की कोशिश करने , कोविड-19 से पहले अमेरिका का आर्थिक पुनरुद्धार और वैश्विक महामारी से उचित तरीके से निपटने आदि के कारण भारतीय-अमेरिकी ट्रम्प की ओर आकर्षित हो रहे हैं।इसमें कहा गया है, ट्रम्प ने वैश्विक मंच पर भारत का दर्जा बढ़ाया है। निस्संदेह, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका को लेकर दक्ष नीति को जाता है। भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हैं। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का श्रेय ट्रम्प और मोदी को जाता है।

सर्वेक्षण में कहा गया है, भारत में हर भारतीय-अमेरिकी के माता-पिता, भाई, बहन, मित्र हैं या कोई कारोबार है। वे चाहते हैं कि भारत का सम्मान हो और उसकी चीन से रक्षा हो। ट्रम्प ऐसा कर सकते हैं। उन्हें डर है कि ट्रम्प की गैरमौजूदगी में, चीन भारत के साथ युद्ध शुरू कर सकता है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि संभावित भारतीय अमेरिकी मतदाताओं में से 50 प्रतिशत मतदाता ट्रम्प के पक्ष में मतदान करेंगे।

सियोल में प्रेसवार्ता के दौरान दक्षिण कोरिया के सेना के उच्चाधिकारी

दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर लगाया अधिकारी की हत्या का आरोप

सियोल। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर उसके एक अधिकारी की हत्या का आरोप लगाया और उत्तर कोरिया से दोषियों को सजा देने की अपील की। अंतर-कोरियाई समुद्री सीमा में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए तैनात दक्षिण कोरियाई नौका से सोमवार को एक सरकारी अधिकारी लापता हो गया था। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लापता अधिकारी मंगलवार दोपहर उत्तर कोरियाई तट पर था। अधिकारी वहां कैसे पहुंचा इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है और बृहस्पतिवार को मंत्रालय की ओर से जारी अद्यतन जानकारी में भी यह नहीं बताया गया कि उसकी मौत कैसे हुई। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम विभिन्न खुफिया जानकारियों के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह उत्तर कोरिया की नृशंस हरकत है और दक्षिण कोरिया इसकी कड़ी निंदा करता है।

हमारे क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे आतंकवाद की समस्या की जड़ तक पहुंचने की जरूरत है : गनी

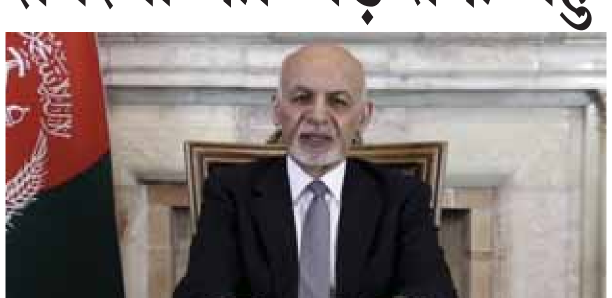

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम चर्चा में अपने रिकॉर्डेड संदेश में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी गनी

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बुधवार कहा कि अफगानिस्तान में स्थाई शांति कायम करने के लिए, हमारे क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे आतंकवाद की समस्या की जड़ तक पहुंचने और इससे एक वैश्विक खतरे के तौर पर निपटने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम चर्चा में अपने रिकॉर्डेड संदेश में गनी ने उन मुद्दों पर चर्चा की, जिससे उनका युद्धग्रस्त देश पिछले कई वर्षों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा, युद्ध और हिंसा के तरीकों में बदलाव आया है, जिसे हमने झेला है और अब भी झेल रहे हैं। वैश्विक आंतकवाद का एक नया रूप सामने आया है जिसमें हम जी रहे हैं और मर रहे हैं, जिसमें वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क, वैश्विक आपराधिक नेटवर्क के साथ निकटता से जुड़ा है, जिससे युद्ध पूरी तरह से गैर परम्परागत हो गए हैं तथा शांति-निर्माण और चुनौतीपूर्ण बन गया है। गनी ने कहा कि एक देश और समाज के तौर पर अफगानिस्तान ने तालिबान के साथ सीधी शांति वार्ता शुरू करने जैसा कठोर निर्णय लेने का साहस दिखाया। उन्होंने कहा, यह काफी नहीं होगा। अफगानिस्तान में स्थाई शांति कायम करने के लिए , हमारे क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे आतंकवाद की समस्या की जड़ तक पहुंचने और इससे एक वैश्विक खतरे के तौर पर निपटने की जरूरत है।

वैश्विक महामारी से निपटने के लिए समन्वय नहीं होने पर संरा चिंतित

संयुक्त राष्ट्र। विश्व के नेताओं ने दुनिया भर में करीब 10 लाख लोगों की जान ले चुकी और आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने में अंतरराष्ट्रीय समन्वय नहीं होने पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली उच्चस्तरीय डिजिटल बैठक में विश्व के नेताओं के पहले से रिकॉर्ड भाषणों में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी और उसके परिणामों पर बुधवार को चिंता जताई गई।कजाखस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकाएव ने इसे वैश्विक सहयोग का बुरी तरह ध्वस्त हो जाना करार दिया और घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो अडो ने कहा, हमारी दुनिया ही पलट गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में विभिन्न सदस्य देशों ने अंतरराष्ट्रीय समन्वय के अभाव के कारण इस महामारी से निपटने में पेश आ रही चुनौतियों एवं संघर्षों का उल्लेख किया। फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो ने कहा, वैश्विक महामारी एक वैश्विक चुनौती होती है और इससे निपटने के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, लेकिन कोविड-19 ने यह खुलासा कर दिया है कि हम इन खतरों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ही काम करना चाहते हैं।

पाकिस्तान सरकार ने शाहबाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज कराया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने नेता प्रतिपक्ष शाहबाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ सात अरब रुपए के धनशोधन का मामला दर्ज कराया है। शाहबाज (69) पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और 2008 से 2018 के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं।समाचार पत्र डॉन की खबर के मुताबिक गृह और जवाबदेही मामलों के लिए प्रधानमंत्री के सलाहकार शहजाद अकबर ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) पीएमएमल-एन के अध्यक्ष शाहबाज और उनके बेटे हम्जा तथा सलमान फर्जी खातों के जरिए धनशोधन के मामलों में संलिप्त हैं लेकिन वह (शाहबाज) हमेशा यह कहते रहे हैं बेटों के कारोबार से उनका कोई-लेना देना नहीं है। अकबर ने कहा, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने एक मामला दर्ज किया है, जिसमें शाहबाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ लाहौर की एनएबी अदालत में सात अरब रुपए के धनशोधन का आरोप लगाया गया है।

संयुक्त राष्ट्र ने बाल विवाह, जबरन विवाह रोकने के लिए भारत की पहलों और नीतियों का संज्ञान लिया

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

बाल विवाह एवं जबरन विवाह पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की एक रिपोर्ट में भारत में लिंग एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने संबंधी राष्ट्रीय नीतियों और क्षमता निर्माण की पहलों का संज्ञान लिया गया है। जून 2018 से मई 2020 की अवधि के लिए बाल, समय पूर्व और जबरन विवाह का मुद्दा पर महासचिव एंतोनियो गुतारेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देशों ने विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के लिए विधाई एवं नीतिगत उपाय लागू किए हैं और बाल, सही उम्र से पहले एवं जबरन विवाह को रोकने के लिए समग्र रणनीतियां अपनाई हैं। रिपोर्ट में बाल विवाह, सही उम्र से पहले विवाह और जबरन विवाह को रोकने के लिए विश्वभर में की गई प्रगति की समीक्षा की गई है।इसमें कहा गया है, इथियोपिया, घाना, भारत, मोजाम्बिक, नाइजर और युगांडा ने बाल विवाह,सही उम्र से पहले विवाह और जबरन विवाह झेलने वाली लड़कियों

● रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएनएफपीए-यूनीसेफ ग्लोबल प्रोग्राम टू एक्सेलरेट एक्शन टू एंड चाइल्ड मैरेज ने भारत में पश्चिम बंगाल के कन्याश्री प्रकल्प कार्यक्रम को समर्थन दिया

समेत लिंग एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय नीतियां विकसित कीं, दिशा-निर्देश जारी किए और क्षमता निर्माण पहलें शुरू कीं। रिपोर्ट में विवाहित लड़कियों एवं महिलाओं संबंधी नीतियों की भी बात की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत में लाडली सम्मान मुहिम के तहत महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजना और परामर्श देने की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएनएफपीए-यूनीसेफ ग्लोबल प्रोग्राम टू एक्सेलरेट एक्शन टू एंड चाइल्ड मैरेज ने भारत में पश्चिम बंगाल के कन्याश्री प्रकल्प कार्यक्रम को समर्थन दिया। इसके तहत बाल विवाह रोकने और शिक्षा जारी रखने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण को प्रोत्साहित किया गया।भारत में स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान ने विवाहित लड़कियों को सशक्त बनाने में योगदान दिया और उन्हें स्वास्थ्य, शैक्षणिक, आर्थिक एवं कानूनी सहायता तक पहुंच का मौका मिला। यूनीसेफ के अनुसार पिछले एक दशक में दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा की दर बढ़ने और बाल विवाह के नुकसान और इसकी अवैधता के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा किए जाने के कारण दो करोड़ 50 लाख बाल विवाह रोके गए।

ट्रेंड बाजार

भूमि पेडनेकर ने की अपनी फिल्म की 'स्पेशल सिस्टर स्क्रीनिंग'

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर अपनी नई फिल्म 'डॉली किटी और वो चमकते सितारे' अपनी बहन समीक्षा पेडनेकर के साथ देखना चाहती हैं और वो इसे स्पेशल 'सिस्टर स्क्रीनिंग' बताती हैं। भूमि बताती हैं, 'समीक्षा और मैं इसी सप्ताह रिलीज़ होने वाली इस फिल्म को साथ बैठकर देखना चाहते हैं। हमने पहली बार साथ में फिल्म बूसान में देखी थी और मेरी फिल्मी यात्रा मेरी बहन के साथ के बिना नहीं हो सकती थी। वहां हमारा अच्छा समय बीता था। इस बार भी हमनें साथ में फिल्म देखने का निर्णय लिया है और ये मेरे लिए 'स्पेशल सिस्टर स्क्रीनिंग' होगी।'

गुरमीत कौर को कोविड-19 का भय

गुरमीत चौधरी का कहना है कि 'द वाईफ' नाम की फिल्म को इस महामारी के दौर में पूरा करना हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हमारी प्रमुख चिंता ये थी कि यदि हममें से किसी को कोविड-19 संक्रमण हो जाता है तो शेष लोगों को 21 दिन का पृथक वास व्यतीत करना होगा और फिर फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ेगा। यदि कोविड-19 संक्रमण के प्रकरण बढ़े तो ये चक्र तो चलता ही रहेगा।'

रणवीर सिंह बहिर समुदाय की मदद को आए आगे

सुपरस्टार रणवीर सिंह संबंधित अधिकारियों से 'इंडियन साइन लैंग्वेज' अर्थात भारतीय संकेत भाषा को भारत की 23वीं आधिकारिक भाषा का स्थान देने पर विचार करने का आग्रह करते रहे है। हाल ही में उन्होंने इस लक्ष्य के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर किये हैं। रणवीर का अपना रिकॉर्ड लेबल 'इंकइंक' जो उन्होंने नवज़ार ईरानी के साथ मिलकर बनाया है, ने साइन लैंग्वेज में एक म्यूज़िक वीडियो भी रिलीज़ किया। इस अभिनेता के इन प्रयासों के समर्थन में भारतीय बहिर समुदाय ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक वीडियो बनाकर उनकी प्रशंसा की।

एली गोल्डिंग में थी आत्मविश्वास की कमी

एली गोल्डिंग वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय गायक हैं और उन्हें दो ब्रिट अवार्ड मिल चुके हैं तथा ग्रैमी तथा गोल्डेन ग्लोब अवार्ड के लिए भी अतीत में उनका नामांकन किया जा चुका है। उनके लिए सिलेब्रिटी बनना सरल नहीं रहा। वो पहले भी बता चुके हैं कि उनमें पहले वो आत्मविश्वास नहीं हुआ करता था जो आज दिखता है।

एली ने बताया, 'मैं 14 साल की आयु से ही गायक बनना चाहता था। मुझे लगता है कि मैं सदा से गाता, गिटार बजाना, संगीत लेख तथा स्वयं को परफॉर्म करते हुए कल्पना लोक में खोया रहा हूं। लेकिन मुझमें उन दिनों उतना आत्मविश्वास नहीं हुआ करता था और मुझे बस इसी पर काम करना शेष था। हमें इतना सम्मान और चर्चा मिलने से पहले स्वयं पर काफी काम करना पड़ता है।'

'अ प्रॉमिस्ड लैंड' में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक़ ओबामा ने बताई अपनी कहानी

अपनी पहचान की तलाश करते एक युवा से लेकर स्वतंत्र दुनिया के नेता बनने तक बराक ओबामा ने राष्ट्रपति के रूप में अपने जीवन वृतांत 'अ प्रामिस्ड लैंड' में अपनी राजनीतिक शिक्षा से लेकर अपने पहले कार्यकाल के अविस्मरणीय क्षणों का उल्लेख किया है जो उनके अनुसार नाटकीय परिवर्तन तथा अशांति का समय था।

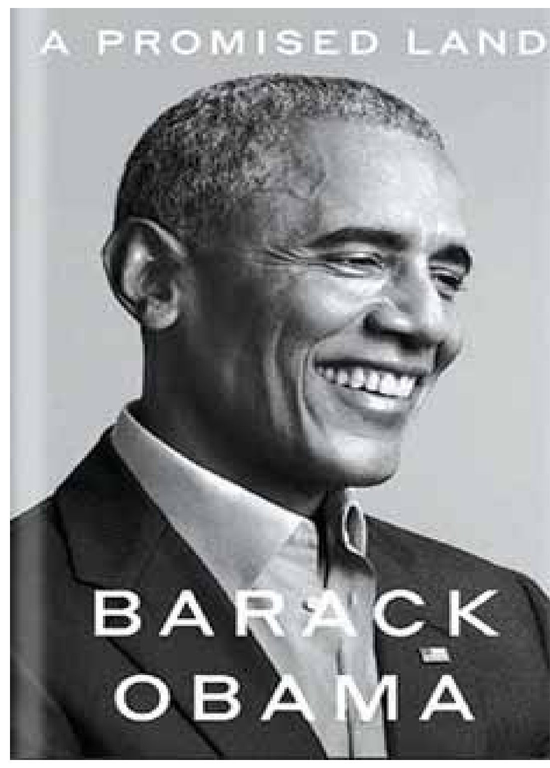

बराक़ ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे और उनके इस जीवन वृतांत को दो खंडों में प्रकाशित किया जाएगा। पहले खंड का शीर्षक 'अ प्रामिस्ड लैंड' रखा गया है और इसका प्रकाशन पेंग्विन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा और इसे 25 भाषाओं में निर्गत किया जाएगा। इसके दूसरे खंड के प्रकाशन के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा।

इसमें ओबामा ने अपनी उस असंभव सी लगने वाली लंबी यात्रा की कहानी कही है। अपनी पहचान की तलाश करते एक युवा से लेकर स्वतंत्र दुनिया के नेता बनने तक बराक ओबामा ने इसमें अपनी राजनीतिक शिक्षा से लेकर अपने पहले कार्यकाल के अविस्मरणीय क्षणों का उल्लेख किया है जो उनके अनुसार नाटकीय परिवर्तन तथा अशांति का समय था।

उन्होंने इस व्यक्तिगत विवरण में उस इतिहास का वर्णन किया है जो उस समय बन रहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसमें अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक क्षणों से लेकर लोवा कॉकस विजय जिसने जमीनी कार्य की शक्ति को निरूपित किया और इसके बाद 4 नवंबर 2008 का वो क्षण आया। वो अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति चुने गए और इस प्रकार वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले पहले एफ्रो-अमेरिकी बने।

अपने कार्यकाल के बारे में बताते हुए उन्होंने राष्ट्रपति की अभूतपूर्व शक्तियों तथा अमेरिका की भेदभावपूर्ण राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भी विवरण दिया है। एक प्रकार से ओबामा ने इस प्रकाशन के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के ओवल कार्यालय, वाइट हाउस के सिचुयेशन कक्ष से लेकर मास्को, काइरो, बीजिंग तथा और आगे लेकर जाते हैं। उन्होंने किस प्रकार अपने कैबिनेट का चयन किया, वैश्विक वित्तीय संकट पर उनके विचार तथा व्लादिमिर पुतिन के साथ व्यवहार के बारे में भी इसमें गहन विवेचना की गई है। उन्होंने किस प्रकार अफोर्डेबल केयर ऐक्ट पास कराया, अफगानिस्तान के बारे में अमेरिकी रणनीति को लेकर सेना के जनरलों से संघष, वॉल स्ट्रीट सुधार, डीप वॉटर होराइज़न से लेकर ऑपरेशन नेप्ट्यून्स स्पीयर के बारे में भी अंतदृष्टि प्रस्तुत की है जिसके कारण ओसामा बिन लादेन को मारने में सफलता मिली।

ये जीवन वृतांत अंतरंग और अंतर्मनन से परिपूर्ण दिखता है। इसमें एक व्यक्ति की इतिहास से संघर्ष की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। सामुदायिक स्तर पर काम करने वाले एक संगठनकर्ता की निष्ठा का किस प्रकार वैश्विक धरातल पर परीक्षण किया गया, के बारे में विवरण दिया गया है। ओबामा ने बड़े साहस से इसे स्वीकार किया है कि उन्होंने उस चुनाव में स्वयं को ब्लैक अमेरिकी के रूप में प्रस्तुत कर चुनाव में एक विजेता संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया था। और किस प्रकार उनका नारा 'आशा और परिवर्तन' चुनावों में चर्चा और परिचर्चा का हिस्सा बना। उन्होंने इसका भी उल्लेख इसके प्रथम खंड में किया है कि अमेरिका और बाहर की शक्तियों ने किस प्रकार उनके चुनाव में विरोध किया था। वाइट हाउस में रहते हुए उनकी पत्नी और पुत्री के जीवन का जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ, के बारे में भी इसमें विवरण है। लेकिन इसके बावजूद उनका ये विश्वास अडिग रहा कि इस अमेरिकी महाप्रयोग में भी प्रगति और विकास सदा संभव हैं।

इस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'किसी पुस्तक को पूर्ण करने जैसी भावना का अस्तित्व नहीं होता लेकिन मुझे इसपर गर्व है। मैंने पिछले कुछ वर्ष राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल के बारे में सोचने में बिताए हैं और इस पुस्तक 'अ प्रॉमिस्ड लैंड' में मैंने राष्ट्रपति चुनाव अभियानों, अपने कार्यकाल, महत्वपूर्ण घटनाओं तथा उन्हें आकार देने वालों, अपने सही निर्णयों के संबंध में विचार और उन त्रुटियों के बारे में जो मुझसे हुई, उन राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक शक्तियों जिनसे मुझे और मेरी टीम को जूझना पड़ा, के बारे में बताया है। मैंने इस पुस्तक में अपने पाठकों को अपनी और मिशेल की व्यक्तिगत यात्रा के बारे में भी बताने का प्रयास किया है। और अंत में आज जब अमेरिका एक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसमें मैंने अपने कुछ वृहद विचारों को समाहित किया है जिनसे आज अपने देश में हो रहे विविध विभाजनों को समाप्त किया जा सकता है ताकि लोकतंत्र का लाभ हर व्यक्ति को मिल सके। ये वो कार्य है जो केवल किसी एक राष्ट्रपति तक ही सीमित नहीं है बल्कि हम सभी नागरिकों को भी इसमें जुटना होगा। मुझे विश्वास है कि इसकी कंटेंट सूचनात्मक और रोचक होने के साथ ही विश्व भर के युवाओं को कम से कम दायित्व अपने हाथ में लेने, आवाज उठाने और विश्व को श्रेष्ठ स्थान बनाने के लिए प्रेरित अवश्य करेगी।'

(इस पुस्तक 'अ प्रॉमिस्ड लैंड' का प्रकाशन 17 नवंबर को होना है)

आयुष्मान खुराना टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों की सूची में

अभिनेता आयुष्मान खुराना को अभिनेता के रूप में उनके योगदान के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अमेरिका की टाइम मैगजीन ने प्रशंसा की है। 2020 में सर्वाधिक प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में पांच भारतीयों- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, लंदन आधारित भारतीय मूल के चिकित्सक रवीन्द्र गुप्ता जिन्होंने एड्स के उपचार के लिए काम किया तथा बिलकीस दादी, जो सीएए के विरोध में शाहीनबाग में अग्रणी भूमिका में रहीं।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता को कलाकार की श्रेणी में रखा गया जिसमें उनके साथ ऑस्कर विजेता कोरियाई फिल्म निर्माता बॉन्ग जून हो, लीबैग बनाने वाले तथा स्टार फोएब, वॉलर ब्रिज तथा हॉलिवुड स्टार माइकल बी जॉर्डन तथा पॉप म्यूज़िक सुपरस्टार सेलेना गोमेज़, जे बॉल्विन तथा जेनिफर हड्सन भी इस सूची में रखे गए थे।

आयुष्मान ने कहा, 'मैं वास्तव में विनीत भाव से इस सम्मान को स्वीकार करता हूं। एक कलाकार के रूप में मैंने सिनेमा के माध्यम से समाज में सदा एक सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान देने का प्रयास किया है। इस क्षण मुझे विश्वास दिला रहा है कि मेरा ऐसा करना और मेरी अब तक की यात्रा सही दिशा में थी।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि सिनेमा समाज और लोगों में सही विमर्श को प्रारंभ करने की शक्ति रखता है। आशा है कि कंटेंट के प्रति अपने चयन के माध्यम से मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति योगदान देने में समर्थ हुआ हूं।'

इफ्फी के 51वें संस्करण का आयोजन अब अगले साल 16 से 24 जनवरी को होगा : जावडेकर

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के 51वे संस्करण का आयोजन इस साल 20 से 28 नवम्बर की जगह अगले साल 16 से 24 जनवरी तक किया जाएगा। इसका आयोजन मिश्रित यानि डिजिटिल और प्रत्यक्ष दोनों तरीके से होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने एक बयान में बृहस्पतिवार को कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से इस विषय पर चर्चा करने के बाद इफ्फी का आयोजन टालने का फैसला किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया।

जावडेकर ने कहा, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिशा-निर्देश और नियमों के अनुरूप गोवा में 16-24 जनवरी 2021 तक संयुक्त रूप से महोत्सव का आयोजन करने का फैसला किया गया है। उन्होंने एक बयान में कहा, डिजिटल और प्रत्यक्ष यानी मिश्रित तरीके से महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्किट में हाल में आयोजित महोत्सवों के अनुरूप कोविड-19 से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाएगा।

इफ्फी के पिछले साल स्वर्ण जयंती समारोह के शुभारंभ में अभिनेता अमिताभ बच्चन और रजनीकांत ने एक साथ शिरकत की थी। फ्रांस की नामी अदाकारा इसाबेल हुपर्ट को लाइटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चर्चित गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने भी पिछले साल शुरूआती समारोह में अपनी प्रस्तुतियों के जरिए प्रशंसकों का मनोरंजन किया था। पिछले साल के समारोह में विभिन्न देशों की करीब 250 फिल्में दिखाई गई थी।

राणा सफवी को मिला यमीन हजारिका पुरस्कार

नई दिल्ली। इतिहासकार राणा सफवी को यमीन हजारिका की स्मृति में स्थापित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यमीन हजारिका पूर्वोत्तर से केंद्रीय पुलिस सेवा में आने वाली पहली महिला थीं। संस्कृति, इतिहास और भारत के स्मारकों पर कई किताबें प्रकाशित कर चुकीं सफवी को भारतीय संस्कृति में उनके समन्वयात्मक योगदान के लिए चुना गया।

असम से आने वाली हजारिका का चयन 1977 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली पुलिस सेवा (दानिप्स) में हुआ था। वह चाणक्यपुरी (दिल्ली) की सहायक पुलिस आयुक्त रहीं और बाद में राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस उपायुक्त (महिलाओं के खिलाफ अपराध) का पद भी संभाला। दिल्ली में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान वह तीन प्रमुख थानों की प्रभारी थीं। उसके बाद वह संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक मिशन पर बोस्निया चली गई थीं।

1999 में 43 वर्ष की उम्र में कैंसर से उनका निधन हो गया था। सम्मान समारोह डिजिटल रूप से हुआ जिसमें हजारिका की बेटी हुमा ने दिल्ली में सफवी को रजत स्मृति चिन्ह दिया। इस मौके पर असम के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत विशिष्ट अतिथि थे। यह पुरस्कार 2015 से हर वर्ष महिला पेशेवरों को उनके योगदान के लिए दिया जाता है।

मानव कौल, आनंद तिवारी कोरोना वायरस से संक्रमित

अर्जुन रामपाल ने स्वयं को पृथक किया

मुंबई। अभिनेता अर्जुन रामपाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि अभिनेता मानव कौल और आनंद तिवारी के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद उनकी आगामी फिल्म नेल पॉलिश की शूटिंग तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। रामपाल ने कहा कि वह अपनी जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और इस समय घर में पृथक-वास कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, मैं घर पर पृथक-वास में हूं। नेल-पालिश के सेट पर कल मानव कौल और आनंद तिवारी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। प्रोडक्शन ने तत्काल शूटिंग रोक दी है और हर व्यक्ति की दोबारा जांच की जा रही है।

अभिनेता ने कहा, मैं घर में पृथक-वास में हूं और जांच के परिणाम का इंतजार कर रहा हूं। हर किसी से दूर रह रहा हूं। लड़कों जल्दी ठीक हो जाओ। बग्स भार्गव कृष्ण द्वारा निर्देशित नेल पालिश जी5 पर रिलीज की जाएगी। मुंबई में संक्रमित लोगों की संख्या बुधवार को 1,90,138 हो गई। शहर में 52 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 8,601 हो गई।

अभिनेता भूपेश पांड्या का फेफड़ों के कैंसर से निधन

भाषा। मुंबई

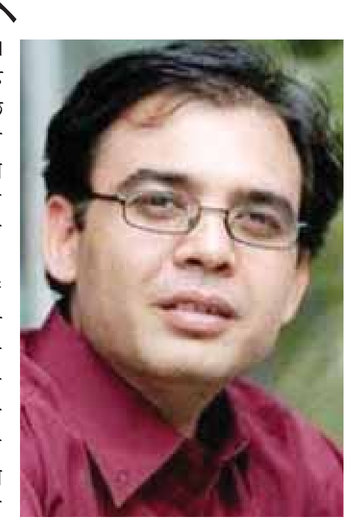

विक्की डोनर और परमाणु: द स्टोरी ऑफ पोकरण जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय के लिए आलोचकों की भी सराहना बटोरने वाले अभिनेता भूपेश पांड्या का निधन हो गया। उनकी आयु 45 के करीब थी। अभिनेता एवं पांड्या के सहयोगी राजेश तैलंग ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) से स्नातक पांड्या फेफड़े के कैंसर से पीड़ित थे, गुजरात के अहमदाबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के लिए उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत थी। एनएसडी में पांड्या के वरिष्ठ रह चुके तैलंग ने बताया कि कुछ साथियों ने अभिनेता की आर्थिक मदद के लिए ऑनलाइन चंदा करके 20 लाख रुपए जुटाए थे लेकिन पांड्या की बुधवार को मौत हो गई। उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, वह एनएसडी में मेरा कनिष्ठ था और हमने एक साथ बहुत काम किया। जब मुझे उसकी सेहत और इलाज में आने वाले खर्च के बारे में पता चला तो मैंने इसे लोगों के साथ साझा करने का सोचा। तैलंग ने कहा, चंदा एकत्र करने की साइट कीटो के जरिए करीब 21 से 22 लाख रुपए इकट्ठा हो गए और कुछ लोगों ने सीधे उनकी पत्नी के खाते में पैसे डाले, लेकिन यह दुखद है कि गुजरात के अपोलो अस्पताल में कल उनका निधन हो गया।

पांड्या ने शुजीत सरकार की 2012 में आई फिल्म विक्की डोनर में चमन का किरदार निभाया था। उन्होंने हज़ारो ख्वाहिशें ऐसी और गांधी टू हिटलर जैसी फिल्मों में भी काम किया था। एनएसडी में उनके सहयोगियों और अभिनेता मनोज वाजपेई, गजराज राव और कास्टिंग डायरेक्टर-फिल्म निर्माता मुकेश छाबड़ा जैसे अन्य सहयोगियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। ड्रामा स्कूल के आधिकारिक अकांउट से ट्वीट किया गया, भूपेश कुमार पांड्या के (पूर्व छात्र, एनएसडी, 2001 बैच) मौत की खबर बेहद दुखद है। एनएसडी परिवार हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। मनोज बाजपेई ने ट्वीट किया, भगवान भूपेश पांड्या की आत्मा को शांति दे। एनएसडी के अनुसार, पांड्या का अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास राजस्थान के बांसवाड़ा में किया जाएगा। उनके परिवार में माता-पिता, पत्नी और दो बच्चे हैं।

आशा नेगी और अंश बागरी साथ होंगे कामेडी शो लव का पंगा में

लोकप्रिय कलाकार आशा नेगी और अंश बागरी जल्द ही हंगामा प्ले के आगामी ओरिजिनल रोमांटिक कॉमेडी शो लव का पंगाष् में एक साथ नजर आएंगे। पवित्र रिश्ता और अभय 2 जैसे हिट टेलीविजन और वेब शो में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध आशा नेगी अपने इस नए शो में नेहा का किरदार निभाती नज़र आएंगी जो कि दिल्ली की एक मॉडर्न लड़की है तथा छुट्टियों का अकेले ही शांतिपूर्ण आनंद उठाने के लिए निकल पड़ी है। वेल्लापंती दिल तो हैप्पी है जी और डेज ऑफ तफरी में प्रमुख भूमिकाएं निभाने वाले अंश बागरी इस कॉमेडी में सुमित बने दिखाई देंगे जो कि एक देसी और बिंदास हरियाणवी छोरा है। मनाली की खूबसूरत जगहों पर फिल्माया गया यह शो प्यार और रोमांस को आधुनिक नज़रिए से देखता है।

शो के बारे में बात करते हुए अंश बागरी ने कहा, लव का पंगा आपको इन दो किरदारों के साथ मनाली की खूबसूरत सैर कराता है। यह ऊंचे दर्ज़े के मनोरंजन वाला हल्का फुल्का शो है जो दर्शकों को अपने किरदारों के साथ यकीनन गहरे जुड़ाव का अहसास कराएगा। आशा के साथ काम करना एक शानदार अनुभव रहा। वह बेहद समर्पित व सहज.स्वाभाविक अभिनेत्री है और मनाली में शूटिंग करते वक्त हमने खूब धमाल मचाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शक भी इस शो का उतना ही आनंद उठाएंगे जितना कि हमने इसकी शूटिंग करने में उठाया है। नितेश सिंह द्वारा निर्देशित और एबज ओरिजिनल द्वारा निर्मित लव का पंगा स्ट्रीम करने के लिए जल्द ही हंगामा प्ले और भागीदार नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।